R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 23 । अंक : 19
01 से 15 जुलाई 2025
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

कट्टर विचारधाराएं, विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं और अत्याधुनिक हथियारों की होड़

विनाश की राह पर मानवता!

साइबर और परमाणु आयुधों से लैस देशों की आपसी टकराहट भविष्य को दे रही चुनौती

रूस-यूक्रेन, इजराइल-ईरान, अफ्रीका-म्यांमार बढ़ा रहे तीसरे विश्व युद्ध की आशंका

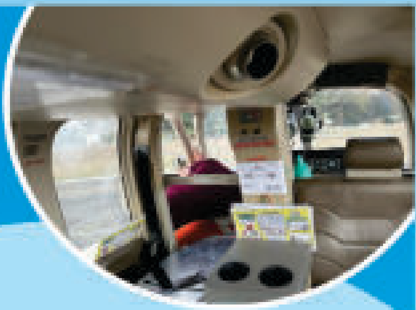

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

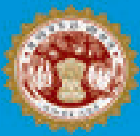

मध्यप्रदेश सरकार की

"एक संवेदनशील पहल"

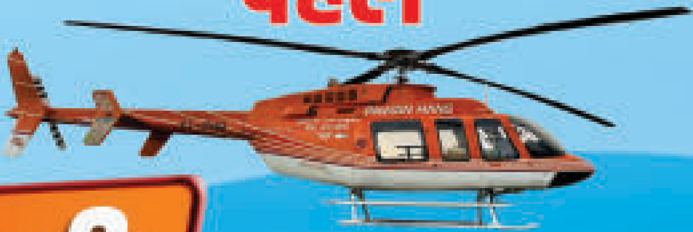

पीएमश्री

एयर एम्बुलेंस सेवा

प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में गंभीर रूप से बीमार, दुर्घटनाग्रस्त लोगों की आपातकाल में त्वरित सहायता के लिए मध्यप्रदेश सरकार की एक परिवर्तनकारी पहल। अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं और उपकरणों से सुसज्जित इस सेवा के माध्यम से मुश्किल समय में त्वरित जीवनरक्षक समाधान मिलने से आमजन को समय रहते मिलेगी उचित उपचार की सुविधा।

स्वस्थ और सुरक्षित मध्यप्रदेश का संकल्प

- ₹ 592 करोड़ की लागत से उज्जैन में प्रदेश की पहली मेडिसिटी एवं मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन
- वर्तमान में प्रदेश में 17 शासकीय एवं 13 निजी चिकित्सा महाविद्यालय संचालित
- 55 जिला चिकित्सालयों में भारतीय जन औषधि केंद्रों और 800 आयुष आरोग्य मंदिर का संचालन प्रारंभ
- 8 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय निर्माणाधीन एवं पीपीपी मोड पर 12 चिकित्सा महाविद्यालय शीघ्र होंगे प्रारंभ
- 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग आयुष्मान भारत योजना से ले रहे लाभ

आपातकालीन सहायता के लिए सम्पर्क करें : 9111777858

मध्यप्रदेश शासन

इस अंक में

कर्मचारीनामा

8 | पदोन्नति का फॉर्मूला तय!

मप्र में लंबे समय से प्रतीक्षित पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित नई व्यवस्था अब मूर्तरूप लेने जा रही है। मप्र लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। अब सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी)...

डायरी

10-11 | किसके खिलाफ...

मप्र के मंत्रालय में किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय से कम दांवपेंच नहीं चला जाता है। यहां भी अक्सर अफसर अपने विरोधी के खिलाफ खेमेबाजी करते रहते हैं। वर्तमान में कुछ वरिष्ठ अधिकारी मिलकर लामबंदी...

शराब

14 | शराब ठेकेदारों पर नकेल

मप्र में शराब ठेकेदारों की मनमानी चरम पर है। शराब ठेकेदार कानून व सरकारी नियमों से बेखौफ एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बेच रहे हैं। इससे सरकार व आम जनता को आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है। ऐसे में लगातार मिल रही शिकायतों को...

स्वास्थ्य

18 | कोविडः फिर पैर पसारती...

महामारी कोविड-19 ने 2020-21 में समूचे विश्व को झकझोर दिया था। मौत और अर्थव्यवस्था के आंकड़े डरावने थे। भारत में दमघोंटू लॉकडाउन, ऑक्सीजन संकट और टीकाकरण की चुनौतियां भयावह थीं। वह दौर सोचकर ही रूह कांप जाती है। बाद में लॉन्ग कोविड भी बहुतों को जिंदगियों से वंचित...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

विकास के साथ विश्व के शक्तिशाली देश विस्तारवाद की होड़ में दूसरे देशों की सीमाओं को अपने में मिलाने में लगे हुए हैं। कट्टर विचारधाराएं, विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं और अत्याधुनिक हथियारों की होड़ के बीच साइबर और परमाणु आयुधों से लैस देशों की आपसी टकराहट भविष्य को चुनौती दे रही है। इस बीच अमेरिका अपने आप को विश्व की नंबर-1 शक्ति बनाने के लिए जिस तरह की पैंतरेबाजी कर रहा है, उससे मानवता विनाश की ओर बढ़ रही है।

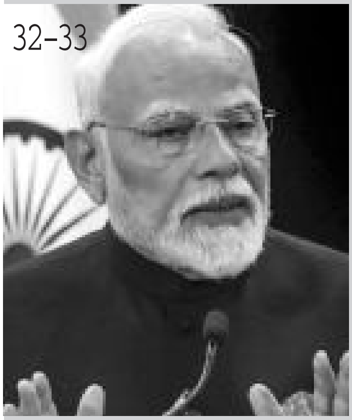

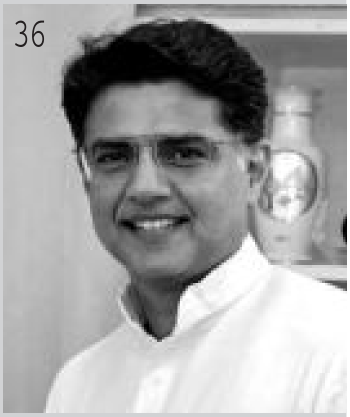

राजनीति

30-31 | राजनीति को नई दिशा...

ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह देश में राजनीति हो रही थी, उसी बीच कुछ राजनेताओं को विदेशों में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भेजा गया था। उन नेताओं ने जिस तरह भारत की बात रखी, उससे देश की राजनीति को नई दिशा मिली है। क्योंकि अधिकतर नेता युवा थे।

महाराष्ट्र

35 | उद्धव-राज होंगे एक!

महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले सियासी समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। शिवसेना यूबीटी और मनसे के साथ आने की चर्चा भी सियासी गलियारों में जमकर चल रही है। गठबंधन को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। ठाकरे बंधुओं के गठबंधन की चर्चा इसलिए हो रही है कि...

बिहार

39 | बिहार में भविष्य दांव पर लगा...

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान के 2025 बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की पुष्टि ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। गत दिनों बिहार के आरा में पहुंचे चिराग पासवान ने कहा...

6-7 अंदर की बात

41 पड़ोस

42 विदेश

44 खेल

45 फिल्म

46 व्यंग्य

पाक्षिक
अक्स

वर्ष-23, अंक-19, पृष्ठ-48
1 से 15 जुलाई, 2025

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

प्रमुख संवाददाता

भावना सक्सेना-भोपाल, जय मतानी-भोपाल,
हर्ष सक्सेना-भोपाल,
दक्ष दवे-इंदौर, संदीप वर्मा-इंदौर,
विपिन कंधारी-इंदौर, गौरव तिवारी-विदिशा,
ज्योत्सना अनूप यादव-गंजबासौदा, राजेश तिवारी-उज्जैन,
टोनी छाबड़ा-धार, आशीष नेमा-नरसिंहपुर,
अनिल सोडानी-नई दिल्ली, हसमुख जैन-मुंबई,
इंद्र कुमार बिन्नानी-पुणे।

प्रदेश संवाददाता

पारस सरावगी (इंदौर)
09329586555
नवीन रघुवंशी (इंदौर)
09827227000 (इंदौर)
धर्मेन्द्र कथूरिया (जबलपुर)
098276 18400
श्यामसिंह सिकरवार (उज्जैन)
094259 85070
सुभाष सोमानी (रतलाम)
089823 27267
मोहित बंसल (विदिशा)
075666 71111

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी, फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

अपनी बात

वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं

शायर साहिर लुधियानवी का एक शेर है...

हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठे
वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं

उपरोक्त पंक्तियों को मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव साकार कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने का संकल्प लिया था। उस संकल्प को साकार करने के लिए मप्र अपने रणनीतिक प्रयासों से औद्योगिक विकास के नए युग की ओर अग्रसर है। निवेशकों को अधिक प्रभावी अवसर देने के लिए निवेश प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाया गया है। उज्जैन में शुरू हुआ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सिलसिला आज भी जारी है। वहीं राजधानी भोपाल में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का भी आयोजन किया गया। प्रदेश में जीआईएस के माध्यम से 30.77 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्राप्त हुआ, जिससे करीब 21 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राज्य सरकार ने उद्योग, निवेश और रोजगार के अवसर विकसित करने के लिए 18 नई नीतियां फरवरी में लागू की हैं। प्रदेश में 340 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र 10 फूड पार्क, 5 एसईजेड, 2 स्पाइस पार्क संचालित हैं। मप्र में पर्याप्त लैंड बैंक उपलब्ध है, नए निवेशकों को उद्योग शुरू करने के लिए सरकार पूरी मदद दे रही है। राज्य में बिजली भी सरप्लस है। लेदर पार्क, फार्मा पार्क, टैक्सटाइल पार्क, आईटी और सर्विस सेक्टर में नए अवसर बने हैं। आईटी सेक्टर में प्रदेश में सैकड़ों ईएसडीएम कंपनियां संचालित हैं, जहां 2 लाख से अधिक आईटी प्रोफेशनल्स कार्यरत हैं। कपड़ा उद्योग में खरगोन, मंदसौर, उज्जैन, बुधनी, पीथमपुर बड़े केंद्र हैं। जल्द ही धार में टैक्सटाइल सेक्टर में पीएम मित्र पार्क तैयार होने वाला है। प्रदेश में खनिज संपदा भरपूर है। पन्ना में हीरा मिल ही रहा है, वहीं सिंगरौली जिले में सोने की खदान मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की नीति है कि जहां कॉन्क्लेव करते हैं, वहां इंडस्ट्री का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी करते हैं। रतलाम में हाल ही में संपन्न राइज कॉन्क्लेव नए उद्यमी तैयार करने का अभिनव प्रयास है। वहीं मप्र की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति, समृद्ध प्राकृतिक संसाधन, विकसित बुनियादी ढांचा और उद्योग-अनुकूल नीतियां इसे निवेश के लिए देश का सबसे आकर्षक डेस्टिनेशन बनाती हैं। शहरी विकास, पर्यटन, माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी और एमएसएमई, ये सभी क्षेत्र अपनी असीमित संभावनाओं और अनुकूल वातावरण से निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। मप्र न केवल देश का पहला डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट है, बल्कि ग्रीन एनर्जी हब, विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र और उभरते हुए टेक्नोलॉजी हब के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। मप्र का शहरी बुनियादी ढांचा तेजी से सुदृढ़ हो रहा है। राज्य की स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और लॉजिस्टिक्स हब इसे एक आदर्श रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश डेस्टिनेशन बना रहे हैं। मप्र को भारत का दिल कहा जाता है और इसके धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौन्दर्य से पूर्ण पर्यटन क्षेत्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। खजुराहो, उज्जैन, सांची, पचमढ़ी, कान्हा और बांधवगढ़ जैसे विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। पर्यटन समिट में हॉस्पिटैलिटी, थीम-बेस्ड डेस्टिनेशन और एडवेंचर टूरिज्म में निवेश को बढ़ावा देने के लिए गहन चर्चा होगी। मप्र खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। यह देश में डायमंड, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, कोयला, मैंगनीज और तांबे का प्रमुख उत्पादक है। पन्ना स्थित एशिया की एकमात्र डायमंड माइंस और विशाल कोयला भंडार राज्य को माइनिंग इंडस्ट्री के लिए एक आदर्श डेस्टिनेशन बनाते हैं। मप्र ग्रीन एनर्जी हब बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। रीवा सोलर प्लांट, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और ग्रीन हाइड्रोजन में हो रहे विकास इसे नवकरणीय ऊर्जा निवेशकों के लिए एक प्रमुख केंद्र बना रहे हैं।

- राजेन्द्र आगाल

कर्मचारियों को मिलेगी राहत

मप्र में पदोन्नति का मामला पिछले 9 सालों से उलझा हुआ है। इन 9 सालों के दौरान हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही रिटायर्ड हो गए और बड़ी संख्या में कर्मचारी पदोन्नति का रास्ता देख रहे हैं, लेकिन अब इसका रास्ता खुलने जा रहा है। इससे प्रदेश के कई कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

● **दिनेश यादव,** इंदौर (म.प्र.)

दोषियों को कठोर सजा हो

मप्र के कई विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है। पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाले में फर्जी अभ्यर्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सॉल्वर के जरिए परीक्षा देकर आरक्षक बनने वाले अब तक 33 उम्मीदवारों का खुलासा हो चुका है। सरकार को इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

● **आनंदी शिवहरे,** ग्वालियर (म.प्र.)

मजबूत हो कांग्रेस

मप्र में कांग्रेस की जमीनी हालत ठीक नहीं है। प्रदेश में चार दशक तक सत्ता में रहने वाली यह पार्टी पिछले 20 साल से सत्ता से बाहर है। कांग्रेस को अच्छे नेतृत्व के साथ ही प्रदेश में मजबूती के साथ खड़े होने की जरूरत है। जिससे वह आने वाले चुनावों में भाजपा को टक्कर दे सके।

● **राजेंद्र कुमार,** बैतूल (म.प्र.)

स्त्री हो या पुरुष, कानून सबके लिए समान हो...

देशभर में इन दिनों इंदौर की सोनम रघुवंशी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसने हनीमून पर अपने ही पति की हत्या करवा दी। इससे न केवल समाज पर बुरा असर पड़ रहा है, बल्कि पुरुषों में भी खौफ का माहौल दिखाई दे रहा है। वहीं परिवार भी अब देख-परखकर ही शादी करने की बात कह रहे हैं। एक तरफ महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि वे बहुत सशक्त हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही कोई स्त्री अपराध करती है, उसके बचाव में कहा जाने लगता है कि वह तो ऐसा कर ही नहीं सकती। अपराध को अपराध की तरह देखना चाहिए। स्त्री-पुरुष नहीं करना चाहिए। इसीलिए लंबे अर्से से मांग हो रही है कि स्त्रियों संबंधी कानूनों को लैंगिक भेद से मुक्त किया जाए। स्त्री या पुरुष, जो भी अपराधी हो, उसे सजा मिले।

● **सुमित कुशवाह,** रायसेन (म.प्र.)

रेप और ब्लैकमेलिंग की घटनाओं पर लगे अंकुश

हाल के दिनों में हिंदू युवतियों और महिलाओं के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग के संगठित मामले सामने आ रहे हैं। मप्र में भी कई जगहों पर इस प्रकार की वारदातें सामने आ रही हैं। सभी मामलों में आरोपियों के मुस्लिम और पीड़िताओं के हिंदू होने के कारण इन घटनाओं को कथित तौर पर लव जिहाद गैंग का नाम दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश की सियासत गरमा गई है। शासन-प्रशासन को इन घटनाओं पर सख्ती के साथ कार्यवाही करना चाहिए, जिससे इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।

● **निशा मेहतो,** इटारसी (म.प्र.)

झुग्गीमुक्त होगी राजधानी

पिछले साल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर राजधानी को झुग्गी मुक्त बनाने की कार्ययोजना पर काम शुरू हुआ। इसी के तहत राजधानी भोपाल को झुग्गी मुक्त बनाने की कार्ययोजना पर काम चल रहा है। जिला प्रशासन अब तक कागजी कार्रवाई तो पूरी कर चुका है, लेकिन शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने अथवा झुग्गियों के विस्थापन की शुरुआत अभी नहीं हो सकी है। जल्द ही शहर को झुग्गीमुक्त बनाया जाएगा। मप्र सरकार का यह कदम सराहनीय है।

● **अभिषेक पुरोहित,** भोपाल (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

बीरेन के बिना भाजपा का गुजारा नहीं

भारतीय जनता पार्टी को दो साल लग गए थे एन बीरेन सिंह को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से हटाने में और अब साढ़े चार महीने हो गए उनके हटे हुए तब भी भाजपा वहां सरकार नहीं बना पा रही है। सोचें, मणिपुर में बीरेन सिंह का क्या मतलब है? पहले उनको हटाने के लिए भाजपा के सर्वशक्तिशाली नेतृत्व को राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा यानी सीधे उनके हाथ से किसी दूसरे नेता के हाथ में सत्ता ट्रांसफर नहीं किया जा सके। हालांकि तब विधानसभा निलंबित रखी गई ताकि नई सरकार बनाई जा सके। भाजपा ने राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले केंद्रीय गृह सचिव रहे अजय कुमार भल्ला को राज्यपाल बनाकर मणिपुर भेजा ताकि प्रशासन और राजनीति दोनों संभले। राष्ट्रपति शासन लगने के तुरंत बाद राज्य में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि नई सरकार बनाने का हर प्रयास एन बीरेन सिंह रोक दे रहे हैं। बहुसंख्यक मैती समुदाय में उनकी गजब लोकप्रियता है और भाजपा उनकी अनदेखी करके नया मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है। तभी कई बार विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की और दिल्ली आकर भाजपा आलाकमान से मुलाकात की लेकिन सरकार नहीं बनी। राज्य के प्रभारी संबित पात्रा ने कई बार बैठक की लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली।

कार्ति ने एक नई पार्टी की जरूरत बताई

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे और तमिलनाडु की शिवगंगा सीट के सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा है कि देश में एक नई पार्टी की जरूरत है। उन्होंने तमाम पारंपरिक पार्टियों से अलग हटकर एक ऐसी पार्टी की जरूरत बताई है, जो देश के शहरी विकास का ध्यान रखने वाली पार्टी है। यानी उसका सारा फोकस शहरों के बुनियादी ढांचे का सुधार करने पर हो और तेजी से हो रहे शहरीकरण की जरूरतों को पूरा करने पर हो। वे चाहते हैं कि यह पार्टी तमाम किस्म के भावनात्मक मुद्दों से अलग रहे। कार्ति चिदंबरम ने इस नई पार्टी का आइडिया सुझाते हुए कहा है कि यह पार्टी जाति, धर्म, भाषा जैसे मुद्दों पर बात नहीं करेगी या उस पर ध्यान नहीं देगी। इसकी बजाय पार्टी शहरी मुद्दों, लोगों के आरामदेह जीवन, बुनियादी ढांचे के विकास, नागरिक सेवाओं आदि पर ध्यान दे। उन्होंने इसके लिए नगर नाम सुझाया है। एनएजीएआर का मतलब उन्होंने बताया है नेशनल अलायंस फॉर गवर्नेंस एंड रिन्यूअल। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ध्यान रहे उनके पिता पी चिदंबरम ने भी पिछले दिनों विपक्षी गठबंधन इंडिया के अस्तित्व को लेकर बयान दिया था, तब भी कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी।

मानिक साहा बनाम बिप्लब देब

त्रिपुरा में भाजपा के अध्यक्ष पद का चुनाव 29 जून को हो जाना था। भाजपा के चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण ने इसके लिए टाइमलाइन जारी कर दी थी। यह तय था कि रविवार, 29 जून को भाजपा के नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन एक दिन पहले 28 जून को पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष की ओर से नया निर्देश जारी किया गया और चुनाव टाल दिया गया है। सोचें, कितने समय से प्रदेश अध्यक्ष का फैसला लंबित है। दो दिन पहले ही भाजपा के चुनाव अधिकारी ने दूसरे राज्यों में चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की और एक हफ्ते में कम से कम पांच राज्यों में अध्यक्ष के चुनाव का फैसला किया ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सके। इसके बावजूद त्रिपुरा में प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व की खींचतान में अध्यक्ष का नाम टल गया। ध्यान रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री मानिक साहा हैं, जो कुछ साल पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब हैं, जो प्रदेश की राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं ताकि फिर से मुख्यमंत्री बन सकें। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मानिक साहा अपनी सरकार के मंत्री और अपने करीबी नेता टिंकू रॉय को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। उनकी दूसरी पसंद प्रदेश के भाजपा प्रवक्ता नबेंदु भट्टाचार्य हैं।

अगली बारी बंगाल की

बिहार के बाद मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की बारी पश्चिम बंगाल की होगी। तभी पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस बहुत बेचैन है। ममता बनर्जी ने कोलकाता में इसे लेकर लगातार दो दिन बयान दिए हैं तो उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन और सागरिका घोष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में शुरू हुए मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान पर सवाल उठाया। दोनों ने इसे अलोकतांत्रिक बताया और कहा कि इतने कम समय में चुनाव आयोग कैसे इस काम को पूरा करेगा। तृणमूल कांग्रेस ने इस पुनरीक्षण अभियान के जरिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी लागू होने की आशंका भी जताई है। उसकी आशंका काफी हद तक सही दिख रही है क्योंकि बिहार में पुनरीक्षण कर रहे चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि जो मतदाता जन्म प्रमाणपत्र नहीं दे पाएंगे, उनका नाम तो मतदाता सूची से कटेगा ही लेकिन साथ ही उसकी सूचना आगे सरकार को दी जाएगी, ताकि उनकी नागरिकता की जांच हो सके।

चुनाव आयोग से लड़ाई

बिहार में विपक्षी गठबंधन इंडिया के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। उसको भाजपा और जदयू गठबंधन से चुनाव लड़ना है और प्रशांत किशोर ने सत्ता विरोधी वोट पर अलग दावेदारी की हुई है, जिससे विपक्ष परेशान है। इस बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। आयोग ने मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण शुरू कर दिया है। 22 साल के बाद मतदाता सूची का ऐसा पुनरीक्षण हो रहा है, जिसमें बिहार के करीब आठ करोड़ मतदाताओं को नए सिरे से मतदाता बनना है। यानी पहले की मतदाता सूची रद्द हो गई है और हर मतदाता को नए सिरे से फॉर्म भरना है, अपनी सारी जानकारी देनी है, जन्म प्रमाण पत्र देना है और ताजा फोटो लगानी है। इस काम के लिए 25 दिन का समय दिया गया है। हालांकि विपक्ष और स्वतंत्र पत्रकारों व राजनीति विश्लेषकों की ओर से इस पर सवाल उठाया गया तो चुनाव आयोग ने एक आंशिक राहत दी है।

एक की दमदारी, सब पर भारी

प्रदेश में इस बार 16 डिप्टी कलेक्टरों को आईएएस बनाने के लिए डीपीसी होनी थी। इसके लिए 48 डिप्टी कलेक्टरों की सूची तैयार की गई थी, ताकि उसे यूपीएससी को भेजा जा सके, जिससे उनका प्रमोशन अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में हो सके। सबको उम्मीद थी कि प्रदेश को जल्द ही 16 आईएएस अधिकारी मिल जाएंगे। लेकिन सूची बीच में ही अटक गई। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि एक डिप्टी कलेक्टर के कारण अन्य अफसरों की किस्मत पर फिलहाल पानी फिर गया है। सूत्रों का कहना है कि आईएएस के लिए होने वाली डीपीसी में शामिल करने के लिए जिन डिप्टी कलेक्टरों को चयनित किया गया था, उनमें से एक ऐसा था जिसकी फाइल सीआर खराब होने के कारण रोक दी गई थी। लेकिन उक्त डिप्टी कलेक्टर इतना पावरफुल निकला कि उसके कारण अन्य अफसरों की फाइल भी रुक गई। सूत्र बताते हैं कि डीपीसी के लिए तैयार सूची पर मुख्यमंत्री ने साइन कर दिया था, ताकि सूची यूपीएससी भेजी जा सके। लेकिन ऐन वक्त पर एक पूर्व मुख्यमंत्री ने मामले में टांग अड़ा दी। बताया जाता है कि जिस डिप्टी कलेक्टर की फाइल रोकी गई थी, उसी की सिफारिश लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कदम उठाया। सूत्रों का कहना है कि उक्त डिप्टी कलेक्टर की दमदारी ऐसी रही कि सीएम की साइन के बाद भी डीपीसी की फाइल रोक दी गई और अफसरों का प्रमोशन नहीं हो पाया।

कोटवार की ड्रेस कलेक्टर से लो...

पारदर्शिता के कारण कई बार अधिकारी तरह-तरह के प्रयोग करते हैं, जो उन पर ही भारी पड़ जाते हैं। ताजा मामला कोटवारों की ड्रेस का है, जिसको लेकर तरह-तरह की बातें की जा रही हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में कार्यरत 25 हजार कोटवारों की ड्रेस के लिए नया प्रावधान किया गया था कि उनको अब ड्रेस कलेक्ट्रेट से ही मिलेगी। करीब 6 महीने से प्रमुख सचिव (राजस्व) के फरमान से यह व्यवस्था लागू की गई है। बताया जाता है कि जब इस व्यवस्था की जानकारी प्रशासनिक मुखिया को मिली तो उन्होंने कोटवार संघ के अध्यक्ष को बुलाया और उनसे इस बारे में जानकारी ली तो वे चौंक गए। क्योंकि प्रशासनिक मुखिया जब अपर मुख्य सचिव (वित्त) हुआ करते थे, तब उन्होंने व्यवस्था की थी कि कोटवारों को ड्रेस के लिए 6 हजार रुपए उनके खाते में दिए जाएंगे। तबसे ये व्यवस्था लागू थी, लेकिन करीब 6 महीने पहले कोटवारों की ड्रेस के लिए टेंडर निकाले गए। कहा गया कि कोटवार खाते में रकम जाने के बाद नई ड्रेस न खरीदकर पुरानी ड्रेस ही पहनते थे। ऐसे में अब उन्हें हर हाल में नई ड्रेस मिलेगी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस व्यवस्था को लागू करने में भले ही पारदर्शिता का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसमें बड़ा घालमेल भी हो सकता है। सूत्र बताते हैं कि इन सारे तथ्यों को देखते हुए प्रशासनिक मुखिया ने पूरे मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

हाथी के दांत दिखाने के...

उपरोक्त कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ऐसा ही कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में अक्सर दिखाई देता है। एक मामला इस समय जो चर्चा में है, वह है शिक्षा विभाग में। बच्चों को शिक्षित करने के साथ ही नैतिकता, शिष्टाचार, आचार, व्यवहार आदि सिखाने वाले इस विभाग में कहीं भी सुशासन नजर नहीं आ रहा है। आलम यह है कि विभागीय मंत्री नैतिकता और ईमानदारी का चोला ओढ़कर हमेशा सुशासन की बात करते हैं, लेकिन विभाग के अंदर स्थिति इसके विपरीत है। सूत्रों का कहना है कि विभाग में घपला-घोटाला करने वाले अधिकारियों से मंत्रीजी की खूब छन रही है। ऊपरी तौर पर मंत्रीजी भले ही शांत और कड़क मिजाज में नजर आते हैं, लेकिन अधिकारियों के साथ मिलकर वह सारे काम कर रहे हैं, जिसकी सुशासन में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसका उदाहरण विगत दिनों तबादलों में देखने को मिला। मंत्री ने व्यवस्था दी कि विभाग में सारे तबादले ऑनलाइन किए जाएंगे। इसके लिए शिक्षकों और अधिकारियों से ऑनलाइन आवेदन भी मंगाए गए, लेकिन अधिकांश तबादले ऑफलाइन कर दिए गए। इससे विभाग की खूब किरकिरी भी हो रही है। लेकिन मंत्री ने अधिकारियों से इस बारे में जवाब-तलब भी नहीं किया कि आखिर ऑनलाइन व्यवस्था होने के बावजूद ऑफलाइन तबादले क्यों किए गए। मंत्री ने अफसरों की करनी को जस का तस स्वीकार कर लिया। इससे इसमें बड़े घालमेल की संभावना जताई जा रही है।

अफसर नहीं सुन रहे बात

मप्र में अघोषित तौर पर लगभग हर मंत्री अपने विभाग के अफसरों की मनमानी से परेशान है। आलम यह है कि अफसर मंत्री के संज्ञान में लाए बिना ही काम कर देते हैं। जब मंत्री को पता चलता है तो वे बगले झांकने लगते हैं। ऐसे ही एक मंत्री अपने अफसरों से इस कदर परेशान हैं कि वे घूम-घूमकर गुहार लगा रहे हैं कि उनके विभाग के अधिकारी उनकी तनिक भी नहीं सुन रहे हैं। अपने विभाग के अफसरों की मनमानी से प्रदेश के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्रीजी खुद बीमार हैं। बताया जाता है कि उन्होंने इस संदर्भ में संगठन को भी शिकायत की है। लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। सूत्रों का कहना है कि विगत दिनों मंत्रीजी महामहिम के साथ कार्यक्रम में जा रहे थे, तो उन्हें भी अपनी व्यथा सुना डाली थी, मैं तो अपने अफसरों के सामने मजबूर हूं। इस संदर्भ में आप ही कुछ कर सकते हैं। यहां बता दें कि यह भले ही एक मंत्री की व्यथा है लेकिन अधिकांश मंत्रियों की स्थिति ऐसी ही है। अफसर न मंत्रियों की सुन रहे हैं और न ही विभागीय कामों में मंत्रियों को भाव दे रहे हैं।

यहां से भी विदाई की तैयारी

प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें उनके मातहत तनिक पसंद नहीं करते हैं। वे जहां भी पदस्थ रहे हैं, वहां उनके खिलाफ एक वर्ग हमेशा सक्रिय रहा है। वर्तमान में साहब महामहिम के दरबार में पदस्थ हैं। सूत्रों का कहना है कि वहां से भी साहब की विदाई की तैयारी चल रही है। 1992 बैच के ये आईएएस अधिकारी जहां भी पदस्थ होते हैं, उनका विवादों से नाता जुड़ जाता है। इस कारण वे जहां भी जाते हैं, उनके खिलाफ माहौल बना दिया जाता है। सूत्रों का कहना है कि बड़ी उम्मीद के साथ साहब को वर्तमान जगह पर पदस्थ किया गया है, लेकिन वहां भी उनके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई है। बताया जाता है महामहिम के करीबी एक अधिकारी ने एसीएस स्तर के इन साहब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि उन्हें जल्द ही वहां से रवाना किया जा रहा है। यहां बता दें कि साहब दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर गए पर वहां से भी रातों रात हटा दिए गए। जो अधिकारी इनको हटवाने की कोशिश में लगे हुए हैं वे अपने आगे किसी की नहीं चलने देते हैं।

पदोन्नति का फॉर्मूला तय!

मप्र में लंबे समय से प्रतीक्षित पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित नई व्यवस्था अब मूर्तरूप लेने जा रही है। मप्र लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। अब सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) सभी विभागों में डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) की प्रक्रिया शुरू करेगा। यह पदोन्नति वर्ष 2025 के पदों के लिए होगी। जबकि वर्ष 2026 के लिए सितंबर में डीपीसी प्रस्तावित है। नई डीपीसी प्रक्रिया को सशर्त माना जाएगा, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। जीएडी का कहना है कि कोर्ट में रिवर्ट के मामलों को लेकर भी सरकार अपना पक्ष रखेगी और कैविएट दाखिल करेगी, ताकि भविष्य में कोई निर्णय बिना पक्ष सुने न हो। जीएडी के अधिकारियों के अनुसार सबसे पहले सामान्य प्रशासन विभाग अपनी डीपीसी करेगा। इसके बाद अन्य विभागों के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें निम्न बिंदुओं की जानकारी दी जाएगी। पदों की गणना कैसे हो, नए नियमों के पैरा की व्याख्या, वर्गवार आरक्षण व्यवस्था का अनुपालन और मेरिट और सीनियोरिटी के नियम के बारे में बताया जाएगा।

अनुसूचित जाति (अजा) को 16 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति (अजजा) को 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कैडर स्तर पर लागू होगा। यदि आरक्षित कोटे के पद भरे जा चुके हैं, तब पात्र अजा/अजजा वर्ग के व्यक्ति को अनारक्षित श्रेणी में स्थान मिल सकता है। भविष्य की डीपीसी में उस पद को आरक्षित कोटा में ही गिना जाएगा। प्रत्येक पद के लिए दोगुना+4 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। जैसे 10 पद खाली हैं तो 24 लोग चयन प्रक्रिया में शामिल होंगे। पद भरने की प्राथमिकता में पहले अजजा, फिर अजा और अंत में अनारक्षित वर्ग को लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, पदोन्नति नियमों को अंतिम रूप देने से पहले 27 ड्राफ्ट तैयार किए गए थे। अंततः मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से चर्चा कर कैबिनेट द्वारा स्वीकृत नियम को अधिसूचित किया जाएगा। जीएडी का दावा है कि यह नया नियम सभी वर्गों को समान अवसर सुनिश्चित करता है।

पदोन्नति नियमों में खास बात यह है कि प्रत्येक संवर्ग में पदों का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। प्रमोशन कमेटी में संबंधित विभाग के सचिव अध्यक्ष होंगे और विभागाध्यक्ष सचिव की भूमिका निभाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग का उपसचिव (या उससे ऊपर का अधिकारी) समिति का हिस्सा रहेगा। अर्हकारी सेवा अवधि उस चयन वर्ष की तिथि तक मानी जाएगी। पदोन्नति के लिए उपयुक्तता सेवा अभिलेख और पिछले 5 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों के आधार पर तय होगी। जिन लोक सेवकों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद दंडित किया गया है, वे पदोन्नति के लिए अयोग्य माने जाएंगे।

उधर, मुख्य सचिव अनुराग जैन ने हाईलेवल बैठक कर प्रमोशन की प्रक्रिया को तेज गति से निपटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को प्रमोशन के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया है। इस दौरान सभी विभाग एसीआर तैयार कर लें और विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कर प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी कर लें। ताकि कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए और ज्यादा इंतजार न करना पड़े। बताया जा रहा है कि जुलाई के आखिर तक करीबन 50 हजार कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। बता दें कि पिछले 9 सालों से मप्र के अधिकारी-कर्मचारी पदोन्नति का रास्ता देख रहे थे। इस दौरान हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही रिटायर्ड हो गए। लेकिन अब जुलाई के अंत में कर्मचारियों को मोहन यादव सरकार बड़ी राहत देने जा रही है।

मप्र में पदोन्नति के लिए खाली पदों को एससी (16 प्रतिशत), एसटी (20 प्रतिशत) और अनारक्षित में बांटा जाएगा। क्लास-1 अधिकारी के लिए लिस्ट मेरिट कम सीनियोरिटी के आधार पर, जबकि क्लास-2 और नीचे के पदों के लिए सीनियोरिटी कम मेरिट के आधार पर दावेदारों की सूची बनेगी। पूर्व में प्रमोशन पा चुके कर्मचारियों को रिवर्ट नहीं किया जाएगा, न रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वहीं, पदोन्नति से भरे जाने वाले हर संवर्ग के पद अलग से तय होंगे। डीपीसी में एससी-एसटी वर्ग का एक-एक अधिकारी शामिल होगा। सीआर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति नहीं मिलेगी। पदोन्नति के लिए हर साल सितंबर से लेकर नवंबर के बीच डीपीसी की बैठक की जाएगी।

● **सुनील सिंह**

5 साल के लिए होगा आरक्षण

गौरतलब है कि पदोन्नति नियम-2025 में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग को आरक्षण तो दिया गया है पर यह स्थायी नहीं रहेगा। प्रत्येक संवर्ग में प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता के आधार पर इसका निर्धारण 5 साल के लिए होगा। यदि किसी संवर्ग में प्रतिनिधित्व आरक्षण की तय सीमा से अधिक है तो यह कम भी हो सकता है। इसका निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। पदोन्नति नियम में एससी-एसटी वर्ग के लिए आरक्षित रखे जाने वाले पदों की गणना के साथ ही प्रत्येक संवर्ग में प्रतिनिधित्व प्रशासनिक दक्षता के आधार पर निर्धारित करने का प्रविधान रखा गया है। एससी के लिए 16 और एसटी के लिए 20 प्रतिशत पदोन्नति के पद आरक्षित रखे जाएंगे। पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संवर्ग में आरक्षित वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों के पदों की गणना विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से पहले होगी। इसके लिए संख्या का निर्धारण विभागीय मंत्री, विभागाध्यक्ष और सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव स्तर के अधिकारी की समिति करेगी। इसमें एक सदस्य एससी-एसटी वर्ग से अनिवार्य रूप से होगा। यदि किसी संवर्ग में विशेष परिस्थिति नहीं है तो आरक्षण एससी-एसटी के लिए 36 प्रतिशत रहेगा। जानकारी के अनुसार यदि प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता के आधार पर कोई विभाग किसी संवर्ग में आरक्षण कम करने का निर्णय लेता है तो ऐसा मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के अनुमोदन से ही किया जा सकेगा। एक बार जो आरक्षण निर्धारित हो गया, वो 5 साल तक रहेगा। इसके बाद फिर आंकलन करके इसे परिवर्तित किया जा सकेगा। यह प्रविधान इसलिए किया गया है क्योंकि हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हवाले से कहा था कि आरक्षण के लिए प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता को देखा जाए।

आधे प्रदेश को रोशन करेगी सौर ऊर्जा

मप्र सरप्लस बिजली उत्पादन वाला राज्य है। मतलब यहां जितनी बिजली की खपत होती है, उससे ज्यादा निर्माण होता है। यही कारण है कि दिल्ली मेट्रो सहित कई परियोजनाओं को मप्र से बिजली सप्लाई की जाती है। अब मप्र एक कदम आगे बढ़ते हुए कदम उठाने वाला है। मप्र सौर ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने जा रहा है। राज्य अपनी जरूरत की 50 प्रतिशत बिजली की आपूर्ति सौर ऊर्जा के माध्यम से करेगा। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग ने इसके लिए कार्ययोजना बनाई है। प्रदेश में सोलर की बिजली बढ़ाने के लिए सरकार नई-नई योजनाएं ला रही है। इसके तहत ऊर्जा विकास निगम ने प्रदेश के 6 जिलों में 15000 हेक्टेयर जमीन चिन्हित कर ली है। यहां 7500 मेगावॉट क्षमता के सोलर प्लांट स्थापित किए जाने की तैयारी है। प्रदेश में सोलर एनर्जी क्षमता लगातार बढ़ रही है। साल 2012 में सोलर एनर्जी की क्षमता 438 मेगावॉट थी, जो अब बढ़कर 7339 मेगावॉट हो गई है।

अधिकारियों के अनुसार मप्र में वर्ष 2030 तक बिजली की जरूरत लगभग 40 हजार मेगावॉट होगी। इसमें से आधी यानी 20 हजार मेगावॉट बिजली सौर ऊर्जा के द्वारा बनाई जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में वर्तमान समय में 26 हजार मेगावॉट बिजली की जरूरत होती है, अभी सौर ऊर्जा से सात हजार मेगावॉट बिजली की पूर्ति की जा रही है। जबकि सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 में जब 40 हजार मेगावॉट बिजली की आवश्यकता हो सकती है। तब आधी बिजली की पूर्ति सौर ऊर्जा से हो सकती है। इन सोलर प्लांट से उत्पादित होने वाली बिजली को सरकार खरीदेगी। इसके लिए सरकार सोलर प्लांट लगाने वालों से 25 साल का अनुबंध करेगी। इसकी प्रक्रिया ऊर्जा विकास निगम ने शुरू कर दी। सोलर प्लांट लगाने वालों से पंजीयन कराए जा रहे हैं। हर महीने की 15 तारीख तक सोलर प्लांट के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद एनओसी संबंधित क्षेत्र के सब स्टेशन से लेना होगी।

मप्र सौर ऊर्जा पर अपनी निर्भरता में वृद्धि करने जा रहा है। सरकार का प्लान है कि 2030 तक अपनी आधी बिजली की आपूर्ति सोलर एनर्जी से की जाए। इसके लिए प्रदेश में बंजर, अनुपयोगी कृषि भूमि पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इनके जरिए किसानों को बिजली उत्पादक बनाया जाएगा। यह सोलर प्लांट किसान और निवेशक मिलकर भी लगा सकते हैं। दरअसल, 8 हजार मेगावॉट वाली सौर ऊर्जा की परियोजना मुरैना में स्थापित करने को लेकर मप्र और उप्र के बीच सहमति बन गई है। वहीं भिंड, शिवपुरी, आगर, धार, अशोकनगर और सागर में साढ़े सात हजार मेगावॉट ऊर्जा क्षमता की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। सोलर एनर्जी में 17 फीसदी का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही कुसुम-सी और कुसुम-ए योजना के तहत प्रदेश में नए सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। अकेले कुसुम-सी योजना के तहत प्रदेश में 15 हजार मेगावॉट के सोलर प्लांट लगाए जाने का टारगेट ऊर्जा विकास निगम ने तय किया है। कुसुम-सी योजना के तहत लगने वाले सोलर प्लांट के लिए 1900 सब स्टेशन का चयन किया गया है। सोलर प्लांट लगने से किसानों को दिन के समय कम लागत में अधिक बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। इस योजना में किसानों को ज्यादा सुविधा दी जा रही है। अगर किसान अपनी जमीन पर कुसुम-सी योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करना चाहते हैं, तो बिना किसी शर्त के टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। इस योजना में निवेशकों के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं।

जानकारी के अनुसार प्रदेश में आगामी 5 साल के दौरान कई सोलर प्लांट लगने वाले हैं। इनमें बिरसिंहपुर इंदिरा सागर और गांधी सागर फ्लोटिंग सोलर पार्क 1400 मेगावॉट, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट 240 मेगावॉट, मुरैना सोलर पार्क 500 मेगावॉट, सागर सोलर पार्क 500 मेगावॉट, आगर चरण 2 और 3 के तहत 2000 मेगावॉट, धार सोलर पार्क 3000 मेगावॉट और कुसुम योजना के तहत रूफ टॉप ग्रीन पंचायत 3600 मेगावॉट शामिल हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश की बिजली मांग को पूरा करने के लिए 2034-35 तक 29956 मेगावॉट सौर और 5293 मेगावॉट पवन ऊर्जा की जरूरत होगी। रिपोर्ट में बताया है कि प्रदेश में 5.36 फीसदी की दर से सौर ऊर्जा में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में बिजली की डिमांड 18 हजार मेगावॉट से ऊपर पहुंच चुकी है। यह डिमांड 20 हजार मेगावॉट को पार कर सकती है। अगले कुछ सालों में प्रदेश में बिजली की डिमांड 25 हजार मेगावॉट को पार कर जाएगी। इसको देखते हुए सरकार ग्रीन-एनर्जी हब तैयार कर रही है। वर्तमान में राज्य में 5 बड़ी सौर परियोजनाएं हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 2.75 गीगावाट (2,750 मेगावॉट) है।

● नवीन रघुवंशी

भोपाल में बनेगा सेंटर ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन

मप्र देश का पहला राज्य बनेगा जहां यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले अपना सेंटर ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन स्थापित करेगी। यह सेंटर मैनिट (मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) भोपाल में बनाया जाएगा। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में मप्र नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के साथ एमओयू साइन किया है। सेंटर का उद्देश्य सस्ती सोलर एनर्जी और एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को वैश्विक स्तर पर मजबूत करना है। यूनिवर्सिटी, मप्र के रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट को मॉडल बनाकर काम करेगी। अगले 5 साल तक यूनिवर्सिटी मप्र सरकार को तकनीकी सहयोग, रिसर्च और नॉलेज शेयरिंग में मदद करेगी। इससे सस्ती बिजली उत्पादन, एनर्जी स्टोरेज और ट्रांसमिशन में सुधार होगा। छात्रों को इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। मप्र को रिन्युएबल एनर्जी का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में यह पहला कदम है। एसीएस नवकरणीय ऊर्जा मनु श्रीवास्तव ने कहा कि दुनिया की प्रतिष्ठित कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने मप्र के नवकरणीय ऊर्जा के मॉडल को अपने वैश्विक सेंटर की स्थापना के लिए चुना है। इस समझौते से हमें सोलर एनर्जी और स्टोरेज परियोजनाओं को वैश्विक तकनीक के स्तर पर ले जाने में मदद मिलेगी।

मप्र के मंत्रालय में किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय से कम दांवपेंच नहीं चला जाता है। यहां भी अक्सर अफसर अपने विरोधी के खिलाफ खेमेबाजी करते रहते हैं। वर्तमान में कुछ वरिष्ठ अधिकारी मिलकर लामबंदी कर रहे हैं। दरअसल, मप्र की नौकरशाही के बारे में कहा जाता है कि अफसर क्षेत्रीयता के आधार पर बंटे हुए हैं। हालांकि ऊपरी तौर पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वर्तमान में कुछ वरिष्ठ आईएएस अफसरों की लामबंदी चर्चा का विषय बनी हुई है। खबरची का कहना है कि प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में अक्सर देखने को मिल रहा है कि कई वरिष्ठ अफसर कभी इस कक्ष में तो कभी उस कक्ष में बैठकर घंटों चर्चा करते रहते हैं। सूत्रों का कहना है कि जिस कक्ष में चर्चा होती है, उस कक्ष में किसी दूसरे का प्रवेश पूरी तरह वर्जित कर दिया जाता है। इसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल किसी के खिलाफ लामबंदी कर रहा है। वह कौन है, यह शोध का विषय बन गया है।

किसके खिलाफ हो रही लामबंदी...?

विष्णु की बल्ले-बल्ले

विगत कैबिनेट बैठक में तबादले को लेकर दो मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि अफसरों ने हमसे बिना पूछे ही अपने मन से तबादले कर दिए। यही नहीं हमने जो सूची दी थी, उसे भी दरकिनार कर दिया गया। सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्रियों की प्रेशर पॉलिटिक्स कुछ इस तरह काम कर गई कि राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा की तो बल्ले-बल्ले हो गई, क्योंकि विभाग में सारा काम उनके पुत्र विष्णु और उनके ड्राइवर देखते हैं। बताया जाता है कि कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने उनके विभाग के प्रमुख सचिव को बुलाकर कहा कि विभाग के सारे पेंडिंग काम खत्म करो। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मंत्री के सारे काम धड़ाधड़ हो गए और मंत्रीजी की बल्ले-बल्ले हो गई।

टेंडर में बड़ा घालमेल

बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षा विभाग में अनैतिकता चरम पर है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विभाग में अधिकारी वर्षों से कुंडली मारकर बैठे हैं। अभी हाल ही में सरकार को खुश करने के लिए विभाग की प्रमुख ने सांदीपनि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की ड्रेस के लिए टेंडर निकलवाया है। टेंडर को लेकर तरह-तरह की बातें कहीं जा रही हैं। इसकी पहली वजह यह है कि प्रदेश के अन्य सरकारी स्कूलों के बच्चों की ड्रेस के लिए 600 रुपए नगद दिए जा रहे हैं, जबकि सांदीपनि स्कूलों के लिए टेंडर निकाला गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। या तो सभी स्कूलों के लिए टेंडर निकाले जाते, या फिर नगद राशि दे दी जाती। सूत्रों का कहना है कि सांदीपनि स्कूलों के बच्चों की ड्रेस के लिए निकला टेंडर बड़े घालमेल का संकेत है। टेंडर का खाका बनाया भले ही किसी ने है, लेकिन ये पूरा खेल एचओडी का है। स्कूल शिक्षा विभाग की एक व्यथा यह है कि इस विभाग को मूलतः 3 अधिकारी चला रहे हैं। दरअसल, ये तीनों अधिकारी वर्षों से विभाग में जमे हुए हैं। इनमें दो पुरुष और एक महिला है। दोनों पुरुष डायरेक्टर हैं और वर्षों से जमे हुए हैं। इनमें एक ऐसे हैं, जिनके पास 7 विभागों का प्रभार है। डीपीआई के पद पर कमिश्नर कार्यालय में पदस्थ यह अफसर अतिरिक्त राज्य ओपन बोर्ड, संस्कृत बोर्ड, योग केंद्र वेधशाला उज्जैन, मदरसा बोर्ड के भी प्रबंधक अर्थात् सर्वे सर्वा हैं। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा स्वयं या अन्य के माध्यम से कई एनजीओ भी चलाए जा रहे हैं, इस प्रकार से कई करोड़ों का बजट का संचालन यह एकमात्र व्यक्ति कर रहा है। इसी के फलस्वरूप वह शहर में तथा शहर के बाहर लगभग चार फार्महाउस, बैंगलोर में मॉल, 3 कमर्शियल बिल्डिंग, 4 फ्लैट, लगभग तीन आवासीय भवन एवं अनेकों वाहन का मालिक है। वैसे तो ये जुलाई 2025 में रिटायर होने वाले हैं किंतु ये अनेकों राजनेताओं तथा उच्चाधिकारियों के समर्थन प्राप्त होने के फलस्वरूप दो वर्ष का एक्सटेंशन लेने की तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं एक महिला अधिकारी ऐसी हैं, जो ईमानदारी का चोला ओढ़े हुए हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी सीआर पर स्वयं स्व. एमके सिंह का हस्ताक्षर कर लिया था। महिला की महिमा यह है कि इनको हटाने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री के साथ ही वर्तमान शिक्षा मंत्री भी लिख चुके हैं, लेकिन इनका बाल बांका तक नहीं हो पाया है।

90 डिग्री वाले पुल का दोषी कौन?

भोपाल के ऐशबाग में बने 90 डिग्री आरओबी ने देशभर में प्रदेश की किरकिरी कराई है। मामला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संज्ञान में आया तो उन्होंने इस ब्रिज को दोबारा सुधरने के बाद ही शुभारंभ की बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद इस ब्रिज की डिजाइन पास करने वाले और मॉनीटरिंग करने वाले 2 मुख्य अभियंता समेत 8 इंजीनियरों पर कार्रवाई हो चुकी है। उधर, सूत्रों का कहना है कि 90 डिग्री वाले आरओबी की भेंट अब लोक निर्माण विभाग के अफसर भी चढ़ेंगे। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिरकार 90 डिग्री वाले पुल का असली दोषी कौन है। 18 करोड़ रुपए की लागत से करीब 8 साल के लंबे अर्से के इंतेजार के बाद बनकर तैयार हुए इस ब्रिज की टॉप हाईट पर 90 डिग्री का खतरनाक टर्न दे दिया है, जिसने लोगों को असमंजस में डाल दिया है। लोग इस ब्रिज को भविष्य में भोपाल में होने वाले हादसों का सबसे बड़ा केंद्र बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की टेकनोलॉजिया कहकर मीम बना रहे हैं। वहीं लोगों को उस नाम का इंतजार है जिसकी निगरानी में यह पुल बनाया गया है।

कानून व्यवस्था की समीक्षा में जुटे डीजीपी

मप्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाना प्रदेश की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। डीजीपी पीएचक्यू से निकलकर संभागीय मुख्यालयों पर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने 28 जून को उज्जैन जोन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, डीआईजी और पुलिस अधीक्षकों की महत्वपूर्ण बैठक की। इसके बाद 29 जून को इंदौर जोन के पुलिस अधिकारियों के साथ भी बैठक की। इन बैठकों में अधिकारियों के पिछले कार्यों का विस्तृत रिव्यू किया जा रहा है और उन्हें आगामी कार्ययोजना के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। डीजीपी मकवाना का जोर सीधे संवाद और स्पष्ट निर्देशों पर रहा है, ताकि जमीनी स्तर पर पुलिसिंग में अपेक्षित गति लाई जा सके। बैठकों में विभिन्न अपराधों की रोकथाम, लंबित मामलों के निराकरण और पुलिस बल की दक्षता बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। डीजीपी कैलाश मकवाना का यह प्रदेशव्यापी समीक्षा अभियान लगातार जारी है। इससे पहले उनके द्वारा जबलपुर जोन, बालाघाट जोन, पुलिस आयुक्त भोपाल और भोपाल ग्रामीण जोन की **रिव्यू बैठकें** सफलतापूर्वक संपन्न की जा चुकी हैं। इन बैठकों के माध्यम से डीजीपी स्वयं विभिन्न जिलों और जोन के पुलिसिंग पैटर्न, चुनौतियों और आवश्यकताओं को समझ रहे हैं। डीजीपी कैलाश मकवाना ने इस बात पर जोर दिया है कि उनके सीधे निर्देश देने से पुलिस के कामकाज में अपेक्षित गति आ रही है। उनका मानना है कि मैदानी स्तर पर अधिकारियों के साथ सीधा संवाद और समस्याओं का त्वरित समाधान पुलिस तंत्र को अधिक क्रियाशील बना रहा है। उनका यह दौरा प्रदेशभर में पुलिस व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

कितने दिन में मिलेगा कमिश्नर

सागर संभाग के कमिश्नर हाल ही में रिटायर होने वाले हैं। उनकी जगह किसे कमिश्नर बनाया जाएगा, यह सवाल अभी से उठने लगे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि सागर को कमिश्नर कितने दिन बाद मिलेंगे। क्योंकि जब दतिया के कलेक्टर को हटाया गया था तो 17 दिन बाद नए कलेक्टर की नियुक्ति हो पाई थी।

सूची की महिमा अपरंपार

मप्र में तकरीबन 6 माह से आईएएस अधिकारियों के थोकबंद तबादले के कयास लगाए जा रहे हैं। कभी कहा जा रहा है सूची बनकर तैयार है, तो कभी कहा जा रहा है, अभी कुछ नामों पर मंथन हो रहा है। सूची के इंतजार में कई अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। प्रदेश का ऐसा कोई प्रशासनिक केंद्र नहीं होगा, जहां आईएएस अधिकारियों की तबादले की सूची का इंतजार न किया जा रहा हो। इससे सूची की महिमा अपरंपार हो गई है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री बड़े पैमाने पर फेरबदल के मूड में नहीं हैं, लेकिन जिन पदों पर नियुक्तियां बेहद जरूरी हैं, वहां जल्द बदलाव किए जाएंगे। सचिव स्तर के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के दायित्वों में भी फेरबदल संभव है। लेकिन ये सूची कब आएगी, यह कोई नहीं जानता।

वहीं आईपीएस अफसरों में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसकी वजह यह है कि जहां एक तरफ पुलिस मुख्यालय से लेकर मैदान तक तबादले होने हैं, वहीं कुछ वरिष्ठ आईपीएस अफसरों का प्रमोशन भी होने वाला है। अनिल कुमार स्पेशल डीजी बनेंगे। इसके बाद जीपी सिंह के रिटायरमेंट के बाद अरुण कुमार भी स्पेशल डीजी बनाए जाएंगे।

4 महीने में कई अधिकारी होंगे रिटायर

अगले 4 महीने में बड़ा बदलाव होने वाला है। जिसमें प्रदेश के मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और लोक निर्माण विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी समेत अन्य अधिकारी बदले जाएंगे। इनकी जगह नए अधिकारियों को जिम्मा दिया जाएगा। इनमें अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा समेत एक दर्जन आईएएस शामिल हैं। बता दें कि मुख्य सचिव अनुराग जैन 1989 कैडर के आईएएस हैं। वो अगस्त महीने में रिटायर हो रहे हैं। उनके सेवानिवृत्त के बाद सीएस का पद रिक्त हो जाएगा। ऐसे में नए अफसरों को मुख्य सचिव के वेतनमान में प्रमोट होने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही उज्जैन के संभागायुक्त संजय गुप्ता जुलाई में रिटायर हो रहे हैं। इनके बाद जुलाई में माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव केडी त्रिपाठी और फिर अगस्त में सीएस अनुराग जैन का रिटायरमेंट है। अगले 4 महीने में जिन आईएएस अधिकारियों को रिटायर होना है उनमें अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार कौल जुलाई में, उज्जैन संभागायुक्त संजय गुप्ता जुलाई में, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल केडी त्रिपाठी जुलाई में, मुख्य सचिव अनुराग जैन अगस्त में, एसीएस ग्रह विभाग जेएन कंसोटिया अगस्त में, प्रतिनियुक्ति पर भावना वालिंबे सितंबर में, डिप्टी सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी नियाज अहमद खान अक्टूबर में रिटायर होंगे।

● राजेन्द्र आगाल

दिल्ली स्टाइल से काम कर रहे साहब

केंद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति पर लौटे एक आईएएस अधिकारी यहां भी दिल्ली की तर्ज पर काम कर रहे हैं। जबसे साहब विभाग में पदस्थ हुए हैं, वे अपने तरीके से काम कर रहे हैं, जिससे विभाग के अन्य अधिकारियों को परेशानी हो रही है। दरअसल, साहब संभागीय स्तर पर ज्वाइंट डायरेक्टर होने के बावजूद सीएमओ से वीसी के माध्यम से खुद बात कर रहे हैं। इससे विभाग की कैडर व्यवस्था बिगड़ रही है। सूत्रों का कहना है कि साहब खुद सारा काम करना चाहते हैं। ऐसा करके वे ज्वाइंट डायरेक्टर को नकारा बताने की कोशिश करते हैं। यही नहीं टीएल बैठकें भी करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नई बैठक में पुरानी बैठक के मुद्दे भुला देते हैं।

बैंस और बेलवाल की बढ़ीं मुश्किलें

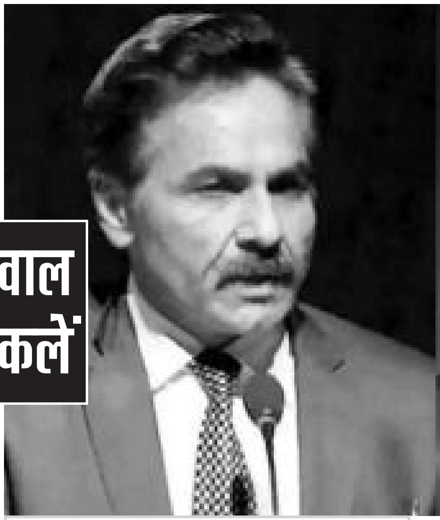

टेक होम राशन घोटाला सामने आने के बाद मप्र के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक पारस सकलेचा की शिकायत पर लोकायुक्त ने प्राथमिकी दर्ज कर 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में इकबाल सिंह बैंस की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट में मप्र में साल 2018-19 से 2021-22 के बीच 500 करोड़ का टेक होम राशन घोटाला सामने आया था। इस मामले में विधायक ने पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और आजीविका मिशन के पूर्व सीईओ ललित मोहन बेलवाल के खिलाफ शिकायत की थी।

पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने अपनी शिकायत सीएजी की रिपोर्ट को आधार बनाकर की थी। इस शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि पोषण आहार मामले में 8 जिलों की जांच में ही सीएजी ने 500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला चार सालों के दौरान पाया है। यदि यह जांच प्रदेश स्तर पर कराई जाए, तो यह घोटाला कई गुना बड़ा निकलकर आएगा। यह घोटाला पूरी रणनीति के तहत किया गया। तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस अपने करीबी अधिकारी एलएम बेलवाल को वन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लाए और उन्हें आजीविका मिशन का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बना दिया। इसके बाद पोषण आहार बनाने वाली सभी 7 फैक्ट्रियों का काम आजीविका मिशन को सौंप दिया गया। जबकि इसके पहले यह काम एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा था। 2018 में कमलनाथ की सरकार के दौरान इस काम को फिर से आजीविका मिशन से वापस ले लिया गया था, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने एक बार फिर बेलवाल को संविदा पर आजीविका मिशन में लाकर सीईओ बना दिया।

पूर्व विधायक की शिकायत के बाद लोकायुक्त ने महिला एवं बाल विकास विभाग, आजीविका मिशन और गड़बडी से जुड़े दूसरे विभागों से जानकारी मांगी और इसमें गंभीरता दिखाई देने पर इसकी प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हालांकि इस मामले को लेकर सीएजी ने कड़ी आपत्ति जताई थी। सीएजी की रिपोर्ट पर राज्य शासन ने अपने जवाब में कहा था कि इस गड़बड़ी को लेकर 73 अधिकारियों के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। 36 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है, 9 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तीन अधिकारी रिटायर्ड हो चुके हैं, इसलिए इन पर कार्रवाई के लिए शासन को लिखा गया है।

पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने 28 अगस्त 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, डॉ. गोविंद सिंह आदि नेताओं के साथ लोकायुक्त में शिकायत दर्ज की थी कि बैंस तथा बेलवाल ने पोषण आहार तथा अन्य योजनाओं में वर्ष 2018-19 से 2021-22 के बीच 8 जिलों में करीब 481.79 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। बाद में ऑडिटर जनरल ने मार्च 2025 में विधानसभा में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भी पोषण आहार घोटाले का उल्लेख किया है। सकलेचा ने कहा कि 4 सालों में 8 जिलों में करीब 500 करोड़ का घोटाला ऑडिटर ने पकड़ा है, सभी जिलों की जांच हुई तो यह कई गुना ज्यादा निकलेगा। सकलेचा ने कहा कि बैंस ने पंचायत विभाग का अपर मुख्य सचिव रहते वर्ष 2017 में आईएफएस अधिकारी ललित मोहन बेलवाल को वन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लाकर आजीविका मिशन का सीईओ बना दिया। फिर पोषण आहार बनाने वाली सातों फैक्ट्री का कार्य एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन से लेकर आजीविका मिशन को दे दिया गया। दिसंबर 2018 में कमलनाथ सरकार बनने पर पोषण आहार का काम फिर से एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन को दे दिया गया। 23 मार्च 2020 को पुनः शिवराज सरकार के आने पर दूसरे दिन ही इकबाल सिंह बैंस को मुख्य सचिव बना दिया गया तथा बैंस ने 2018 में सेवानिवृत्त हो चुके ललित मोहन बेलवाल को जून 2020 में संविदा पर आजीविका मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिया। जिस पर पंचायत विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव और राधेश्याम जुलानिया की आपत्तियों को दरकिनार किया गया। बेलवाल की नियुक्ति के तत्काल बाद पोषण आहार का काम एग्रो इंडस्टरीज कॉरपोरेशन से लेकर आजीविका मिशन को दे दिया गया।

● **जितेंद्र तिवारी**

> *मप्र में अधिकारी-कर्मचारी भ्रष्टाचार को किस तरह पालते-पोसते हैं, इसका उदाहरण महिला एवं बाल विकास विभाग में सामने आया है। जिसको गंभीरता से लेते हुए लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।*

महिला एवं बाल विकास ने की कार्रवाई की खानापूर्ति

पोषण आहार घोटाले में महिला एवं बाल विकास विभाग ने 100 से ज्यादा अधिकारियों पर कार्रवाई की खानापूर्ति की। ऑडिटर जनरल को दी गई रिपोर्ट में महिला एवं बाल विकास ने बताया कि पोषण आहार घोटाले को लेकर 73 अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए। 36 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई। 11 अधिकारियों के विरुद्ध दंडादेश जारी हुए। 9 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई तथा तीन सेवानिवृत अधिकारियों के प्रकरण अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शासन को भेजे गए। सकलेचा ने दावा किया कि मई 2020 से जनवरी 2023 तक महिला एवं बाल विकास के अपर मुख्य सचिव रहे अशोक शाह को भी घोटाला दबाने के लिए ईनाम मिला। 50 वर्ष पुरानी संस्था मुख्य तकनीकी परीक्षक (सीटीई) को खत्म कर नई संस्था एमपी वर्क क्वालिटी कंट्रोल बनाकर उसका डायरेक्टर जनरल 2 अप्रैल 2023 को बना दिया।

सिंधिया समर्थकों की खिलाफत

मप्र के गुना और शिवपुरी नगरपालिकाओं में पिछले 3 वर्षों से सत्तापक्ष के भीतर ही घमासान मचा हुआ है। दोनों ही नगरपालिकाएं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा क्षेत्र में आती हैं और दोनों ही जगह भाजपा की अध्यक्ष हैं। दिलचस्प बात यह है कि गुना में जहां सिंधिया समर्थक अध्यक्ष सविता गुप्ता को भाजपा पार्षदों के ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है, वहीं शिवपुरी में पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया समर्थक अध्यक्ष गायत्री शर्मा पर भाजपा-कांग्रेस दोनों के पार्षद लामबंद हो चुके हैं। विरोध का कारण विकास कार्यों में अनदेखी और पार्षदों की उपेक्षा है। अगस्त में 3 साल पूरे होने पर दोनों जगह अविश्वास प्रस्ताव लाने की सुगबुगाहट है। फिलहाल भाजपा संगठन डैमेज कंट्रोल में जुटा है।

गौरतलब है कि वर्ष 2022 में नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव हुए। गुना नगरपालिका के लिए भाजपा ने सुनीता रविंद्र रघुवंशी को अध्यक्ष पद के लिए मेंडेट दिया। हालांकि, सविता अरविंद गुप्ता ने भी अपना नामांकन दाखिल किया था। कांग्रेस प्रत्याशी रश्मि शर्मा सहित तीन प्रत्याशी मैदान में थे। निर्दलीय सविता गुप्ता को 13, कांग्रेस की रश्मि शर्मा को 13 और भाजपा प्रत्याशी सुनीता शर्मा को महज 9 वोट मिले। पर्ची से फैसला हुआ और सविता अरविंद गुप्ता अध्यक्ष बनीं। सविता अरविंद गुप्ता के अध्यक्ष बनने के बाद से ही नगरपालिका में पार्षदों द्वारा गाहे बगाहे विरोध दर्ज कराया जाता रहा। करीब डेढ़ साल बाद भाजपा ने सविता अरविंद गुप्ता को पार्टी में वापस लिया। हालांकि, पार्टी के ही कुछ पार्षद इस निर्णय के खिलाफ थे। उनको पार्टी में वापस लेने के बाद भी भाजपा के ही कुछ पार्षद बैठकों में विरोध करते रहे। मार्च में हुई बैठक में तो नपा उपाध्यक्ष धरम सोनी, वार्ड 16 के पार्षद दिनेश शर्मा सहित चार अन्य पार्षदों ने नपाध्यक्ष के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया और प्रस्तावों का विरोध किया। पार्षदों का आरोप कि उनके वार्डों में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। साथ ही उनकी मांग थी कि अभी जो 1200 नामांतरण पेंडिंग हैं, पहले उन्हें निपटाया जाए, इसके बाद अध्यक्ष को नामांतरण देने के प्रस्ताव पर चर्चा हो।

39 वार्डों वाली शिवपुरी नगरपालिका में अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध हुआ था। गायत्री शर्मा ने 13 अगस्त 2022 को अध्यक्ष पद की शपथ ली थी। इससे पहले से पूर्व उपाध्यक्ष भानु दुबे की पत्नी दीप्ति दुबे दावेदारी कर रही थीं। लेकिन रामजी व्यास की पत्नी सरोज व्यास अध्यक्ष पद के लिए अड़ गईं। ऐसे में पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को बीच में आना पड़ा। वो बातचीत करने के लिए रामजी व्यास के घर तक गईं। मामला नहीं सुलझा तो अचानक गायत्री शर्मा का नाम आगे बढ़ाया गया और वे निर्विरोध चुन ली गईं। लेकिन यशोधरा राजे के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के बाद शिवपुरी नगरपालिका के राजनीतिक समीकरण बदल गए। यहां भी अध्यक्ष पर विकास कार्य न करने और पार्षदों की अनदेखी के आरोप लगाए जाने लगे। हालात यहां तक पहुंच गए कि पार्षदों ने खुलेआम बगावत कर डाली। 11 जून को भाजपा सहित कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद बगीचा वाले हनुमान मंदिर पर पहुंचे और नपाध्यक्ष को हटाने की कसम खाई। इस दौरान लगभग 18 पार्षद और पार्षद पति के रहने का दावा किया गया। इसके कुछ दिन बाद ही 18 जून को पार्षदों ने पीआईसी की बैठक से पहले भाजपा, कांग्रेस पार्षदों सहित उपाध्यक्ष पति ने विरोध कर दिया। उनका आरोप था कि पीआईसी के रजिस्टर दिखाए जाएं, तो पता चला कि वह अध्यक्ष के घर पर हैं। इस बात को लेकर पार्षदों ने विरोध दर्ज कराते हुए आपत्ति ली। हालांकि, नपाध्यक्ष का कहना था कि रजिस्टर कई जगह घूमते रहते हैं। ऐसे में पीआईसी को दायरा पणजी बनाकर रखनी चाहिए कि कौनसा रजिस्टर कहां गया है।

शिवपुरी नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा पहले पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की समर्थक रही हैं। उन्होंने ही इनका नाम अध्यक्ष के लिए आगे बढ़ाया था। हालांकि, उनके चुनाव नहीं लड़ने के बाद अब वह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की समर्थक हैं। गायत्री का विरोध करने वाले सभी पार्षद मूल भाजपा के हैं। पहले वे यशोधरा राजे सिंधिया के समर्थक माने जाते थे। पहले सिंधिया यहां ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे। चूंकि, शिवपुरी नगरपालिका सिंधिया के लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, ऐसे में अब वह सिंधिया के करीबी भी हैं। ओवरऑल शिवपुरी में 39 पार्षद हैं। इनमें से 22 पार्षद भाजपा के हैं। 10 पार्षद कांग्रेस के और 7 निर्दलीय हैं। जिस समय नगरपालिका के चुनाव हुए, उस समय शिवपुरी में यशोधरा राजे सिंधिया का ज्यादा रोल था। ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे।

● **प्रवीण सक्सेना**

विकास के मुद्दे पर विरोध

दोनों ही नगरपालिकाओं में भाजपा अध्यक्ष को कांग्रेस पार्षदों के विरोध के साथ-साथ भाजपा के पार्षदों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। पार्षद अपने वार्डों में विकास न होने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि विकास कार्य न होने पर जनता उनसे सवाल करती है। गुना के पार्षदों का कहना है कि मानसून आ गया है, नालों की सफाई तक नहीं हुई, ऐसे में बारिश में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। वार्डों में सड़कें खुदी पड़ी हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर पार्टी पदाधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। वहीं शिवपुरी के पार्षदों का कहना है कि महाराज (ज्योतिरादित्य सिंधिया) ने सभी वार्डों में विकास कराने के लिए कहा है, लेकिन उन्हें ही झूठी जानकारी दे दी गई। बताया गया कि करोड़ों के विकास कार्य हुए हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। हम लगभग 15 महीने पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री से मिले। कलेक्टर, विधायक, जिलाध्यक्ष को अवगत करा चुके हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। अब इतना हो चुका है कि वापस लौटने का कोई रास्ता ही नहीं है। या तो इस्तीफा देंगे या अध्यक्ष का बदलाव होगा।

शराब ठेकेदारों पर नकेल

मप्र में शराब ठेकेदारों की मनमानी चरम पर है। शराब ठेकेदार कानून व सरकारी नियमों से बेखौफ एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बेच रहे हैं। इससे सरकार व आम जनता को आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है। ऐसे में लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आबकारी विभाग ने प्रदेशभर में कार्रवाई की है। जिन लाइसेंसी शराब दुकानों पर एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बेची जा रही थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2.31 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है।

गौरतलब है कि राजधानी भोपाल सहित प्रदेशभर में एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेची जा रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि आबकारी आयुक्त ने 1 अप्रैल से हर शराब दुकान पर रेट लिस्ट चस्पा करने का आदेश दिया, कीमत भी तय कर दी, पर इसका पालन नहीं किया जा रहा था। प्रदेशभर में एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचने वाले लाइसेंसी ठेकेदारों के खिलाफ आबकारी विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। आबकारी अमले ने पिछले दिनों राजधानी के बरखेड़ी में शराब दुकान पर कार्रवाई की। यहां महंगी शराब बेचने की शिकायत थी। अधिकारियों ने एक कर्मचारी को 500 का नोट देकर शराब खरीदने भेजा। एक टीम दुकान के आसपास तैनात रही, जिसके पास उस नोट का नंबर और फोटो था। सेल्समैन ने उसे 450 रुपए की शराब 460 रुपए में दी। इस बीच टीम दुकान पर पहुंची और नोट जब्त कर टेस्ट परचेज का पंचनामा बनाया। एक अन्य पंचनामा भी बनाया गया, जिस पर सेल्समैन के हस्ताक्षर थे। विभाग ने दुकान संचालक को नोटिस देकर कार्रवाई की। इसी तरह की कार्रवाई सभी जगह की जा रही है।

जानकारी के अनुसार विभाग बीते 10 दिन में 15 जिलों की 106 लाइसेंसी शराब दुकानों पर 2.31 करोड़ रुपए का जुर्माना कर चुका है। इस तरह की सबसे ज्यादा कार्रवाई जबलपुर जिले में की गई है। दरअसल, 1 अप्रैल से नए ठेके होने के बाद मनमानी कीमतों पर शराब बेचे जाने के मामले सुर्खियों में हैं। मामला मप्र हाईकोर्ट तक भी पहुंच चुका है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और आबकारी विभाग से पूछा है कि प्रदेश में एमआरपी से महंगी शराब क्यों बेची जा रही है? इससे पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी महंगी शराब बेचे जाने के मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए सरकार और आबकारी विभाग से दखल देने की मांग की थी।

गौरतलब है कि महंगी शराब की कीमतों पर नियंत्रण लगाने के लिए आबकारी विभाग ने सभी लाइसेंसी दुकानों पर क्यूआर कोड लगाने के निर्देश दिए हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, इन 10 दिनों में 50 हजार से अधिक लोगों ने क्यूआर कोड से पेमेंट कर शराब खरीदी। ग्राहकों का कहना है कि भोपाल में दो शराब ठेकेदारों की मोनोपॉली चल रही है। इस कारण वे एमआरपी से ज्यादा दरों पर शराब बेच रहे हैं। दुकान वालों से इस बारे में बात की जाती है, तो उनका कहना होता है कि जहां एमआरपी पर बिक रही है, वहां से खरीद लो। अन्य दुकानें दूर होने के कारण महंगी शराब खरीदनी पड़ती है। आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल का कहना है कि एमआरपी से ज्यादा या एमएसपी से कम पर शराब बेचने वाले लाइसेंसी ठेकेदारों पर कार्रवाई की जा रही है। शिकायत मिलने और जांच करने पर 106 लाइसेंसियों पर कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है।

मप्र में एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचने को लेकर आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। पिछले 10 दिनों में आबकारी विभाग ने सबसे अधिक जबलपुर से जुर्माना वसूला है। आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार जबलपुर की 32 शराब दुकानों से 1,10,88,968 रुपए इंदौर की 19 दुकानों से 51,00,000 रुपए, भोपाल की 7 दुकानों से 24,03,169 रुपए, रीवा की 5 दुकानों से 13,70,024 रुपए, सागर की 4 दुकानों से 10,76,017 रुपए, टीकमगढ़ की 7 दुकानों से 5,38,266 रुपए, बुरहानपुर की 3 दुकानों से 4,61,079 रुपए, शिवपुरी की 11 दुकानों से 3,24,205 रुपए, छिंदवाड़ा की 3 दुकानों से 3,00,000 रुपए, पन्ना की 4 दुकानों से 1,97,118 रुपए, छतरपुर की 3 दुकानों से 1,73,286 रुपए, दमोह की 1 दुकानों से 1,33,394 रुपए और नीमच की 3 दुकानों से 59,011 रुपए की वसूली की गई है।

● **धर्मेंद्र कथूरिया**

रेट बताते हैं तो नहीं मिलती शराब

मनीषा मार्केट स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान से बीयर और 180 एमएल मसाला शराब खरीदने वाले शाहपुरा निवासी रोहित यादव ने बताया कि मैंने 130 रुपए में मसाला क्वार्टर खरीदा है। सफेद का क्वार्टर 100 रुपए में मिलता है। यहां से खरीदी बीयर पर रेट मिटा हुआ है, लेकिन 130 रुपए में दी है। रोहित ने कहा कि बोतल पर लिखी रेट दुकानदार को बताते हैं तो वह शराब नहीं देता और धमकाकर और बेइज्जती कर चलता कर देता है। चूंकि क्षेत्र की सभी दुकानों पर इसी दर पर शराब मिलती है। इसलिए जिस कीमत पर देते हैं, खरीद लेते हैं। शहर की 67 दुकानों पर एक ग्रुप द्वारा तैयार सिंडीकेट के एकाधिकार के चलते न केवल भोपाल की सबसे बदनाम शराब कंपनी द्वारा तैयार घटिया गुणवत्ता की देशी मदिरा ही बेची जा रही है, बल्कि बीयर भी सिर्फ हंटर ब्रांड की ही खपाई जा रही है। इसकी गुणवत्ता और स्वाद को लेकर सुराप्रेमी लगातार शिकायतें कर रहे हैं। जबकि किंगफिशर या दूसरी अच्छी गुणवत्ता की शराब उपलब्ध होने से ही मना कर दिया जाता है अथवा कीमत से बहुत अधिक दर पर बेची जा रही है। आबकारी अधिकारियों का कहना है कि कोई दुकान किस कंपनी की शराब या बीयर बेचेगी, यह खुद ठेकेदार तय कर सकता है। इस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। सहायक आबकारी आयुक्त भोपाल वीरेंद्र धाकड़ का कहना है कि शहर में अवैध शराब और नियम विरुद्ध शराब विक्रय पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। महंगी शराब बेचे जाने की सूचना कहीं से भी मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी।

तराई में डकैतों की दहशत

करीब डेढ़ दशक बाद मप्र के पन्ना जिले का तराई इलाका एक बार फिर बदमाशों की आहट से थर्रा उठा है। पप्पू यादव और ठोकिया जैसे खूंखार बदमाशों से 15 साल की आजादी के बाद अब अंतरराज्यीय सीमा में आपराधिक गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। हाल ही में धरमपुर थाना क्षेत्र के पिपराही गांव से 5 से 7 हथियारबंद अपराधियों ने एक बुजुर्ग किसान का अपहरण कर लिया। अपराधी उसे जंगल के रास्तों से होते हुए बृजपुर थाना क्षेत्र में ले गए, लेकिन बुजुर्ग भागने में सफल रहा। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पन्ना पुलिस के साथ सतना, चित्रकूट और बांदा जिले की पुलिस ने जंगलों में संयुक्त गश्त शुरू कर दी है ताकि किसी आपराधिक गिरोह को पनपने न दिया जाए।

दरअसल, डेढ़ दशक की शांति के बाद तराई क्षेत्र में एक बार फिर डकैतों की आहट सुनाई दी है। पिपराही गांव के एक बुजुर्ग किसान को हथियारबंद बदमाशों ने अगवा कर लिया और जंगल के रास्ते अपने साथ ले गए थे। बुजुर्ग ने बताया कि बदमाश उसे रास्ता जानने के लिए ले गए थे और मारपीट नहीं की। जब बदमाश थककर सो गए तो बुजुर्ग भागकर सीधे पुलिस के पास पहुंचा। घटना के बाद पन्ना, सतना, चित्रकूट और बांदा जिले की पुलिस ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। बता दें कि पन्ना जिले के धरमपुर, अजयगढ़ और बृजपुर थाना क्षेत्रों को मप्र शासन ने डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित किया था। लेकिन पंद्रह साल बाद जब तराई क्षेत्र को पप्पू यादव, अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया, मोहन पटेल और गुलबदन जैसे खूंखार अपराधियों से मुक्ति मिली तो अब एक बार फिर अंतरराज्यीय सीमा पर अपराधियों की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं।

धरमपुर थाना क्षेत्र के पिपराही ग्राम पंचायत छतैनी गांव निवासी एक वृद्ध किसान अपने घर के बाहर सो रहा था। तभी पांच से सात हथियारबंद बदमाश वहां पहुंचे और उसे जबरन अगवा कर लिया। चूंकि अज्ञात बदमाशों को जंगल के रास्ते पर जाने के लिए स्थानीय जानकारी की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने इस किसान को पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। जंगल के रास्ते पर चलते हुए वे सेहे पार कर बृजपुर थाना क्षेत्र में पहुंच गए। जहां थकावट के कारण अज्ञात बदमाशों को नींद आ गई और वृद्ध भागने में सफल हो गया। जंगल से भागने के बाद किसान ने खुद ही घटना की जानकारी दी। बुजुर्ग ने बताया कि उसके साथ मारपीट नहीं की गई। बदमाश उसे रास्ता बताने के लिए साथ ले गए थे और सुबह उसके हाथ बांध दिए गए। पूरी रात चलने के बाद बदमाश थक गए और जब उन्हें नींद आ गई तो यह बुजुर्ग भागने में सफल हो गया। वह भागकर सीधे बृजपुर थाने पहुंचा। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पन्ना पुलिस ने सतना, चित्रकूट, बांदा जिले की पुलिस के साथ मिलकर जंगलों में संयुक्त गश्त की है। पन्ना के पुलिस कप्तान साईं कृष्ण थोटा ने बताया कि धरमपुर और बृजपुर थाने की पुलिस टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त और सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। एसपी के मुताबिक, पन्ना जिले की सीमाओं में किसी भी आपराधिक गिरोह को पनपने नहीं दिया जाएगा। पन्ना जिले में लगभग 15 वर्ष पहले डाकुओं का आतंक था। यहां पर डाकुओं के कई गिरोह सक्रिय थे। पन्ना जिला उप्र की सीमा से लगा हुआ जिला है और इसके कुछ थाने उप्र की सीमा से लगते हैं। जिसमें अजयगढ़ थाना, बृजपुर थाना एवं धरमपुर थाना शामिल हैं, जिसके अंतर्गत घनघोर पहाड़ी जंगल आते हैं। डाकुओं के छिपने के लिए ये उपयुक्त जगह हैं। इस कारण डाकू पूर्व में इन्हीं जंगलों में अपना डेरा जमाते थे। और अब 15 साल बाद एक बार फिर से डाकुओं की आहट सामने आई है। बृजपुर एवं धरमपुर थाना अंतर्गत इनकी मूवमेंट को पुलिस तलाश रही है। पुलिस अधीक्षक पन्ना साईं कृष्ण एस थोटा के निर्देश पर पुलिस द्वारा जंगल एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सघन कॉम्बिंग की जा रही है। थाना धरमपुर, थाना बृजपुर एवं पुलिस लाईन की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सुबह 6 बजे से शाम 4.30 बजे तक जंगलों में सघन गश्त की जा रही है। पुलिस ने गांव छतैनी, नवस्ता, सिद्धपुर, पंचमपुर, पिपराही, रमखिरिया, जमुन्हाई, मदारटुंगा, रहुनिया गुजार के लोगों से संदिग्ध गतिविधियों एवं बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति के संबंध में जानकारी ली। गश्त के दौरान घने जंगलों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी हेतु पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है।

वहीं सतना जिले में मप्र व उप्र के बॉर्डर से लगे जंगलों में फिर से डकैतों की आहट है। पुलिस अलर्ट मोड पर है। यहां पर चल रही तेंदूपत्ता तुड़ाई को लेकर होने वाले किसी प्रकार के हमले या परिस्थितियों से निपटने के लिए चित्रकूट क्षेत्र का जंगली इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हुआ, जिसको लेकर पुलिस अब ड्रोन कैमरे से जंगलों की निरागनी ने जुटी हुई है। सतना जिले की धार्मिक नगरी चित्रकूट में ददुआ, ठोकिया, बलखड़िया, बबली कोल, लवलेश पटेल जैसे दुर्दांत डकैतों का क्षेत्र माना जाता रहा है। एक समय यहां डकैतों की गूंज सुनाई देती थी। जंगलों में पूर्व में तेंदूपत्ता तुड़ाई करते समय हमले और अपहरण की घटनाएं होती थीं। ऐसे में एक बार फिर दस्यु प्रभावित क्षेत्र में पुलिस सक्रिय है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सतना पुलिस द्वारा मप्र-उप्र बॉर्डर से लगे 5 थाने चित्रकूट, मझगवां, बरौंधा, धारकुंडी, सिंहपुर में लगातार कांबिंग जारी है। पुलिस की 5 टीमों के साथ ही एसटीएफ भी सर्चिंग में जुटी है। जंगलों में तलाशी अभियान जारी है।

● **बृजेश साहू**

बॉर्डर एरिया में गश्त और जनसंवाद

तराई अंचल के मप्र-उप्र चित्रकूट के साथ पड़ोसी पन्ना जिले के सीमावर्ती इलाकों में नए गिरोह की सुगबुगाहट के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है, जिसके तहत उप्र और पन्ना के बॉर्डर पर स्थित फॉरेस्ट चौकियों में अस्थायी तौर पर जवानों को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा बॉर्डर एरिया में गश्त और जनसंवाद के जरिए ग्रामीणों को सतर्क भी किया जा रहा है। इस कार्य में एसडीओपी चित्रकूट सहित आधा दर्जन से अधिक टीआई के साथ एसटीएफ एवं पुलिस बल जंगल में उतर चुका है। एएसपी विक्रम सिंह कुशवाह के अनुसार ड्रोन के माध्यम से डकैतों के मूवमेंट पर नजर रखने की कोशिश की जा रही है।

मैं फोन पर ऐसी बातें नहीं कर सकता। आप मेरे पास आएंगे तभी बात होगी।
- शिवनारायण सिंह चौहान

सिया-रेरा से बिगड़ी सरकार की साख

‘ मप्र में कुछ ऐसी संस्थाएं यानि निगम, मंडल और प्राधिकरण ऐसे हैं, जहां सरकार की कोशिश रहती है कि अनुभवी अफसरों को रिटायरमेंट के बाद पदस्थ किया जाए, ताकि वे नियमों के तहत सरकार की मंशानुसार काम कर सकें। लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि संस्थाओं की कुर्सी पर बैठने के बाद अधिकारी अपनी मनमर्जी पर उतर आते हैं। ऐसे ही अफसरों के कारण स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी यानि सिया और रेरा विवादों में फंस गए हैं। जिससे सरकार को आर्थिक क्षति तो हो ही रही है, साथ ही बदनामी भी झेलनी पड़ रही है। ’

मप्र में सरकार ने जिन अफसरों पर विश्वास करके उनके अनुभव का लाभ लेने के लिए स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी यानि सिया और रेरा में पदस्थ किया, वे ही अब सरकार की नाक के बाल बन गए हैं। रेरा का विवाद तो लगातार सुर्खियों में है। अब इसी कड़ी में सिया का भी विवाद शामिल हो गया है। दरअसल, यह विवाद सिया के अध्यक्ष शिवनारायण सिंह चौहान की मनमानी से जुड़ा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि जबसे चौहान सिया चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे हैं, तब से वे प्राधिकरण में अपनी चला रहे हैं। जबकि सरकार ने उन्हें अनुभवी अधिकारी मानते हुए रिटायरमेंट के बाद यह जिम्मेदारी दी है। लेकिन सरकार के हितों को दरकिनार करते हुए वे अपने हित में लग गए। इसका परिणाम यह हुआ कि परियोजनाओं की अनुमतियां लटकने लगीं।

परियोजनाओं को अनुमति देने के लिए आयोजित होने वाली बैठकों को चौहान निरस्त करते रहे, इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही थी। यही नहीं इससे सरकार को राजस्व हानि भी हो रही थी। इस सबको देखते हुए 23 मई को 450 परियोजनाओं को ईसी जारी कर दी गई। ये मंजूरी तब दी गई, जब मेंबर सेक्रेटरी आर उमा महेश्वरी छुट्टी पर थीं। इसके बाद उनके स्थान पर प्रभारी बनाए गए श्रीमन शुक्ला ने प्रमुख सचिव नवनीत मोहन कोठारी के अनुमोदन के आधार पर यह कार्रवाई की। इन 450 मामलों में से 200 से ज्यादा खनिज विभाग से जुड़े हैं। इसके बाद सिया के चेयरमैन शिवनारायण सिंह चौहान ने इस निर्णय को गैरकानूनी बताया है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए इस पूरे मामले की शिकायत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से की है। चौहान ने इस संबंध में केंद्र को रिपोर्ट भेजकर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।

जानकारी के अनुसार 22 मई से सिया की नियमित सदस्य सचिव उमा महेश्वरी मेडिकल लीव पर चली गई थीं। इस दौरान एप्को के कार्यकारी निदेशक और जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त श्रीमन शुक्ला को मेंबर सेक्रेटरी का अस्थायी प्रभार दिया गया। 23 मई को, प्रभार मिलने के एक दिन बाद ही शुक्ला ने पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव के अनुमोदन से 450 मामलों को डीम्ड मंजूरी दे दी। उन्होंने इसके लिए ईआईए नोटिफिकेशन 2006 के पैरा-8, कंडिका-3 का हवाला दिया।

14 बैठक के शेड्यूल में एक बैठक ही बुलाई

सूत्रों का कहना है कि सिया के चेयरमैन चौहान की मनमानी इस कदर है कि वे बैठकों में शामिल होने से परहेज करते थे। उन्होंने अपने अब तक के कार्यकाल में जितनी बैठकें की हैं, उससे कई गुना बैठकों को निरस्त किया है। गौरतलब है कि 7 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने सिया चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति की। जनवरी से मार्च तक कोई बैठक नहीं हुई। इसके बाद अप्रैल में सिर्फ दो बैठकें हुईं। मई में 14 बैठकें शेड्यूल की गई थीं, लेकिन सिर्फ एक बैठक ही बुलाई गई। गौरतलब है कि सिया अध्यक्ष की मनमानी और अशोभनीय व्यवहार को लेकर सदस्य सचिव आर उमा महेश्वरी 04.04.2025 को प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग को शिकायत कर चुकी हैं। अध्यक्ष एवं सदस्य सिया द्वारा बैठकों को निरस्त करने व प्रकरणों में निर्णय नहीं लिए जाने के कारण अनावश्यक रूप से विलंब किए जाने की मंशा से निरंतर नई-नई मांगें की जाती हैं और जब इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है या पूरा करने में विलंब होता है तो अध्यक्ष द्वारा सचिवालय के खिलाफ अनावश्यक मनगढंत तरीके से कुछ भी निराधार आरोप लगाए जाते हैं, जबकि इनकी लगभग सभी मांगों को पूरा किया जाता है फिर भी अध्यक्ष द्वारा छोटी-छोटी बात पर अभद्र पूर्वक व्यवहार किया जाता है। अध्यक्ष द्वारा कहा जाता है कि अगर उनके निर्देशों (जो कि अनुचित होते हैं) का पालन नहीं किया जाता है तो मैं तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर दूंगा। यह बात उन्होंने सचिवालय के स्टाफ के समक्ष सभागार में की। इस प्रकार से अध्यक्ष एवं सदस्य के अभद्रता पूर्वक व्यवहार के कारण प्राधिकरण की बैठकें आयोजित किया जाना एवं प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

चेयरमैन चौहान की ओर से केंद्र को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक, 17 मार्च से 15 मई के बीच उन्होंने 10 बार मेंबर सेक्रेटरी को नोटशीट लिखी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव को 22 पत्र भेजे। इन पत्रों में मेंबर सेक्रेटरी की मनमानी और बैठक न बुलाने की शिकायत की थी। बावजूद इसके कोई कार्यवाही नहीं हुई। चौहान का कहना है कि बिना बैठक के ईसी जारी करना नियमों के खिलाफ है। जब राज्य स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो 26 मई को उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय को इस घोटाले की विस्तृत रिपोर्ट भेज दी। पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 के तहत 8 प्रकार के प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय मंजूरी लेना अनिवार्य है। इनमें खनन, सिंचाई, सड़क-हाईवे आदि हैं। 250 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के प्रोजेक्ट में ईसी जारी करने के अधिकार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और 250 हेक्टेयर से कम के प्रोजेक्ट में सिया के पास है। सिया चेयरमैन शिवनारायण चौहान का कहना है कि अथॉरिटी के अलावा किसी और को ईसी जारी करने का अधिकार नहीं है। राज्य और केंद्र दोनों को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है।

दरअसल पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 के तहत 8 प्रकार के प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय मंजूरी लेना अनिवार्य है। इनमें खनन, सिंचाई, सड़क-हाईवे आदि हैं। बता दें कि 250 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के प्रोजेक्ट में ईसी जारी करने के अधिकार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और 250 हेक्टेयर से कम के प्रोजेक्ट में सिया के पास है। ऑफ द रिकार्ड सभी मानते हैं कि खनन, सिंचाई, सड़क-हाईवे आदि प्रोजेक्ट अरबों की लागत वाले होते हैं। इसलिए 25-50 लाख की दान-दक्षिणा के बिना कोई भी अनुमति इन प्रोजेक्ट को मिलती ही नहीं है। सिया चेयरमैन शिवनारायण चौहान का कहना है कि अथॉरिटी के अलावा किसी और को ईसी जारी करने का अधिकार नहीं है। फिर अस्थायी प्रभार संभालने के सिर्फ एक दिन बाद ही श्रीमन शुक्ला को अनुमतियां जारी करने की ऐसी कौन सी जल्दी थी? दरअसल इस मामले में भारत सरकार के ईआईए नोटिफिकेशन 2006 के तहत, हर परियोजना की मंजूरी सिया की सामूहिक बैठक में होनी चाहिए थी। लेकिन जानबूझकर बैठकें ही नहीं बुलाई गई, जिससे फाइलें लंबित रहीं। फाइलें लंबित रखने के पीछे 45 दिनों का नियम था। दरअसल नियम के मुताबिक, अगर 45 दिनों में किसी फाइल पर फैसला नहीं होता, तो ईसी (पर्यावरण मंजूरी) अपने आप मान ली जाती है। इसी मजबूरी के कारण सचिव स्तर से सैकड़ों मंजूरियां जारी कर दी गई। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, मुख्य सचिव ने सिया चेयरमैन शिवनारायण सिंह चौहान से सभी अनुमतियों को रेगुलराइज करने के लिए मंजूरी देने को कहा था, लेकिन चौहान ने सिया के मेंबर सेक्रेटरी पद से आर उमा महेश्वरी को हटाने और नियमित रूप से बैठकें कराने की मांग रखी थी। चौहान हर मामले की सुनवाई कानूनी प्रावधानों के हिसाब से करने के बाद ही ईसी जारी करने पर अड़े हैं। वहीं, शासन के अधिकारियों का तर्क है कि 23-24 मई को जारी ईसी निरस्त की जाती है तो खनन का काम अटकने से राजस्व का नुकसान होगा।

गौरतलब है कि 7 मई 2025 को सिया अध्यक्ष चौहान की अनियमितता की एक जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजी गई, जिसमें बताया गया कि बैठक संख्या 884 में चर्चा के लिए जो 5 मिनिट्स रखे गए थे। अध्यक्ष ने उनके संदर्भ में जो दिशा-निर्देश जारी किए, उसमें विरोधाभास है।

जानबूझकर प्रोजेक्ट लटकाए

वहीं मप्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के चेयरमैन अजीत प्रकाश श्रीवास्तव (एपी श्रीवास्तव) का अब तक का पूरा कार्यकाल विवादों में रहा है। सरकार ने उन्हें जबसे रेरा में पदस्थ किया है, तबसे उन पर कई आरोप लग चुके हैं। श्रीवास्तव पर रेरा में नियुक्तियों में गड़बड़ी करने के साथ ही आकृति टाउनशिप के बिल्डर के खिलाफ चल रही जांच के दौरान उससे ही आवासीय भूखंड खरीदने का आरोप है। मप्र पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने उनके खिलाफ प्राथमिक जांच दर्ज की है। बताया जा रहा है कि शिकायतों की जांच चल रही है।

प्रदेश की रियल एस्टेट पर अंकुश रखने और तेजी से बढ़ते अवैध निर्माण और कॉलोनियों पर नजर बनाए रखने आकार दिए गए रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) में मनमानियों और गलत को सही करार देने के हालात बने हुए हैं। नियमों के विपरीत होने वाले कामों को रोकने, उन्हें दुरुस्त करवाने या गलत करने वाले को सजा देने की बजाय नियम तोड़ने वालों को बचाने में रेरा के अधिकारी-कर्मचारी जुटे हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि रेरा में आने वाली अधिकांश शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। उसका कारण यह है कि कार्यालय में मौजूद अधिकारी-कर्मचारी बिल्डर, कंस्ट्रक्शन कंपनी आदि से सीधे जुड़े हुए हैं। इसके चलते इन लोगों के खिलाफ आने वाली शिकायतों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें समझाइश, लालच, दबाव के हालात बनाने लगते हैं। गौरतलब है कि रेरा का मतलब है रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण जो रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अनुसार अस्तित्व में आया, जिसका उद्देश्य घर खरीदारों की सुरक्षा करना और रियल एस्टेट निवेश को बढ़ावा देना है।

● **अरविंद नारद**

विवादों में घिरे रेरा चेयरमैन

रेरा चेयरमैन एपी श्रीवास्तव विवादों में घिर गए हैं। शासन के पास उनके खिलाफ 4 शिकायतें पहुंची हैं। इनमें नियम विरूद्ध काम करने, प्रोजेक्ट लटकाने और खुद जिस प्रोजेक्ट (आकृति गार्डन) में डुप्लेक्स बनाया, उसके प्रमोटर्स के 12 प्रोजेक्ट को रद्द करने का भी मामला शामिल है। आकृति गार्डन मामले में प्रमोटर्स ने ही शिकायत की है कि रेरा चेयरमैन ने परेशान करने की नीयत से प्रोजेक्ट रद्द किए। इससे फर्म को बैंकों से मिलने वाला 80 से 100 करोड़ का लोन अटक गया। जानकारों का कहना है कि जब किसी वैधानिक संस्था के प्रमुख किसी मामले में खुद पार्टी हैं तो वे सुनवाई नहीं करते। इसी से जुड़ा उदाहरण है कि पूर्व सीएस बीपी सिंह ने गैमन प्रोजेक्ट में सुनवाई करने वाली साधिकार समिति से खुद को अलग कर लिया था। उनका फ्लैट इस प्रोजेक्ट में था। आरोप है कि शासकीय अधिकारियों से मिली मंजूरी को बार-बार जांचा जा रहा है। कमियां निकालकर अटकाया जाता है। जो काम 30 दिन में होना चाहिए, उसके लिए 6 से 8 महीने लगाए जाते हैं। रेरा एक्ट बनने के बाद 21 राज्यों के 217 शहरों में 13000 बिल्डर-डेवलपर काम कर रहे हैं। मप्र में परेशानी बढ़ाई जाती है।

कोविडः फिर पैर पसारती दहशत

महामारी कोविड-19 ने 2020-21 में समूचे विश्व को झकझोर दिया था। मौत और अर्थव्यवस्था के आंकड़े डरावने थे। भारत में दमघोंटू लॉकडाउन, ऑक्सीजन संकट और टीकाकरण की चुनौतियां भयावह थीं। वह दौर सोचकर ही रूह कांप जाती है। बाद में लॉन्ग कोविड भी बहुतों को जिंदगियों से वंचित करता गया। इसलिए 2025 में कोविड के नए मामले आने शुरू हुए तो दहशत तारी होनी ही थी। मामलों के बढ़ने की रफ्तार भी कम तेज नहीं है, मगर गनीमत इतनी है कि अब संक्रामक वैरिएंट उतने घातक नहीं बताए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इन्हें बेहद घातक नहीं मान रहा है। लेकिन चिंताजनक हमारे देश में स्वास्थ्य सेवा की जर्जर हालत जरूर है।

फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर जारी आंकड़ों के अनुसार, 1 जून तक देशभर में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 3,783 हो गई है। 22 मई तक यह संख्या मात्र 257 थी। 9 दिनों में ही एक्टिव केस में इतनी बढ़ोतरी से कोरोना संक्रमण के बादल गहरा गए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1400 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 485 और दिल्ली में 436 एक्टिव केस अब तक आ चुके हैं। हालांकि कोरोना वायरस ने इस साल जनवरी के महीने से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। तब से लेकर अब तक कोरोना से 28 मौतों की पुष्टि हो चुकी हैं। संक्रमण किस तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि 28 में से 21 लोग बीते कुछ ही दिन में मरे हैं। चिंताजनक यह रहा कि बेंगलूरू में एक 63 साल के व्यक्ति की मौत हो गई, जिसे दोनों वैक्सीन के साथ बूस्टर डोज भी लगा था। महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज्यादा (7-7) लोगों ने जान गंवाई है। महाराष्ट्र के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वहां 9 हजार से ज्यादा कोविड टेस्ट कराए जा चुके हैं। सरकार की सूचना के मुताबिक 31 मई कोविड के 68 नए मामले सामने आ चुके थे। केवल मुंबई में ही जनवरी 2025 से अब तक कुल 749 केस मिल चुके हैं। जनवरी से अब तक राज्य में 9,592 टेस्ट किए गए हैं।

भारत में 4 नए वैरिएंट मिले हैं। आईसीएमआर के अनुसार, दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन वैरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है, उनमें एलएफ.7, एक्सएफजी, जेएन.1 और एनबी.1.8.1 सीरीज के वैरिएंट हैं। बाकी जगहों से भी नमूने लेकर सीक्वेंसिंग जारी है, ताकि नए वैरिएंट की भी जांच हो सके। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) ने भी इन्हें चिंताजनक नहीं माना है। लेकिन निगरानी में रखे गए वैरिएंट के रूप में कैटेगराइज किया है। चीन सहित एशिया के दूसरे देशों में कोविड के बढ़ते मामलों में यही वैरिएंट दिख रहा है। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि एनबी.1.8.1 के ए435एस, वी445एच, और टी478आइ जैसे स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन दूसरे वैरिएंट की तुलना में तेजी से फैलते हैं और इन पर कोविड के खिलाफ शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता बनी थी उसका भी असर नहीं होता है।

कोरोना वायरस से मौतों की असली संख्या क्या ?

महामारी कोविड-19 फिर सुर्खियों में है, इसलिए क्या तैयारी होनी चाहिए, बेशक इसके लिए जरूरी है कि कमियों को छुपाकर नहीं, उनका समाधान खोजकर आगे बढ़ा जाए। इस मामले में भारत के महापंजीयक (आरजीआई) के हाल में जारी आंकड़े आंख खोलने वाले हैं। 2020 और 2021 में कोविड से संबंधित मौतों का सरकारी आंकड़ा करीब 4,80,000 था। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान 47 लाख का था, जिसे सरकार खारिज करती रही। लेकिन अब आरजीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि 2020 के मुकाबले 2021 में 21 लाख मौतें अधिक हुईं, यानी 26 फीसदी ज्यादा। कुल मौतों की सही संख्या का पता लगाना बेहद जरूरी है, तभी गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है और व्यवस्था की खामियां दुरुस्त की जा सकती हैं। आरजीआई के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि उत्तरी और पश्चिमी राज्यों के आंकड़ों में भारी विसंगतियां देखी गईं। उनमें कोविड से होने वाली मौतों की संख्या बहुत कम बताई गईं। याद कीजिए, गंगा में बहती लाशें और ऑक्सीजन के अभाव में तड़प-तड़प कर मरते लोगों को, जिनकी गिनती भला कौन करता। केरल इस मामले में मिसाल है कि रिपोर्ट की गई कोविड मौतों और अनुमानित अतिरिक्त मौतों के बीच सबसे कम अंतर था।

देखा गया है कि भारत में कोविड का जेएन.1 वैरिएंट आम है। क्योंकि टेस्टिंग के बाद आधे से ज्यादा नमूनों में यही वैरिएंट मिला है। इसके बाद बीए.2 (26 प्रतिशत) और ओमिक्रॉन सबलाइनेज (20 प्रतिशत) वैरिएंट के मामले मिले हैं। जेएन.1 वैरिएंट इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है। यह ओमिक्रॉन के बीए2.86 का ही एक स्ट्रेन है। इसके लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। यह अन्य वैरिएंट की तुलना में तेजी से फैलता है, लेकिन गंभीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में यह सबसे आम वैरिएंट बना हुआ है। अगस्त 2023 में यह पहली बार पाया गया था। दिसंबर 2023 में डब्ल्यूएचओ ने इसे वैरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं, जो प्रतिरोधक क्षमता कमजोर कर देते हैं।

नया वैरिएंट एनबी.1.8.1 पहली बार अप्रैल 2025 में तमिलनाडु में और एलएफ.7 मई 2025 में गुजरात में पाया गया था। दोनों ओमिक्रॉन के सब-वैरिएंट हैं। डब्ल्यूएचओ ने इन्हें वैरिएंट ऑफ कंसर्न (वीओसीएस) के बजाय वैरिएंट अंडर मॉनीटरिंग (वीयूएमएस) की श्रेणी में रखा है। एनबी.1.8.1 में स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन (ए435ए, वी445ए, टी478आई) हैं, जो इसे अधिक संक्रामक बना रहा है। एलएफ.7 में भी ठीक यही समानताएं हैं। अभी तक देखा गया है कि दोनों वैरिएंट किसी गंभीर स्थिति का कारण नहीं बने हैं। सरकार ने अस्पतालों को सतर्क रहने और पूरी तैयारी रखने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों को आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सप्लाई, वैक्सीन, पीपीई किट, और ट्रिपल-लेयर मास्क की पर्याप्त आपूर्ति निश्चित करने का निर्देश दिया है।

● **विकास दुबे**

म प्र में निर्माण कार्य कराने वाले विभागों में काम की प्रतिस्पर्धा में ठेकेदार कम से कम दर पर काम करने को तैयार हैं। इससे काम की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन विभागों के अधिकारियों का कहना है कि इससे सरकार को बचत होने की संभावना है। लेकिन आश्चर्य का विषय यह है कि अफसरों ने किसी काम का आंकलन जितनी राशि का किया है उससे आधी राशि में कोई उस काम को कैसे कर सकता है। यह किसी गड़बड़ी की आशंका को दर्शाता है। गौरतलब है कि लोक निर्माण विभाग, राजधानी परियोजना सहित अन्य निर्माण विभागों में अलग-अलग निर्माण और संधारण कामों को लेकर अधिकारियों की प्राक्कलन दरों के विपरीत ठेकेदार 48-50 और इससे भी कम दरों पर काम ले रहे हैं। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि 50 प्रतिशत या उससे भी कम दरों पर दिए गए इन कामों की गुणवत्ता खराब नहीं होगी, क्योंकि ये काम अनुविभागीय अधिकारी और उपयंत्री की सतत निगरानी में होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकारी कामों की दरों को लेकर अधिकारी गलत प्राक्कलन दरें तय कर रहे हैं अथवा जिम्मेदार अभियंता ही घटिया कामों पर गुणवत्ता की मोहर लगाकर इन्हें पास कर रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि अधिकारी सरकार की आंख में धूल झोंक रहे हैं। दरअसल, किसी भी काम के लिए जब प्राक्कलन रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसमें बड़ा खेल किया जाता है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि निर्माण विभागों में निर्धारित दर से कम या अधिक (ब्लो-अबव) का पूरा खेल अधिकारियों की सांठगांठ से चलता है। कम दरों के बावजूद अधिकारियों को कम से कम 10 प्रतिशत कमीशन के बाद खुद का लाभ निकालना होता है। 50 प्रतिशत कम दर पर ठेकेदार को बड़ा लाभ दिलाने के लिए एसडीओ और कार्यपालन यंत्री स्तर के अधिकारी किसी भी काम का जो प्राक्कलन तैयार करते हैं, उसमें मूल काम के साथ कई ऐसे काम जोड़ दिए जाते हैं, जो कम खर्च वाले होते हैं। कई काम ऐसे भी होते हैं, जिनमें संधारण की आवश्यकता ही नहीं होती। निविदा विज्ञप्ति में भी मूल काम के साथ अन्य काम शेष जोड़ दिया जाता है, जिसके आधार पर बाहरी व्यक्ति कामों की अनुमानित लागत तय नहीं कर सकता। जिस ठेकेदार को काम देना होता है, निविदा शर्तें और काम उसके अनुकूल तय किया जाता है। काम को ठेकेदारों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति में अधिकारी ही सामंजस्य बैठाने का काम भी करते हैं। मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग संजय मस्के का कहना है कि प्रतिस्पर्धा के चलते ठेकेदार बहुत कम दरों पर ठेके ले लेते हैं। कई ठेकेदार लेबर-मशीनरी का खर्च निकालने के लिए घाटे में भी काम करते हैं। विभागीय कामों की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाता। लोक निर्माण विभाग

बचत या गड़बड़ी

घटिया निर्माण कर रहे ठेकेदार

लोक निर्माण विभाग द्वारा हर महीने विशेष टीम द्वारा कराए जा रहे औचक निरीक्षण में ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे घटिया निर्माण पकड़े जा रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नोटिस दिया जा रहा है। औचक निरीक्षण में अभी तक जितने ठेकेदारों के घटिया निर्माण पकड़े हैं, उनमें से न तो किसी को ब्लैकलिस्ट किया है और न ही डीलिस्ट। हाल ही में लोनिवि की टीम ने रेंडम निरीक्षण के दौरान अनूपपुर, बुरहानपुर और इंदौर में अलग-अलग सड़क निर्माण का घटिया निर्माण पाया। जिसके चलते तीन ठेकेदार मेसर्स गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड गुरुग्राम, मेसर्स केजी गुप्ता इन्फ्रास्ट्रक्चर इंदौर और मेसर्स सिद्धि विनायक बिल्डर्स एंड सप्लायर्स शहडोल के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। संबंधित क्षेत्र के मुख्य अभियंता को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा औचक निरीक्षण किया जाता है।

ने एक ही तारीख में कम दर वाली सात निविदाएं जारी कीं। ऐसे में इनमें घटिया निर्माण की आशंका जताई जा रही है। लोक निर्माण विभाग द्वारा एक ही तारीख को जारी इन सात निविदाओं में सभी सफल निविदाकार ठेकेदारों ने कम दरों पर काम लिए हैं। अधिकारियों का दावा है कि एसडीओ और उपयंत्री की निगरानी में इन कामों की गुणवत्ता खराब नहीं होगी।

विंध्याचल भवन में टैंक मरम्मत सहित अन्य कार्य की निविदा 12 अगस्त 2024 को आमंत्रित की गई। कार्य की अनुमानित लागत 64.98 लाख रुपए थी। इस काम को सफलतम निविदाकार ने 16.63 प्रतिशत कम (ब्लो) दर पर लिया है। वल्लभ भवन ब्लॉक 2 एवं 3 में टफंड ग्लास पार्टीशन की निविदा भी 12 अगस्त 2024 को आमंत्रित की गई। कार्य की अनुमानित लागत 36.24 लाख रुपए थी। सफलतम निविदाकार ठेकेदार ने इस काम को 38.99 प्रतिशत कम (ब्लो) दर पर लिया है। राजधानी उपसंभाग क्रमांक-3 में डीके कॉटेज एवं दानापानी तथा दानिश ब्रिज से इंडस अपोलो हॉस्पिटल मार्ग में सरफेस ड्रेन, सेंट्रल वर्ज एवं अन्य कार्य के लिए 12 अगस्त 2024 को आमंत्रित इस निविदा के काम की अनुमानित लागत 30 लाख रुपए थी। ठेकेदार ने इस काम को 48.86 प्रतिशत कम (ब्लो) दर पर लिया। मयूर पार्क, भोपाल में योगा हॉल के एसी सीट को बदलकर प्री-कोटेज गालवनाईज्ड आय प्रोफाईल सीट लगाने सहित अन्य कार्य के लिए 12 अगस्त 2024 को आमंत्रित इस निविदा के कार्य की अनुमानित लागत 28.40 लाख रुपए थी, ठेकेदार ने इस काम को 39.11 प्रतिशत (ब्लो) दर पर लिया। राजधानी उपसंभाग क्रमांक-3 के अंतर्गत मास्टर प्लान मार्गों में विभिन्न सिविल कार्य के काम की निविदा भी 12 अगस्त 2024 को आमंत्रित हुई। काम की अनुमानित लागत 25 लाख रुपए थी। सफल निविदाकार ने इस काम का ठेका 45.40 प्रतिशत (ब्लो) दर पर लिया है। राजधानी उप संभाग क्रमांक-2 अंतर्गत विभिन्न मार्गों में टॉ-वॉल का निर्माण, सिविल स्ट्रेक्चर के मजबूतीकरण का कार्य की निविदा 12 अगस्त 2024 को जारी हुई। काम की अनुमानित लागत 24 लाख रुपए थी। ठेकेदार ने इस काम को 46.86 प्रतिशत (ब्लो) दर पर लिया है। राजधानी उप संभाग क्रमांक-2 के अंतर्गत विभिन्न मार्गों के पेच वर्क एवं अन्य कार्य काम की निविदा भी 12 अगस्त 2024 को जारी हुई। काम की अनुमानित लागत 19.80 लाख रुपए थी। ठेकेदार ने यह काम 37.37 प्रतिशत (ब्लो) दर पर लिया है।

● हर्ष सक्सेना

मप्र में करीब 3 साल बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस ने अभी से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा मिशन 2028 की तैयारी में लगातार प्रदेशभर में कार्यक्रम आयोजित कर कार्यकर्ताओं में जान फूंक रही है, वहीं कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। दोनों पार्टियों का दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वे अच्छा परफार्मेंस करेंगी।

मिशन 2028 की तैयारी

भाजपा ने जिस रणनीति के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर प्रदेश की सभी 29 सीटें जीती थी, अब उसी रणनीति पर 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार मिशन 2028 के तहत भाजपा 172 विधानसभा सीटों (एससी और आदिवासी वर्ग के प्रभाव वाली 127 सीटों के साथ ही सामान्य वर्ग की 45 सीटों) पर विशेष रणनीति बनाकर काम करने जा रही है। इसको लेकर पचमढ़ी में 3 दिनों तक चली बैठक में मंथन भी किया गया। जानकारों का कहना है कि आगामी विधानसभा में प्रदेश की सभी सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया गया है।

गौरतलब है कि भाजपा विधायकों और सांसदों को पचमढ़ी में 3 दिनों तक अलग-अलग विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर में भाजपा ने दलित-आदिवासी वर्ग के प्रभाव वाली सीटों को लेकर विधायकों, सांसदों के ग्रुप बनाकर चर्चा की। इस चर्चा में भाजपा ने विधायकों को यह टारगेट दिया है कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र के उन वर्गों से बातचीत करें जो हार-जीत तय करते हैं। भाजपा ने उन सीटों को इस लिस्ट में रखा है जो सामान्य यानी अनारक्षित हैं। लेकिन, हार-जीत में दलित आदिवासी वर्ग के वोटर महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। इस चर्चा से साफ है कि आगामी समय में इन 45 अनारक्षित विधानसभाओं में से कुछ सीटें आरक्षित हो सकती हैं। इनको लेकर भाजपा गंभीर है और परिसीमन के बाद होने वाले चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसका नजारा पचमढ़ी में भी देखने को मिला। वहां तीन समूहों में चर्चा हुई। इस ग्रुप डिस्कशन में तीन प्रकार से विधानसभा सीटों को विभाजित किया गया था। पहले समूह में एससी वर्ग के प्रभाव वाली 71 विधानसभा सीटों के विधायकों के साथ चर्चा की गई। इस समूह की बैठक को क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने संबोधित किया। दूसरे समूह में आदिवासी वर्ग के प्रभाव वाली 56 सीटों के विधायकों को रखा गया। इस समूह से प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने चर्चा की। तीसरे ग्रुप में अन्य 74 विधानसभा सीटों के विधायकों, सांसदों के साथ मंत्री राकेश सिंह ने चर्चा की।

दरअसल प्रदेश में आदिवासी और एससी वर्ग के प्रभाव वाली सीटें सत्ता का रास्ता तय करती हैं। भाजपा विधायकों और सांसदों को पचमढ़ी में 3 दिन तक अलग-अलग विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर में विधानसभा सीटों पर फोकस किया गया था। इसके लिए अलग-अलग ग्रुप बनाकर विधायकों से चर्चा हुई है। मप्र में आदिवासी सीटें, जिस राजनीतिक दल के हिस्से में गई, उसके हाथ में सत्ता रही। यही कारण है कि दोनों राजनीतिक दल आदिवासी सीटों पर फोकस कर रहे हैं। भाजपा इसकी तैयारी में अभी से जुट गई है। भाजपा इस वर्ग के कल्याण के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। पिछले तीन चुनाव में राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से आदिवासी वर्ग वाली सीटों का प्रभाव रहा। इन सीटों की हार-जीत राज्य की सियासत में बड़ा बदलाव ला देती है, जिस भी राजनीतिक दल को इन सीटों में से ज्यादा पर जीत हासिल हुई, उसे सत्ता नसीब हुई है। इतना ही नहीं लगभग हर चुनाव में यहां मतदाताओं का रूख भी बदलता नजर आता है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों में से 30 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और सत्ता में आ गई थी। वर्ष 2013 के चुनाव में भाजपा के हाथ में 31 सीटें आई थी। समूह चर्चा में ये कहा गया कि प्रदेश में 47 विधानसभा सीटें आदिवासी

मप्र भाजपा अध्यक्ष के लिए दमदार नेताओं की कतार

मप्र में भाजपा के नए अध्यक्ष के ऐलान का मुहूर्त 5 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं बन पाया है। प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के पास दमदार दावेदारों की कतार है। फिर क्या वजह है कि पार्टी में अध्यक्ष का चयन नहीं हो पा रहा है। जानकारी के मुताबिक जुलाई में राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान के पहले जिन राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होनी है, कतार में खड़े उन राज्यों में मप्र भी है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक भी दौरा मप्र में अब तक नहीं हो पाया है। उधर पार्टी संगठन में जिम्मेदारी मिलने की आस लगाए नेताओं का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब विपक्षी दल कांग्रेस भी मुद्दा उठा रही है कि क्या पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के लिए इतने पहलवान हो गए हैं कि एक नाम पर मुहर लगाना मुश्किल हो रहा है। मप्र भाजपा में पिछले 45 साल में कुल 13 प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। शुरुआत 1980 में सुंदरलाल पटवा से हुई। वे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे। इनके बाद वीडी शर्मा तक इस पद पर 13 प्रदेश अध्यक्ष रहे, बल्कि कई बार तो प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के पहले अचानक बदले गए, लेकिन इतनी देरी 45 साल में पहली बार है। मप्र में जो स्थिति है, पार्टी अध्यक्ष को लेकर कमोबेश वही स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर भी है। कहा ये जा रहा है कि जुलाई तक राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। उसके पहले प्रदेश स्तर पर अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी।

और 35 विधानसभाएं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। लेकिन, 36 सीटें ऐसी हैं जो आरक्षित नहीं हैं लेकिन, एससी वर्ग के वोटर निर्णायक हैं। इसी तरह 9 सामान्य सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी वोटर निर्णायक हैं। जो सीटें सामान्य हैं लेकिन, एससी, एसटी वोटर महत्वपूर्ण भूमिका में हैं उन सीटों के विधायकों को प्रभावशाली वोटर्स के बीच जाकर बातचीत करना चाहिए। उनके जो स्थानीय मुद्दे हैं या सरकार से अपेक्षाएं हैं उनको जानकर समाधान के लिए काम करना चाहिए।

पचमढ़ी में हुए प्रशिक्षण वर्ग में भाजपा ने विधायकों को यह टारगेट दिया है कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र के उन वर्गों से बातचीत करें जो हार-जीत तय करते हैं। भाजपा ने उन सीटों को इस लिस्ट में रखा है, जो सामान्य यानी अनारक्षित है, लेकिन हार-जीत में दलित आदिवासी वर्ग के वोटर महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। इस चर्चा से साफ है कि आगामी समय में इन 45 अनारक्षित विधानसभाओं में से कुछ सीटें आरक्षित हो सकती हैं। इनको लेकर भाजपा गंभीर है और परिसीमन के बाद होने वाले चुनाव की तैयारी में जुट गई है। गौरतलब है कि प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में एससी के लिए आरक्षित सीटें 35 हैं। इनमें कांग्रेस के एससी विधायक 9, भाजपा के एससी विधायक 26 हैं। वहीं एसटी के लिए आरक्षित सीटें 47 हैं। इनमें कांग्रेस के एसटी विधायक 22, भाजपा के एसटी विधायक 24 और अन्य दल के एसटी विधायक 1 हैं। भाजपा की कोशिश है कि आगामी विधानसभा में इन सीटों पर पार्टी का प्रदर्शन और बेहतर हो। इसके लिए अभी से रणनीति बनाकर काम किया जा रहा है। समूह चर्चा में विधायकों से कहा गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए जो क्षेत्र आरक्षित हैं वहां के विधायकों को अनुसूचित जाति, आदिवासी वर्ग के लोगों के बीच जाकर ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि क्या उन्हें शासन की योजना का पात्रता के अनुसार फायदा मिल रहा है या नहीं? लोगों, युवाओं, महिलाओं और स्थानीय स्तर पर किसानों से बातचीत कर यह जानने की कोशिश करें कि वे सरकार से क्या चाहते हैं? भाजपा से इन वर्गों की क्या अपेक्षा है? उनकी परेशानियां क्या हैं? बैठक में इस बात पर खासा जोर दिया गया कि जिन वर्गों के मतदाता प्रभावशाली भूमिका में हैं यदि वे किसी और दल के साथ जुड़े हैं तो उन्हें जोड़ने का प्रयास करें। पढ़े-लिखे युवाओं और दलित वर्ग के इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, व्यवसायियों को जोड़ने का प्रयास करें। यदि आप नहीं जोड़ेंगे तो कोई और उन्हें अपने साथ जोड़ लेगा।

मप्र में सिर्फ 15 महीनों को छोड़कर पिछले 20 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर रही है। पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। 2020 में हुए दलबदल के बाद कई क्षेत्रों में कांग्रेस का संगठन बेहद नाजुक स्थिति में हैं। अब कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए विदिशा मॉडल पर काम करेगी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने संगठनात्मक रूप से सबसे कमजोर जिले विदिशा में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए 70 एक्सपटर्स को चुनकर विदिशा जिले की पांचों विधानसभा सीटों के हर ग्राम पंचायत और वार्ड में भेजा गया। एक्सपटर्स ने पंचायत और वार्ड में सबसे पहले कांग्रेस की कमजोरी की वजहों को लेकर रिपोर्ट तैयार की। इसके बाद पंचायत और वार्ड समिति के लिए वैचारिक रूप से मजबूत कार्यकर्ताओं के नाम छांटे। बातचीत के बाद पंचायत और वार्ड समिति का गठन किया। इन समितियों के सदस्य अब गांव और वार्ड में कांग्रेस के लिए काम करेंगे। फर्जी वोटर्स की पहचान से लेकर वोटरलिस्ट वेरिफिकेशन और चुनाव की तैयारी में ये समिति काम करेगी। विदिशा जिले में समितियों के गठन के बाद अब इस मॉडल पर प्रदेश के दूसरे जिलों में काम किया जाएगा।

कांग्रेस ने विदिशा जिले की पंचायत और वार्ड समितियों का गठन करने के बाद ऑनलाइन डेटा अपलोड भी किया है। इसमें समिति के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों के नाम, मोबाइल नंबर सहित तमाम जानकारी ऑनलाइन दर्ज की गई है। अब इन समितियों के वॉट्सऐप ग्रुप बनाकर आगे संगठन के काम को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा। विदिशा जिले की पंचायतों और वार्डों में बनाई गई समितियों के वेरिफिकेशन का काम 30 जून तक चला। इसके लिए पीसीसी में एक कॉल सेंटर बनाया जा रहा है। जहां से सभी समितियों के अध्यक्ष सहित तमाम सदस्यों से टेलीफोनिक बातचीत कर सत्यापन किया जाएगा।

● श्याम सिंह सिकरवार

टिफिन मीटिंग करेंगे पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी

विदिशा जिले में गठित हुई पंचायत और वार्ड समिति के अध्यक्षों के साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जुलाई के महीने में टिफिन मीटिंग करेंगे। विधानसभा वार होने वाली टिफिन मीटिंग में सभी कार्यकर्ता अपने-अपने घर से भोजन बनवाकर टिफिन लेकर आएंगे और एक जगह पीसीसी चीफ सभी अध्यक्षों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे और भोजन करेंगे। विदिशा जिले के बाद कांग्रेस अब इस मॉडल पर भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की उन विधानसभाओं में इस पर काम शुरू करेगी, जहां कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। कांग्रेस का मानना है कि इन दोनों संभागों में कांग्रेस की स्थिति सुधारने की सबसे ज्यादा जरूरत है। कांग्रेस के संगठन प्रभारी संजय कामले ने का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत महत्वाकांक्षी पायलट प्रोजेक्ट के लिए विदिशा जिले को चुना था। पार्टी में इस बात की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी कि संगठन में किस तरह से संगठन में बदलाव करना चाहिए। कैसे कांग्रेस पार्टी की जमीनी स्तर पर शुरुआत कर सकते हैं। हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पर जोर दिया। विदिशा जिले के पायलट प्रोजेक्ट में जमीनी स्तर पर समितियों के गठन का काम करने पहुंचे एक्सपटर्स को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा।

आबाद होगा जंगल

चीता की बसाहट से टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा

वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में चीते आने वाले हैं। यह देश का ऐसा पहला टाइगर रिजर्व होगा जहां बाघ, तेंदुए व चीते एक ही जगह देखे जाएंगे। इसके पहले प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क और गांधीसागर अभयारण्य में चीता शिफ्टिंग प्रोजेक्ट सफल रहा है। 15 साल पहले चीतों की बसाहट के लिए सर्वे हुआ था। उस समय नौरादेही अभयारण्य था। इसकी तीन रेंज मुहली, सिंहपुर और झापन को चीता की बसाहट के अनुकूल माना गया था। टाइगर रिजर्व के अफसर और वाइल्ड लाइफ के जानकारों के अनुसार चीता आने में एक साल का समय लग सकता है। दरअसल, अभी एक और सर्वे बाकी है। वहीं फेंसिंग और गांवों के विस्थापन का काम भी अधूरा है। भारतीय वन्य जीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) देहरादून की टीम ने चीते की बसाहट के लिए दो नए स्थान चिन्हित किए हैं। उनमें गुजरात के बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व के अलावा सागर के इस टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। डब्ल्यूआईआई भारत के चीता प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी भी है। माना जा रहा है कि अगले वर्ष तक यहां चीतों की शिफ्टिंग हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का पहला ऐसा वाइल्ड लाइफ एरिया होगा जहां बिग कैट फैमिली के तीन सदस्य एक साथ दिखेंगे। अभी रिजर्व में टाइगर और तेंदुए की बसाहट है। चीतों के आने से इस परिवार की तीन प्रजातियां हो जाएंगी।

डब्ल्यूआईआई ने देश में सबसे पहले सागर के इस टाइगर रिजर्व को चिन्हित किया था। वर्ष 2010 में यहां पहला सर्वे किया गया था। जिसमें रिजर्व की तीन रेंज मुहली, सिंहपुर और झापन को चीता को बसाहट के अनुकूल माना गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के डीआईजी डॉ. वीवी माथुर और डब्ल्यूआईआई के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने डिप्टी डायरेक्टर डॉ. एए अंसारी के साथ वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की तीनों रेंज मुहली, झापन और सिंहपुर का दो दिन तक मैदानी मुआयना किया। जानकारों के अनुसार यह तीनों रेंज चीता की बसाहट के लिए आदर्श स्थान हैं। यहां घास के लंबे व खुले स्थान हैं। वन्य जीव शास्त्रियों का कहना है कि चीता, तेंदुए और बाघ के शिकार का तरीका और उनके टारगेट जीव-जंतु अलग-अलग होते हैं। बाघ जहां नीलगाय, भैंसा, हिरण प्रजाति के छोटे-बड़े जानवर का शिकार करता है, तो वहीं तेंदुआ मध्यम श्रेणी के जानवर जैसे जंगली सुअर, हिरण, नीलगाय, भैंसा के बच्चों का शिकार करता है। जबकि चीता छोटी साइज के हिरण जैसे चीतल, काला हिरण और खरगोश सरीखे जानवरों का शिकार करता है। चीता, बाघ व तेंदुए से दूरी बनाए रखता है। चीतों के लिए मुफीद है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नौरादेही क्षेत्र में काफी पहले चीतों के प्राकृतिक वास के प्रमाण मिले हैं। यहां घास के खुले मैदान हैं। नौरादेही से गांवों के विस्थापन के साथ मैदान और फैल रहे हैं। यहां चीते लंबी दौड़ के साथ शिकार कर सकते हैं। टाइगर रिजर्व का कोर एरिया 1414 वर्ग किमी है। बफर एरिया-925.120 वर्ग किमी का है। 600 वर्ग किमी एरिया में चीतों को रखने के लिए मैदान चिन्हित भी किए जा रहे हैं। यह क्षेत्रफल के लिहाज से प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व में चीतों को शिकार के लिए चिंकारा, चीतल व काले हिरण की पर्याप्त संख्या है। यही वजह है कि यहां बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। चीतों की यहां बाघ-बाघिन से टकराव जैसी स्थिति बनने की आशंका नहीं है। बाघ बड़े जानवरों का शिकार करता है, जबकि चीता छोटे शाकाहारी वन्य जीवों से पेट भरता है। माना जा रहा है कि अगले वर्ष तक यहां चीतों की शिफ्टिंग हो जाएगी। अगर ऐसा होता है, तो वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का पहला ऐसा वाइल्डलाइफ एरिया होगा, जहां बिग कैट फैमिली के तीन सदस्य एक साथ देखने मिलेंगे। अभी रिजर्व में टाइगर और तेंदुए की बसाहट है। चीतों के आने से इस परिवार की तीन प्रजातियां हो जाएंगी।

दुर्गावती टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. एए अंसारी ने बताया कि हाल ही में चीता की शिफ्टिंग के संबंध में सर्वे टीम आई थी। चीते आने में अभी 1 साल का वक्त लग सकता है। कुछ तैयारियां बाकी हैं। हालांकि अभी अधिकृत तौर पर हमारे पास चीता शिफ्टिंग को लेकर कोई पत्र नहीं आया है। प्रदेश में प्रोजेक्ट चीता 2022 में शुरू हुआ था। नामीबिया से आठ और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। कूनो में शावकों को मिलाकर 29 चीते हैं। इनके अलावा दो चीते गांधीसागर भेजे जा चुके हैं। 29 चीतों में 10 विदेशी हैं। 19 भारत में जन्मे हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) देहरादून ने चीते की बसाहट के लिए दो नए स्थान चिन्हित किए हैं। जिनमें गुजरात के बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व के अलावा सागर का रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व शामिल है। चीता प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी डब्ल्यूआईआई के अधिकारियों ने सागर पहुंचकर टाइगर रिजर्व में चीतों की बसाहट के लिए जंगल का निरीक्षण किया है। माना जा रहा है कि अगले वर्ष तक यहां चीतों की शिफ्टिंग हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का पहला ऐसा वाइल्ड लाइफ एरिया होगा, जहां बाघ, तेंदुओं के साथ चीता भी देखने को मिलेंगे। अभी रिजर्व में टाइगर और तेंदुए की बसाहट है। चीतों के आने से इस परिवार की तीन प्रजातियां हो जाएंगी। देश में चीतों की बसाहट के लिए डब्ल्यूआईआई ने सबसे पहले सागर के इस टाइगर रिजर्व को चिन्हित किया था।

● **लोकेश शर्मा**

टाइगर रिजर्व में इस समय टाइगर और तेंदुए हैं। पर्यटक यहां पहुंचते हैं, लेकिन चीतों की बसाहट होने से टाइगर रिजर्व में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक यहां अधिक संख्या में पहुंचेंगे, जिससे सागर समेत आसपास के क्षेत्रों में रोजगार व अन्य विकास होंगे। साथ ही टाइगर रिजर्व में पर्यटक एक साथ चीता, टाइगर और तेंदुआ देख सकेंगे। टाइगर रिजर्व में चीतों की बसाहट से ज्यादा जरूरी उनकी सुरक्षा और संरक्षण होगा। इस लिहाज से वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में कई गांवों का विस्थापन शेष रह जाने की कमी है। इनमें सबसे बड़ा गांव मुहली है। जहां की आबादी करीब 1500 लोगों की है। इसके अलावा बाकी दो रेंज झापन और सिंहपुर में भी कुछ गांव हैं। जहां से लोगों को विस्थापित करने के लिए शासन को करीब 200 करोड़ रुपए व्यय करने होंगे।

जमीन में दफन 70,000 करोड़ के हीरे

छतरपुर जिले से 100 किमी दूर बक्सवाहा के जंगलों में एक ऐसी खोज हो चुकी है, जो मप्र की तकदीर और तस्वीर बदलने का दम रखती है। 25 साल पहले बंदर डायमंड प्रोजेक्ट के तहत बक्सवाहा के जंगलों में एक सर्वे शुरू हुआ था, जिसमें जमीन के नीचे 3 करोड़ कैरेट से ज्यादा (लगभग 6000 किलो) हीरे का भंडार होने का दावा किया गया था। उस वक्त इस डायमंड डिपॉजिट की अनुमानित कीमत 55 हजार करोड़ रुपए आंकी गई थी, जो अब लगभग 60 से 70 हजार करोड़ रुपए के करीब है। अगर ये खजाना जमीन से बाहर आता तो मप्र की किस्मत बदल जाती।

दरअसल, मप्र के बक्सवाहा के जंगलों में यह सर्वे ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रियोटिंटो ने कराया था। देश की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी रियोटिंटो ने सन् 2000 से 2005 के बीच पूरे बक्सवाहा जंगल में सर्वे कराया। एक दिन सर्वे टीम की खुशी का ठिकाना न रहा जब उन्हें किंबरलाइट पत्थरों की बड़ी-बड़ी चट्टानें नजर आईं। दरअसल, हीरा इसी किंबरलाइट की चट्टान में पाया जाता है। 25 साल पहले रियोटिंटो कंपनी को यहां हीरों के भंडार का पता चला था। कंपनी को यहां बड़े पैमाने पर किंबरलाइट की चट्टानें मिली थीं। दावा था कि जमीन के नीचे 55 हजार करोड़ तक के हीरे हो सकते हैं। दावा था कि जंगल में जमीन के नीचे साढ़े तीन करोड़ कैरेट (लगभग 6000 किग्रा) से ज्यादा के हीरे हैं। हालांकि, इसकी खोज करने वाली कंपनी 2017 में इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गई, जिसके बाद बक्सवाहा के जगंल को सरकार ने हीरा निकालने के लिए नीलाम किया था। ये प्रोजेक्ट लीज पर आदित्य बिड़ला ग्रुप की एसेल माइनिंग कंपनी को 2019 में मिला पर हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। छतरपुर जिले की बक्सवाहा हीरा खदान 2019 में नीलाम की गई थी। आदित्य बिड़ला ग्रुप की एसेल माइनिंग कंपनी ने 50 साल की लीज पर इसे लिया था। कंपनी को लगभग 364 हेक्टेयर जमीन मिली थी। खुदाई शुरू हो पाती उसके पहले ही पर्यावरण प्रेमियों और सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। बताया गया था कि इस जंगल में 62.64 हेक्टेयर क्षेत्र हीरे निकालने के लिए चिह्नित किया गया था, पर कंपनी ने 382.131 हेक्टेयर का जंगल मांगा, जिससे बाकी जमीन का उपयोग खनन करने और प्रोसेस के दौरान खदानों से निकला मलबा डंप करने में किया जा सके। इसी दौरान हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया।

खनिज अधिकारी अमित मिश्रा के मुताबिक, बक्सवाहा के जंगलों में बंदर डायमंड के नाम से एक ब्लॉक बनाया गया था, जिसे रियोटिंटो कंपनी ने एक्सप्लोर किया था लेकिन रियोटिंटो उसे छोड़कर चली गई थी। उस समय फॉरेस्ट से उन्होंने रकबा बहुत बड़ा मांगा था, जो किसी वजह से नहीं दिया गया। उसके बाद एक छोटा रकबा 364 हेक्टेयर का बनाया गया था। अगर बक्सवाहा की माइंस चलती तो एशिया की सबसे बड़ी माइंस होती, उस समय 55 हजार करोड़ के हीरे निकलने की वेल्युएशन की गई थी।

वहीं खनिज अधिकारी ने आगे कहा, 364 हेक्टेयर क्षेत्र की लीज दी गई तो अफवाहें उड़ीं कि पूरे में खुदाई होगी और लाखों पेड़ कटेंगे। ये महज अफवाह थी। अब खुदाई की आधुनिक तकनीकें आ गई हैं, ज्यादा से ज्यादा एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर जमीन पर ही खुदाई होती है, इससे न तो ज्यादा पेड़ कटते हैं और न वन्य जीवों को नुकसान होता है। जितने पेड़ कटते हैं उसके 10 गुना पेड़ लगवाए भी जाते है, और उनकी पूरी देखरेख की जाती है। वन विभाग ने जंगल के पेड़ों की अनुमानित संख्या करीब सवा दो लाख बताई है और खनन के दौरान इन सभी पेड़ों को काटना पड़ेगा। इन पेड़ों में सबसे ज्यादा पेड़ सागौन के हैं। इसके अलावा पीपल, तेंदू, जामुन, अर्जुन और कई औषधीय पेड़ भी यहां मौजूद हैं।

भारत में अभी तक का सबसे बड़ा हीरा भंडार छतरपुर के ही पास पन्ना जिले में है जबकि बक्सवाहा में पन्ना से 15 गुना ज्यादा हीरे निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। मप्र सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में हीरे की खोज के लिए साल 2000 में ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रियोटिंटो की मदद से एक सर्वे कराया था। सर्वे के दौरान टीम को कुछ जगहों पर किंबरलाइट पत्थर की चट्टानें दिखाई दीं। हीरा इन्हीं किंबरलाइट की चट्टानों में मिलता है। साल 2002 में ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रियोटिंटो को बक्सवाहा के जंगल में हीरे तलाशने का काम औपचारिक रूप से मिल गया। लंबे शोध के बाद कंपनी ने खनन की तैयारियां शुरू कीं लेकिन स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों के विरोध के चलते रियोटिंटो ने साल 2016 में इस परियोजना से खुद को अलग कर लिया। साल 2019 में इसकी दोबारा नीलामी की गई और हीरों की खदान का नया लाइसेंस आदित्य बिड़ला ग्रुप की एसेल माइनिंग कंपनी को मिला।

● **सिद्धार्थ पांडे**

वन जाएगा तो जीवन जाएगा

खनन और पर्यावरण जैसे मामलों में सक्रिय रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता आशीष सागर कहते हैं कि लोग लंबे समय से इसका विरोध कर रहे हैं लेकिन सरकार हीरों के लालच में जंगल नष्ट करने पर तुली हुई है। आशीष कहते हैं कि हीरे निकालने के लिए पेड़ काटने से पर्यावरण को भारी नुकसान होना तय है। इसके अलावा वन्यजीवों पर भी संकट आ जाएगा। सरकार और कंपनी हर स्तर पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन पहले एनजीटी और अब हाईकोर्ट ने भी इसकी गंभीरता को महसूस किया है। मई 2017 में सरकार ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें तेंदुआ, गिद्ध, भालू, बारहसिंगा, हिरण, मोर जैसे वन्यजीवों के होने की बात कही गई थी लेकिन अब नई रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये वन्यजीव यहां नहीं हैं। छतरपुर के ही रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर साल 2007 से ही पर्यावरण को होने वाले नुकसान और जंगल में मौजूद प्रागैतिहासिक साक्ष्यों के नष्ट हो जाने के खतरे के कारण खनन के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। अमित भटनागर कहते हैं कि स्थानीय लोगों और कई आदिवासी समुदाय के लोगों की आजीविका जंगल से ही चल रही है और जंगल के नष्ट होने से हजारों लोगों के सामने आजीविका का संकट आ जाएगा।

कट्टर विचारधाराएं, विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं और अत्याधुनिक हथियारों की होड़

विनाश की राह पर मानवता!

विकास के साथ विश्व के शक्तिशाली देश विस्तारवाद की होड़ में दूसरे देशों की सीमाओं को अपने में मिलाने में लगे हुए हैं। कट्टर विचारधाराएं, विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं और अत्याधुनिक हथियारों की होड़ के बीच साइबर और परमाणु आयुधों से लैस देशों की आपसी टकराहट भविष्य को चुनौती दे रही है। इस बीच अमेरिका अपने आप को विश्व की नंबर-1 शक्ति बनाने के लिए जिस तरह की पैंतरेबाजी कर रहा है, उससे मानवता विनाश की ओर बढ़ रही है।

● राजेंद्र आगाल

विख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने परमाणु युद्ध के विनाशकारी परिणामों को लेकर चेताते हुए कहा था कि मुझे नहीं पता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, पर चौथा विश्व युद्ध लाठियों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। उनका यह कथन तीसरे विश्व युद्ध के भयावह खतरे को दर्शाता है, खासकर जब आज 9 देशों के पास 12,000 परमाणु हथियार हैं। रूस, ईरान और पाकिस्तान की परमाणु पैंतरेबाजी का उल्लेख इस भयावह दूरदृष्टि की प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। 20वीं सदी, जो औद्योगिक क्रांति के बाद वैश्विक विवेक की उम्मीद जगाने वाली थी, वही सदी-होलोकॉस्ट, हिरोशिमा, रवांडा, कंबोडिया, वियतनाम, स्टालिनवाद, माओ के कल्चरल रिवोल्यूशन और 9/11 आतंकी हमले जैसी घटनाओं से भर गई। ये सभी त्रासदियां उन्हीं राष्ट्रों, विचारधाराओं और आदर्शों के नाम पर घटीं, जो खुद को मुक्ति और प्रगति के वाहक मानते थे।

हमारी दुनिया एक ऐसी शतरंज की बिसात बन चुकी है, जहां हर चाल सत्ता, भय और विनाश के इर्द-गिर्द घूमती है। वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य तनावपूर्ण है। रूस-यूक्रेन युद्ध, मध्य-पूर्व में इजराइल-ईरान, अफ्रीका-म्यांमार में गृहयुद्ध और एशिया में बढ़ते क्षेत्रीय विवादों ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ा दी है। आज का विश्व उस मुहाने पर खड़ा है, जहां परमाणु महत्वाकांक्षाएं, हाइब्रिड युद्ध की रणनीतियां और सभ्यताओं का टकराव मानवता के भविष्य को चुनौती दे रहा है। ईरान-इजराइल संघर्ष अब केवल दो देशों का विवाद नहीं रहा, बल्कि एक व्यापक वैचारिक युद्ध का रूप ले चुका है। मानव जाति स्वतंत्रता की खोज में जिस पथ पर चली, वहां सत्ताएं बदलीं, व्यवस्थाएं गिरीं, साम्राज्य टूटे, लेकिन उनके स्थान पर जो कुछ आया, उसमें एक नई किस्म की हिंसा छिपी हुई थी-संवैधानिक, संस्थागत और वैचारिक। आजादी के नाम पर भीड़ उन्मादी बनी, राष्ट्र एक-दूसरे पर टूट पड़े और नागरिक समाज राष्ट्र-राज्य की मशीनरी में पिसता चला गया। जहां एक ओर **डेमोक्रेसी** का नाम लेकर औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ, दूसरी ओर उसी लोकतंत्र ने कई देशों में तानाशाही का मुखौटा पहन लिया। हिटलर भी लोकतांत्रिक ढंग से सत्ता में आया था, स्टालिन ने भी जनता के नाम पर लाखों लोगों की हत्या की थी और अमेरिका ने फ्री वर्ल्ड के नाम पर वियतनाम और इराक को झुलसा दिया था। अब विकास के साथ विश्व के शक्तिशाली देश विस्तारवाद की होड़ में दूसरे देशों की सीमाओं को अपने में मिलाने में लगे हुए हैं। कट्टर विचारधाराएं, विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं और अत्याधुनिक हथियारों की होड़ के बीच साइबर और परमाणु आयुधों से लैस देशों की आपसी टकराहट भविष्य को चुनौती दे रही है। इस बीच अमेरिका अपने आप को विश्व की नंबर-1 शक्ति बनाने की लिए जिस तरह की पैंतरेबाजी कर रहा है, उससे मानवता विनाश की ओर बढ़ रही है।

इजराइल-ईरान संघर्ष विराम

कुछ दिनों के भीषण युद्ध के बाद इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम हो गया। कहना मुश्किल है कि यह संघर्ष विराम कितने समय तक टिकेगा? ईरान पर हमला बोलते समय इजराइल ने यह कहा था कि उसका उद्देश्य ईरानी परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना है। उसे कुछ आरंभिक सफलता भी हासिल हुई। उसके अचानक हमले में ईरान के कई शीर्ष सैन्य कमांडर और परमाणु विज्ञानी मारे गए। शुरुआती सफलता के बीच इजराइल ने कहना शुरू कर दिया कि हमले के पीछे उसके उद्देश्य बड़े हैं और एक उद्देश्य ईरान में सत्ता परिवर्तन का भी है। ईरान की सत्ता उन कट्टर मजहबी नेताओं के कब्जे में है, जो हमास-हिजबुल्ला का साथ देते हैं। इजराइल के समर्थन में अमेरिका के कई ताकतवर नवरूढ़िवादी सांसदों की आवाज भी उठने लगी। शुरुआत में अमेरिका इस लड़ाई में कूदने से हिचक रहा था, पर ईरान की जवाबी कार्रवाई से घिरे इजराइल की मदद के लिए आखिरकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी वायुसेना को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के आदेश देने ही पड़े। इसके बावजूद ईरानी परमाणु कार्यक्रम के पूरी तरह ध्वस्त होने को लेकर संदेह है। वैसे भी ईरान की मिसाइल क्षमता आशा से कहीं अधिक निकली। युद्ध लंबा खिंचने पर इजराइल में कहीं अधिक बर्बादी हो सकती थी। इसी कारण ट्रंप ने आनन-फानन युद्ध विराम का ऐलान भी कर दिया और वह भी अपने व्यापक लक्ष्यों की पूर्ति के बिना, क्योंकि न तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट हो पाया और न ही वहां सत्ता परिवर्तन के फिलहाल कोई आसार दिख रहे हैं। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं कि इजराइल और ट्रंप के मागा (मेक अमेरिकी ग्रेट अगेन) खेमे ने यह योजना सदा के लिए छोड़ दी है। सही मौका देखकर इसे फिर से क्रियान्वित करने का प्रयास होगा।

वैसे तो अमेरिका को फिर से महान बनाने के अभियान में लगा ट्रंप प्रशासन ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए किसी जमीनी युद्ध में नहीं उलझना चाहता, परंतु उसके इरादों को देखते हुए भारत को सतर्क होना होगा। भारत को सामरिक दृष्टिकोण से भी इस **युद्ध के निहितार्थ** समझने की आवश्यकता है। इजराइल-ईरान युद्ध के दौरान व्हाइट हाउस में ट्रंप की ओर पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की आवभगत का एक गहरा अर्थ है। जब मुनीर व्हाइट हाउस में थे, लगभग उसी समय अमेरिकी मदद से सत्तासीन बांग्लादेश की भारत विरोधी मोहम्मद यूनुस सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी वाशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों से मिल रहे थे।

शक्ति का संतुलन नहीं

आज विश्व उसी दहलीज पर खड़ा है, जहां परमाणु महत्वाकांक्षाएं, हाइब्रिड युद्ध की रणनीतियां और सभ्यताओं का टकराव मानवता के भविष्य को चुनौती दे रहा है। हर राष्ट्र ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हथियारों का विशाल भंडार एकत्रित कर लिया है, परंतु शक्ति का यह संतुलन अब पूर्णतः बिखर चुका है। विश्व के 9 देशों-रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल व उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) के अनुसार, रूस और अमेरिका के पास कुल 12,000 परमाणु हथियारों का 90 प्रतिशत हिस्सा है। रूस के पास 5,459 परमाणु हथियार हैं, जिन्हें उसने 1,710 मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और बमवर्षकों पर तैनात कर रखा है। प्लेटो ने कहा था, जब शक्ति बिना नैतिकता के आती है, तो वह विनाश को जन्म देती है। यह कथन आज के परमाणु संपन्न विश्व के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। इस असीम शक्ति ने विश्व को एक ऐसे कगार पर पहुंचा दिया है, जहां संतुलन की जगह भय और अविश्वास ने ले ली है। दरअसल, रूस ने 2022 में अपनी परमाणु नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया। इसके अनुसार, यदि कोई गैर-परमाणु देश परमाणु शक्ति के समर्थन से रूस पर हमला करता है, तो उसे युद्ध माना जाएगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट रूप से कहा, हम अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर हथियार का उपयोग करेंगे, चाहे वह परमाणु हो या पारंपरिक। उनका यह बयान यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में था। रूस ने आरएस-28 सरमत मिसाइलें तैनात की हैं, जो पूरे क्षेत्र को तबाह करने की क्षमता रखती हैं। इस युद्ध ने न केवल यूरोप को, बल्कि संपूर्ण विश्व को एक नए महायुद्ध की आशंका में डाल दिया है। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो यह युद्ध शक्ति व नैतिकता के बीच गहरे टकराव को दर्शाता है।

भारत की कूटनीतिक चुनौती

भारत की स्थिति इन सभ्यताओं के संघर्ष के मध्य अत्यंत विशिष्ट और चुनौतीपूर्ण है। भारत के इजराइल और ईरान, दोनों देशों के साथ गहरे और बहुआयामी संबंध हैं। इजराइल के साथ सैन्य सहयोग निरंतर बढ़ रहा है, जबकि ईरान के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और ऊर्जा-आधारित संबंध मजबूत हैं। चाबहार बंदरगाह भारत की उत्तरी पहुंच का महत्वपूर्ण द्वार है, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है। दूसरी ओर, इजराइल से प्राप्त रक्षा तकनीक भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बन चुकी है। यह स्थिति भारत की कूटनीतिक क्षमताओं की वास्तविक परीक्षा है। दक्षिण एशिया में भारत-पाकिस्तान परमाणु समीकरण एक अलग चुनौती प्रस्तुत करता है। सिपरी के अनुसार, भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। भारत की पहले प्रयोग नहीं की नीति के विपरीत, पाकिस्तान की परमाणु नीति अस्पष्ट है, जिससे क्षेत्रीय तनाव निरंतर बना रहता है। पाकिस्तानी मंत्री शाजिया मर्री का यह कथन कि हमारा परमाणु शस्त्रागार सजावट के लिए नहीं है, भारत के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है। पाकिस्तान द्वारा अपनी परमाणु ताकत को इस्लामिक बम के रूप में प्रचारित करना भारत की चिंता बढ़ाता है। हालांकि, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर पर वार्ता के बाद अस्थायी शांति बनी है, पर स्थिति नाजुक बनी हुई है। दार्शनिक दृष्टिकोण से यह टकराव मानवीय स्वार्थ और भय को दर्शाता है।

एटमी खतरा

अभी तक दुनिया में 9 देशों के पास एटमी हथियार हैं। उनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी पांच सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन हैं। उनके अलावा भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल हैं। लेकिन इजराइल इसे स्वीकार नहीं करता। एटमी हथियार प्रतिरोधक की तरह हैं, जैसा कि शीतयुद्ध के दौरान अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बीच था। दोनों के बीच सिर्फ एक बार जरूर एटमी हथियारों के इस्तेमाल का डर राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के कार्यकाल में क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान पैदा हुआ था। तब ऐसा लगा था कि अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ दोनों ही तैयारी में हैं, लेकिन दोनों आखिर पीछे हट गए। दुनिया 1945 में **एटम बम का भारी विध्वंस** और विनाश देख चुकी है। तब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर उसे फेंका था। उस विनाश और वर्षों तक उसके असर को देखकर कोई भी जिम्मेदार सरकार ऐसा करने की जुर्रत नहीं करेगी। भले कुछ हलकों में यह चिंता है कि एटमी हथियार संपन्न भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे के खिलाफ ऐसी हरकत कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही देश ऐसा कतई नहीं करेंगे क्योंकि सीमा के दोनों तरफ के लोग उससे प्रभावित होंगे। इसीलिए, अतिरंजित धमकियों और दावों के बावजूद रूस के व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ एटमी हथियार का इस्तेमाल करेंगे, ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती है। बेशक, यह डर जरूर है कि किसी एटमी संयंत्र के पास गलती से मिसाइल या ड्रोन हमले हो सकते हैं और भीषण तबाही हो सकती है। उत्तर कोरिया के किम जोंग अमूमन उनके दुश्मनों को एटमी हमले की बात करके धमकाते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने जिम्मेदार रवैया ही दिखाया है।

रूस-यूक्रेन युद्ध फरवरी 2022 में शुरू हुआ था, जो चौथे वर्ष में प्रवेश कर गया है। दोनों पक्ष एक-दूसरे के खिलाफ अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर कैलिबर क्रूज मिसाइलें, किंझाल हाइपरसोनिक मिसाइलें, इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें और गेरान-2 (शाब्दिक रूप से जेरेनियम-2) ड्रोन से घातक हमले कर रहा है। गेरान-2 को यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों द्वारा ईरानी-निर्मित शाहेद-136 का परिवर्तित रूप माना जाता है। कुछ समय पहले ही अमेरिकी खुफिया सूत्रों और यूक्रेनी अधिकारियों ने दावा किया था कि ईरान ने रूस को शाहेद-136 सहित कई सौ ड्रोन की आपूर्ति की थी। हालांकि ईरान ने बार-बार इन दावों को खारिज किया कि उसने यूक्रेन को ड्रोन भेजे। साथ ही युद्ध में तटस्थ रहने की बात कही है। 6 जून, 2025 को रूस ने एक रात में 479 ड्रोन और 20 मिसाइलों से हमला किया, जिसका जवाब यूक्रेन ने 277 ड्रोन और 19 मिसाइलों को नष्ट करके दिया। कीव में हुए इन हमलों में 14 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए, जिससे युद्ध की क्रूरता उजागर हुई। उधर, यूक्रेन ने पश्चिमी सहायता से हिमारस रॉकेट सिस्टम, जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइलें, पैट्रियाट हवाई रक्षा प्रणाली और तुर्की निर्मित बायकर टीबी2 ड्रोन का उपयोग किया है। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर छोटे ड्रोनों से हमले किए, जो रूस की वायु रक्षा प्रणालियों को भेदने में सक्षम हैं। अब रूस ने 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न करने वाली ओरेश्निक बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करने की धमकी दी है, जिससे युद्ध और घातक हो सकता है।

ईरान-अमेरिका

विडंबना यह है कि तेहरान का एटमी सफर अमेरिकी मदद से ही शुरू हुआ, जब अमेरिका के भरोसेमंद दोस्त ईरान के शाह सत्ता में थे। शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने 1953 में तख्तापलट करके प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेग की निर्वाचित सरकार को हटा दिया और सरकार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। अमेरिका और ब्रिटेन ने उस तख्तापलट का समर्थन किया था। वहां एटमी कार्यक्रम 1950 के दशक में शुरू हुआ। यह तब तक ठीक-ठाक था, जब तक ईरान और पश्चिमी दुनिया के बीच टकराव नहीं उभरे थे। लेकिन 1979 की इस्लामी क्रांति से हालात बदल गए, जब शाह को देश छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। अयातुल्ला खामेनेई और क्रांति के झंडाबरदार शाह से नफरत करते थे। उन्हें शाह के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण अमेरिका और पश्चिमी दुनिया भी उतनी ही नापसंद थी। इसीलिए, आश्चर्य नहीं है कि इस्लामी क्रांति के पैरोकारों ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और दर्जनों अमेरिकियों को बंधक बना लिया और उन्हें 14 महीने से अधिक समय तक बंधक बनाए रखा। वहां कूटनीतिक शिष्टाचार के बदले अमेरिका मुर्दाबाद के नारे ही गूंजते रहे। उसके बाद ऐसी दुश्मनी और संदेह पैदा हो गया, जो आज भी एटमी गतिरोध में दिखता है। क्रांति के दौरान अराजकता के दौर में ईरान में एटमी

कार्यक्रम रोक दिया गया था, लेकिन 1980 के ईरान-इराक युद्ध के दौरान गुप्त रूप से फिर से शुरू किया गया। इसी वजह से अमेरिका-ईरान संबंधों में दरार आज भी जारी है। ईरान ने 1950 के दशक में जो एटमी कार्यक्रम शुरू कर दिया था, उसमें 1970 के दशक में बिजली रिएक्टरों की योजना के साथ उसका विस्तार हो गया था। लेकिन इस्लामी क्रांति के बाद कुछ ठहराव और फिर ईरान-इराक युद्ध के दौरान इस परियोजना को नए सिरे से शुरू किया गया, तबसे ईरानी वैज्ञानिक एटमी कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं। लंबे समय तक अमेरिका से कठोर प्रतिबंधों का सामना करने के बाद ईरान ओबामा के दौर में एटमी समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार था। संयुक्त व्यापक कार्ययोजना या जेसीपीओए नामक उस समझौते को ईरान को सैन्य एटमी महत्वाकांक्षाएं छोड़ने और असैन्य एटमी उपयोग की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया था।

तीसरे विश्वयुद्ध की आशंका

बीते कुछ सालों में दुनिया के कई देशों के बीच टकराव बढ़ा है। रूस और यूक्रेन पिछले 3 साल से जंग में उलझे हुए हैं। पश्चिम एशिया में भी ईरान और इजराइल के बीच तनाव बना हुआ है और दोनों देश हाल ही में सीधी जंग भी लड़ चुके हैं। इधर, एशिया में भी भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष हाल ही में खत्म हुआ है। दुनिया के इन देशों के बीच जैसे-जैसे संघर्ष आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे तीसरे विश्वयुद्ध की आशंका भी बढ़ती जा रही है। अगर तीसरा विश्वयुद्ध होता भी है तो सिर्फ रूस, यूक्रेन, ईरान, इजराइल जैसे देश ही इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। दरअसल, दुनिया के कई और देश हैं जिनके बीच तनाव बना हुआ है और कभी भी सैन्य संघर्ष छिड़ सकता है।

चीन और ताइवान दुनिया के उन देशों में शुमार हैं, जिनके बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि चीन का इरादा ताइवान पर कब्जा करने का है, यहां तक कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। हालांकि, ताइवान अपनी संप्रभुता पर डटा हुआ है। बीते साल जनवरी में चीन ने 12 बार ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की थी। इसके बाद अप्रैल, 2024 में भी चीनी फाइटर जेट्स कई बार ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल हो चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया दो हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा था उत्तर कोरिया और दूसरा हिस्सा दक्षिण कोरिया। यह विभाजन ही दुनिया के सबसे बड़े विवाद का कारण बना। दक्षिण कोरिया अमेरिका के करीब होता गया और उत्तर कोरिया को रूस और चीन जैसे देशों का साथ मिला। 1968 में उत्तर कोरिया पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की हत्या की नाकाम कोशिश के आरोप भी लगे। यहीं से यह विवाद कट्टर दुश्मनी में बदल गया। उत्तर कोरिया कई बार अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए दक्षिण कोरिया की सीमा पर मिसाइलों का परीक्षण करता रहता है।

भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। 1947 में हुए विभाजन के बाद से अब तक पाकिस्तान कई बार भारत पर हमला कर चुका है और उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़े विवाद की जड़ कश्मीर मुद्दा है, जिसके लिए पाकिस्तान भारत में आतंकी हमले भी करवाता रहता है। भारत के विपरीत, ईरान ने एटमी अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करके गलती की, जो देशों को परमाणु हथियार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से रोकती है। इस संधि को वैश्विक एटमी प्रसार व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है, हालांकि इसमें देशों को असैन्य एटमी ऊर्जा के इस्तेमाल की इजाजत है। 1968 में जब इस संधि पर हस्ताक्षर हो रहे थे, तो 168 देशों ने उस पर अपनी मुहर लगाई और वह 1970 में लागू हुई थी। भारत ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। उसकी दलील थी कि इसमें भेदभाव है क्योंकि यह दूसरों को एटमी इस्तेमाल से रोकती है, लेकिन जिनके पास परमाणु हथियार हैं उन्हें रखने की छूट देती है। अगर निरस्तीकरण लक्ष्य है, तो एटमी हथियार वाले देशों को अपने भंडार नष्ट करने होंगे। उससे पांच एटमी हथियार शक्तियों- अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस को अनुचित लाभ मिला क्योंकि उन सभी ने पहले ही परीक्षण कर लिया था और जो वे चाहते थे, वह बना लिया था। बहरहाल, हालात बिगड़ते जा रहे हैं और दुनिया में युद्ध और एटमी खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अमेरिका की पहल बेहद जरूरी हो गई है। तमाम आशंकाओं के बाद 16 जून को अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति का जोर युद्ध पर नहीं, शांति पर है। इसलिए शायद अमेरिका सीधे युद्ध में न कूदे लेकिन ईरान और इजराइल को भी

चीन की रणनीति

चीन की भू-राजनीतिक दृष्टि केवल प्रशांत क्षेत्र या ताइवान तक सीमित नहीं है। पिछले दशक में चीन ने ईरान के साथ ऊर्जा, रक्षा और तकनीक के क्षेत्रों में गहन भागीदारी विकसित की है। मार्च 2021 में दोनों देशों ने 25 वर्षीय रणनीतिक समझौता किया, जिसके अंतर्गत चीन ईरान में 400 अरब डॉलर का निवेश करेगा और बदले में ईरान नियमित तेल आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। इसे केवल वाणिज्यिक संबंध मानना भूल होगी। यह चीन की पश्चिम एशिया में प्रभाव स्थापित करने की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। अली हुसैनी खामेनेई और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठकों में बार-बार साझा सभ्यताओं की रक्षा और पश्चिमी हस्तक्षेप का विरोध जैसी चर्चाएं होती रही हैं। हार्वर्ड के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स के निदेशक रहे सैमुएल हंटिंगटन ने 1993 में भविष्यवाणी की थी, आने वाला संघर्ष राष्ट्रों के बीच नहीं, बल्कि सभ्यताओं के बीच होगा। आज ईरान इस्लामी जागरण की बात करता है और इजराइल अपनी यहूदी पहचान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जो इस बात का संकेत है कि यह सांस्कृतिक और पांथिक प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट रूप ले चुका है। हाल के वर्षों में इजराइल के हमलों का प्रत्युत्तर ईरान ने सिर्फ प्रत्यक्ष नहीं, बल्कि हिज्बुल्लाह, हूती विद्रोही और सीरिया स्थित मिलिशिया जैसी प्रॉक्सी सेनाओं के माध्यम से दिया है। ईरान अब शिया क्रीसेंट को सक्रिय कर रहा है, जो लेबनान से लेकर इराक, सीरिया और बहरीन तक फैला हुआ है। यह संघर्ष मध्य-पूर्व की उन पुरानी दरारों को पुनः गहरा कर रहा है, जो पहले से ही सुन्नी-शिया और अरब-गैर-अरब तनावों से ग्रस्त हैं। सऊदी अरब की प्रतिक्रिया इस संदर्भ में निर्णायक होगी। युवराज सलमान ने स्पष्ट चेतावनी दी थी, अगर ईरान परमाणु शक्ति बनता है, तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। इससे क्षेत्रीय परमाणु दौड़ की शुरुआत हो सकती है।

अपने इरादों में सुधार करना पड़े। शायद पश्चिमी एशिया में स्थितियां उस तरह न बदलें, जैसा नेतन्याहू और अमेरिकी प्रशासन का इरादा रहा है।

सैन्य खर्च में बेतहाशा वृद्धि

2024 में रूस के यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद से यूरोपीय क्षेत्र के सैन्य खर्च में व्यापक इजाफा हुआ है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक यूरोप का सैन्य खर्च 2024 में 17 प्रतिशत बढ़कर 693 अरब डॉलर हो गया, जो 2015 के मुकाबले 83 फीसदी अधिक है। आंकड़ों के मुताबिक, 2024 में माल्टा को छोड़कर सभी यूरोपीय देशों के सैन्य खर्च में वृद्धि हुई है। रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से 2024 में यूक्रेन का कुल सैन्य खर्च 2.9 फीसदी बढ़कर 64.7 अरब डॉलर रहा। अगर इसे जीडीपी यानी यूक्रेन की कुल अर्थव्यवस्था के मुकाबले देखें तो स्थिति ज्यादा साफ नजर आती है। 2024 में यूक्रेन का सैन्य खर्च उसकी कुल जीडीपी का 34 फीसदी रहा। हालांकि, यह 2023 के 37 फीसदी के मुकाबले कम है, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है, जिसका सैन्य खर्च उसकी कुल जीडीपी के मुकाबले दहाई अंकों में हैं, जबकि दुनिया के शीर्ष सैन्य खर्च वाले देशों में जीडीपी के मुकाबले उनके सैन्य खर्च की हिस्सेदारी 10 फीसदी से काफी नीचे है। रूस का इसी वर्ष सैन्य खर्च (अनुमानित) 149 अरब डॉलर रहा, जो उसकी जीडीपी का 7.1 फीसदी हिस्सा है। यह 2023 के मुकाबले सालाना आधार पर 38 प्रतिशत अधिक है। गौरतलब है कि रूस जहां 2024 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले शीर्ष पांच देशों में शुमार रहा, वहीं यूक्रेन शीर्ष 10 में आठवें पायदान पर शामिल रहा। मध्य पूर्व में सऊदी अरब सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश है। वैश्विक तौर पर यह सातवां बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। मध्य-पूर्व का यह क्षेत्र पहले इजराइल-फिलीस्तीन संघर्ष का गवाह रहा और अब इस क्षेत्र में एक और संघर्ष व्यापक रूप लेता दिख रहा है। 2024 में मध्य पूर्व क्षेत्र का कुल सैन्य खर्च 243 अरब डॉलर रहा, जो 2023 के मुकाबले सालाना आधार पर 15 फीसदी अधिक है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश सऊदी अरब है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के बाद इजराइल और ईरान के बीच तनाव और संघर्ष की स्थिति गंभीर होती जा रही है। दोनों संघर्ष में इजराइल के शामिल होने की वजह से 2024 में उसके सैन्य खर्च में 65 फीसदी का इजाफा देखने को मिला और यह बढ़कर 46.5 अरब डॉलर हो गया। जीडीपी में प्रतिशत हिस्सेदारी के आधार पर देखें तो 2023 में इजराइल की जीडीपी में उसके रक्षा खर्च की हिस्सेदारी 5.4 प्रतिशत रही, जो 2024 में बढ़कर 8.8 फीसदी हो गई। यूक्रेन के बाद इजराइल दूसरा सर्वाधिक खर्च करने वाला देश है। वहीं, 2023 के मुकाबले 2024 में ईरान का रक्षा खर्च कम रहा।

आंकड़ों के मुताबिक, 2024 में इरान का रक्षा खर्च करीब 8 अरब डॉलर रहा, जो उसकी जीडीपी का 2 प्रतिशत है। रक्षा खर्च में आई कमी की वजह अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से महंगाई में इजाफा होना है। अमेरिकी प्रतिबंधों का असर ईरान के तेल निर्यात पर पड़ा है, जो ईरान के निर्यात राजस्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एशिया और ओशेनिया क्षेत्र में 2024 में कुल रक्षा खर्च 629 अरब डॉलर रहा, जो 2023 के मुकाबले 6.3 फीसदी अधिक है। 2024 में सालाना वृद्धि के लिहाज से देखें तो विशेषकर पूर्वी एशिया में सैन्य खर्च में 2024 में 7.8 फीसदी का इजाफा हुआ और यह बढ़कर 433 अरब डॉलर हो गया। उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरे को देखते हुए दक्षिण कोरिया ने रक्षा खर्च में वृद्धि की, वहीं ताइवान ने भी अपने रक्षा खर्च में करीब दो फीसदी का इजाफा किया। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान लगातार अमेरिका से हथियार खरीद रहा है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दक्षिण एशिया तनाव का केंद्र बिंदु रहा। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब सीजफायर की वजह से तनाव में कमी आई है। हालांकि, पिछले कई वर्षों से भारत ने अपने रक्षा खर्च में इजाफा किया है। 2024 के सैन्य खर्च के आंकड़ों के मुताबिक, 2024 में भारत का कुल सैन्य खर्च 86.1 अरब डॉलर रहा है, जो 2023 के मुकाबले 1.6 फीसदी अधिक है। अगर जीडीपी में हिस्सेदारी के लिहाज से देखें तो 2024 में भारत के रक्षा खर्च की उसकी जीडीपी में हिस्सेदारी 2.3 फीसदी रही। वैश्विक तौर पर सैन्य खर्च के मामले में भारत चौथा बड़ा देश है। वहीं पाकिस्तान का 2024 में सैन्य खर्च 10.2 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 5 फीसदी कम है। जीडीपी के मुकाबले अगर देखें तो 2024 में पाकिस्तान की जीडीपी में सैन्य खर्च की हिस्सेदारी 2.7 फीसदी रही। 2025-26 के केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय को 6,81,210.27 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जो पिछले वर्ष के बजटीय अनुमान के मुकाबले 9.5 फीसदी अधिक है।

जंग समाप्ति के बाद अब ईरान में तख्तापलट के आसार

इजराइल के साथ जारी युद्ध के बीच ईरान में अली हुसैनी खामेनेई की सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इजराइल के हमलों में ईरान के कई शीर्ष सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। इजराइल ने ईरान की सेना और शासन के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया है, जिससे सत्ता संरचना कमजोर हुई है। दूसरे, 85 वर्षीय खामेनेई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनके शासन को घरेलू (महंगाई, मानवाधिकार उल्लंघन, महिलाओं के अधिकार) और बाहरी (इजराइल-अमेरिका के हमले, परमाणु कार्यक्रम पर दबाव), दोनों मोर्चों पर गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है। इससे भी खामेनेई शासन के तख्तापलट की आशंका बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में तीन प्रमुख गुट सत्ता के दावेदार माने जा रहे हैं। पहला, विदेश में बसे विपक्षी नेता, जिनमें सबसे प्रमुख नाम रजा शाह पहलवी (पूर्व शाह के बेटे) का है, जो लोकतांत्रिक और पश्चिम समर्थक ईरान की बात करते हैं। दूसरा गुट, मोजाहेदीन-ए-खल्क (एमईके) है, जो प्रमुख विपक्षी संगठन है और मौजूदा इस्लामी शासन के खिलाफ है। तीसरा गुट है, देश के भीतर सुधारवादी और लोकतांत्रिक ताकतें, जो मौजूदा मजहबी शासन को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार की मांग कर रही हैं।

भविष्य की महाशक्ति का उद्घोष

उज्ज्वल भविष्य की ओर एक मजबूत कदम

देश का दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के करीब पहुंचना सिर्फ एक आर्थिक उपलब्धि नहीं है, यह उज्ज्वल भविष्य की ओर एक मजबूत कदम है। यह भविष्य की महाशक्ति का उद्घोष है। आज दुनिया भारत को स्थिरता, अवसर और नवाचार के केंद्र के रूप में देख रही है। वैश्विक विश्लेषकों का मानना है कि भारत 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। यह यात्रा भारत के करोड़ों नागरिकों की सामूहिक आकांक्षाओं की जीत है, चाहे वे बेंगलुरु के स्टार्टअप हों, सूरत के बुनकर, पंजाब के किसान या हैदराबाद के इंजीनियर हों, हर भारतीय इस सफलता का सहभागी है।

भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के मुहाने पर पहुंच गया है। 4.186 ट्रिलियन (लाख करोड़) डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ भारत जापान जैसे विकसित देश को पीछे छोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। यह उपलब्धि मात्र आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों के संघर्ष, परिश्रम और सपनों की तस्वीर है। एक दशक पहले भारत कई आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन आज यह दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। जहां तमाम देश आज कई मोर्चों पर अनिश्चितता और आशंकाओं से जूझ रहे हैं, वहीं भारत मजबूत और स्थिर नेतृत्व में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हालांकि यह सफर आसान नहीं था, लेकिन मजबूत नेतृत्व, साहसी नीतियों और जनभागीदारी की बदौलत भारत ने यह मुकाम हासिल किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर चलते हुए मोदी सरकार ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ा। आर्थिक विकास का यह मॉडल केवल महानगरों या अमीर तबकों तक सीमित नहीं रहा।

2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब भारत दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। करीब दो ट्रिलियन डॉलर (लाख करोड़) की अर्थव्यवस्था और कई नीतिगत समस्याएं देश की गति को रोक रही थीं। अगले 10 वर्षों में भारत ने एक के बाद एक आर्थिक सुधारों और नीतिगत फैसलों के जरिये विकास की रफ्तार तेज कर दी। 2019 में भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर पांचवां स्थान प्राप्त किया और अब जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान पर पहुंचने को है। आईएमएफ और विश्व बैंक, दोनों ने इसकी पुष्टि की है। भारत की आर्थिक प्रगति के मूल में सुधारों की सशक्त नींव रही है। जीएसटी ने देश को एकीकृत बाजार में बदला, कर प्रणाली को सरल बनाया और राजस्व बढ़ाया। इन्साल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ने बैंकिंग क्षेत्र को मजबूती दी और ऋण प्रणाली में अनुशासन लाया। मेक इन इंडिया ने विनिर्माण को पुनर्जीवित किया और निवेशकों का भरोसा बहाल किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग 2014 में 142 से 2020 में 63 पर आ गई। इसने देश की आर्थिक सेहत सुधारने के साथ शासनतंत्र की मानसिकता भी बदली।

प्रधानमंत्री मोदी की डिजिटल इंडिया मुहिम ने देश के कोने-कोने को इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं से जोड़ा। इससे न सिर्फ सरकारी सेवाएं सुलभ हुईं, बल्कि डिजिटल भुगतान, स्टार्टअप और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिला। यूपीआई जैसी प्रणालियों ने डिजिटल भुगतान को इतना आसान बना दिया कि 2024 तक हर महीने 14 अरब से अधिक लेनदेन इससे हो रहे थे। जनधन योजना, आधार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने करोड़ों लोगों को वित्तीय प्रणाली से जोड़ा और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाई। इसके अलावा सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। भारतमाला, सागरमाला और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे प्रोजेक्ट्स के तहत सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और शहरी विकास पर अभूतपूर्व निवेश हुआ। 2014 से 2024 तक भारत में 80,000 किमी से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और हर घर जल जैसी योजनाओं ने गांवों और शहरों का कायाकल्प किया। इसके साथ ही उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के जरिये मोबाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और रक्षा उत्पादों के घरेलू निर्माण को जबरदस्त बढ़ावा मिला। इस सबके बीच भारत ने ग्लोबल बिजनेस में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाई। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कुल निर्यात (सामान और सेवाएं मिलाकर) 824.9 अरब डॉलर के रिकार्ड स्तर पर पहुंचा।

यह आईटी सेवाओं, फार्मा, रत्न एवं आभूषण, कपड़ा और इंजीनियरिंग उत्पादों में अभूतपूर्व वृद्धि का परिणाम है। भारतीय आईटी कंपनियों ने जहां दुनियाभर में धाक जमाई, वहीं दवाओं के सस्ते उत्पादन ने देश को दुनिया की फार्मेसी बनाया। कृषि उत्पादों के निर्यात और वैश्विक मांग में भी निरंतर वृद्धि हुई, जिससे भारत की वैश्विक छवि एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरी। जन-धन योजना के अंतर्गत 24 अगस्त, 2024 तक 53.13 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। उज्ज्वला योजना ने 11 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। आयुष्मान योजना से 50 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा मिली। ये योजनाएं इसका प्रमाण हैं कि भारत का विकास सशक्तिकरण और समानता के मूल्यों पर आधारित है। एक समय अमेरिका की सामरिक जरूरतों की पूर्ति सरकारी उद्यमों से होती थी। करीब 68 प्रतिशत नौसैनिक जहाज सरकारी यार्ड में बनते थे और प्रमुख रक्षा तकनीक मुख्यत: ब्रिटेन से आयात होती थी। 19वीं सदी के आखिरी वक्त में निजी कंपनियों के इस क्षेत्र में आगमन ने वहां रक्षा उत्पादन के पूरे समीकरण बदल डाले। इन कंपनियों ने आधुनिक तकनीक में निवेश बढ़ाकर, औद्योगिक लॉबी बनाकर रक्षा उत्पादन को नए आयाम दिए। प्रथम विश्व युद्ध के समय जब अमेरिका सैन्य महाशक्ति के रूप में स्थापित हुआ, तब निजी क्षेत्र उसकी रीढ़ बन चुका था। भारत में वाहन निर्माण से लेकर सॉफ्टवेयर क्षेत्र में उत्तरोत्तर बढ़ती ताकत में निजी क्षेत्र का अहम योगदान रहा है।

● रजनीकांत पारे

राजनीति को नई दिशा...

ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह देश में राजनीति हो रही थी, उसी बीच कुछ राजनेताओं को विदेशों में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भेजा गया था। उन नेताओं ने जिस तरह भारत की बात रखी, उससे देश की राजनीति को नई दिशा मिली है। क्योंकि अधिकतर नेता युवा थे।

यह सहज स्वाभाविक था कि पहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना की अकल्पनीय कार्रवाई पर विश्व के चुनिंदा देशों में भारत का पक्ष रखने गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करते। अतीत में भी विशेष अवसरों पर ऐसे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के कई देशों में गए हैं, लेकिन कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। दुर्भाग्य से इस बार ऐसा हुआ और सत्तापक्ष-विपक्ष में उस समय भी आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, जब प्रतिनिधिमंडल विदेश में थे। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो प्रतिनिधिमंडल में शामिल अपने दल के सांसदों के खिलाफ ही अभियान छेड़ दिया। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि तृणमूल कांग्रेस ने किस तरह अपने एक सांसद को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने से रोक दिया और विदेश गए एक भाजपा सांसद घरेलू राजनीति पर निगाह रखे रहे और राजनीतिक विरोधियों को जवाब देने में लगे रहे। वहीं विदेशों में सटीक एवं प्रभावी भारतीय पक्ष रखने के कारण शशि थरूर जहां असंख्य भारतीयों की वाहवाही लूट रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी में उनका भारी विरोध हो रहा है। **चर्चा एवं विवादों** में चल रहे शशि थरूर केरल के तिरुवंतपुरम से चार बार के कांग्रेस के सांसद हैं।

सिंदूर ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान दुनिया से सहानुभूति बटोरने के लिए जहां विश्व समुदाय में अनेक भ्रम, भ्रांतिया एवं भारत की छवि को छिछालेदार करने में जुटा है, वहीं भारत का डर दिखा-दिखा कर ही पाक अनेक देशों से आर्थिक मदद मांग रहा है। इन्हीं स्थितियों को देखते हुए दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने के लिए केंद्र सरकार ने जिस तरह से सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों का गठन किया है और इन दलों में विपक्षी दलों के सांसद एवं नेताओं ने भारत का पक्ष बिना आग्रह, दुराग्रह एवं पूर्वाग्रह के दुनिया के सामने रखा, उसकी जितनी सराहना की जाए, कम है। इन विपक्षी नेताओं ने विदेश में भारतीय राष्ट्रवाद को सशक्त एवं प्रभावी तरीकों से व्यक्त किया। देश ने इन नेताओं को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते और एक लय में आगे बढ़ते देखा, जबकि संसद में वे केवल आपस में लड़ते दिखाई देते थे। यह सराहनीय पहल भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि बनी है, जो भारत की भविष्य की राजनीति के भी नए संकेत दे रही है। क्योंकि इसने भारत में एक नए एवं सकारात्मक राजनीतिक नेतृत्व को उभरता हुआ दिखाया है। यूं तो सात दलों के सभी सदस्यों ने भरपूर तरीके से शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत का पक्ष रखकर दुनिया को भारत के पक्ष में करने की सार्थक पहल की है, लेकिन कांग्रेस के शशि थरूर एवं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी एक नए किरदार में नजर आए हैं। थरूर को लेकर कांग्रेस पार्टी में प्रारंभ से ही विरोध एवं विरोधाभास की स्थितियां बनी हुई थीं।

विदेशों में सटीक एवं प्रभावी भारतीय पक्ष रखने के कारण शशि थरूर जहां असंख्य भारतीयों की वाहवाही लूट रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी में उनका भारी विरोध हो रहा है। चर्चा एवं विवादों में चल रहे शशि थरूर केरल के तिरुवंतपुरम से चार बार के कांग्रेस के सांसद हैं। वे एक ऐसे कूटनीतिज्ञ राजनेता हैं, जो अपने राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन करना जानते हैं। वे एक ऐसे स्वतंत्र सोच एवं साहसी निर्णय लेने वाले नेता भी हैं जो अपनी पार्टी के रुख से अलग भी स्टैंड लेते रहे हैं। लेकिन ताजा संदर्भों में वे कांग्रेस के लिए अब असहज सच्चाई बन गए हैं। क्योंकि थरूर ने वह सबकुछ किया है जिसकी पार्टी में इजाजत नहीं है। प्रतिनिधि मंडल में थरूर के नाम पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी, क्योंकि कांग्रेस ने केंद्र को थरूर का नाम नहीं दिया था। थरूर ने कहा था- मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं, जब भी राष्ट्रीय हित की बात होगी और मेरी सेवाओं की जरूरत होगी, तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। थरूर

विदेश नीति पर दलगत राजनीति न हो

कम से कम अब तो पक्ष-विपक्ष की ओर से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में विदेश नीति पर दलगत राजनीति न हो और तब तो बिल्कुल भी नहीं, जब विश्व समुदाय को यह संदेश देना आवश्यक हो कि भारत के राजनीतिक दल राष्ट्रहित के मामले में दलगत हित से परे हटकर एक सुर में अपनी बात कहते हैं। अपने यहां तो यह मान्यता रही है कि विदेश नीति सत्ताधारी दल की नहीं, देश की होती है। विदेश नीति से जुड़े किसी मसले पर विभिन्न दलों के बीच असहमति हो सकती है, लेकिन उसका प्रकटीकरण इस तरह नहीं होना चाहिए कि भारत विरोधी ताकतें उसका लाभ उठाने में सफल रहें। हाल के समय में ऐसा हुआ है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने के फैसले और डोकलाम विवाद के समय हमारे कुछ नेताओं के बयान ऐसे रहे, जिन्हें कभी पाकिस्तान या चीन ने अपने पक्ष में भुनाया।

सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आम सहमति जरूरी

सच तो यह है कि रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीति के साथ राष्ट्रीय हित के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच इस पर आम सहमति कायम होनी चाहिए कि उन पर राजनीतिक वर्ग की साझा नीति क्या हो। यदि न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन और जीएसटी लागू करने संबंधी मामलों को छोड़ दिया जाए तो अन्य किसी विषय पर पक्ष-विपक्ष के बीच आम सहमति मुश्किल से ही देखने को मिली है। इन दिनों भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की पहल आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल तो आसार इसी के हैं कि इस प्रस्ताव पर पक्ष-विपक्ष की राय एक जैसी होगी, लेकिन यह ध्यान रहे कि अतीत में ऐसे प्रस्ताव कभी सफल नहीं हो सके, क्योंकि कभी क्षेत्रवाद की राजनीति आड़े आ गई और कभी जाति की राजनीति।

ने कांग्रेस छोड़ने की अटकलों के सवाल पर कहा- जब आप देश की सेवा कर रहे हों, तब ऐसी चीजों की ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारे राजनीतिक मतभेद भारत के बॉर्डर के बाहर जाते ही खत्म हो जाते हैं। सीमा पार करते ही हम पहले भारतीय होते हैं। थरूर इन दिनों अमेरिकी सहित कई देशों के दौरे पर हैं, जहां वे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बने मल्टी पार्टी **डेलीगेशन** को सुपर लीड कर रहे हैं। सरकार के समर्थन में बोलने पर कांग्रेस के अनेक नेता थरूर की खिंचाई करने में जुटे हैं। उन्हीं में एक नेता उदित राज ने थरूर को भाजपा का सुपर प्रवक्ता तक बता दिया है। जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और सत्तारूढ़ भाजपा पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान युद्धविराम को लेकर लगातार हमलावर हैं।

4 जून 2025 को राहुल गांधी ने तब हद ही कर दी जब उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आत्मसमर्पण कर दिया। इतना ही नहीं ये सब कहने का अंदाज भी उनका इतना खराब था कि जैसे कोई दुश्मन देश का बंदा बोल रहा हो। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि, मैं भाजपा और आरएसएस वालों को अच्छे से जान गया हूं, इनको थोड़ा सा दबाओ तो डरकर भाग जाते हैं। राहुल ने आगे कहा, उधर से ट्रंप ने फोन किया और इशारा किया कि मोदीजी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर और जी हुजूर करके मोदीजी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी के इस भ्रामक एवं गुमराह करने वाले बयान का थरूर ने जोरदार तरीके से जबाव दिया एवं कांग्रेस पार्टी को ही घेरा। राष्ट्रपति ट्रंप की भारत-पाक के बीच मध्यस्थता के बयान पर थरूर बोले- मैं यहां किसी विवाद को हवा देने नहीं आया हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति का सम्मान है। हमें नहीं पता उन्होंने पाकिस्तान से क्या कहा, पर हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं थी।

आग्रह-दुराग्रह से ग्रसित होकर कांग्रेस के नेता एक-दूसरे को नीचा दिखाने की ही बातें कर रहे हैं, इन कांग्रेसी नेताओं में दायित्व की गरिमा और गंभीरता समाप्त हो गई है। राष्ट्रीय समस्याएं और विकास के लिए खुले दिमाग से सोच की परंपरा उनमें बन ही नहीं रही है। जब मानसिकता दुराग्रहित है तो दुष्प्रचार ही होता है। कोई आदर्श संदेश राष्ट्र को नहीं दिया जा सकता। राष्ट्र-विरोधी राजनीति एवं सत्ता-लोलुपता की नकारात्मक राजनीति हमें सदैव ही उल्ट धारणा (विपथगामी) की ओर ले जाती है। ऐसी राजनीति राष्ट्र के मुद्दों को विकृत कर उन्हें अतिवादी दुराग्रहों में परिवर्तित कर देती है। राहुल गांधी एवं कांग्रेस ने राष्ट्रीय संकट में भी यही सब करके आम जनता से अधिक दूरियां बना ली हैं। शशि थरूर ने तो बड़ी लकीरें खींच दी, कांग्रेस कब ऐसी **लकीरें खींचने** की पात्रता विकसित करेगी? हर राजनीतिक दल को कई बार अग्नि स्नान करता पड़ता है, पर आज कांग्रेस तो कीचड़ स्नान कर रहा है। जहां तक कांग्रेस नेताओं का सवाल है, एक और निहित संदेश सामने आया कि सिर्फ गांधी परिवार ही कांग्रेस का नेतृत्व नहीं कर सकता जबकि भारत की सबसे पुरानी पार्टी में अभी भी प्रतिभाओं का खजाना है, उसके पास अनुभवी नेता हैं, जो जटिल मुद्दों को समझने और नेतृत्व देने में सक्षम हैं।

बड़ी लकीरें तो प्रतिनिधि मंडल में गए अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी खींची है। जिनमें एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विश्व की राजधानियों में भारत की स्थिति और मौजूदा विकास को भी रेखांकित किया है। ओवैसी, जो भारत के अल्पसंख्यकों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी भाषा में आड़े हाथों लिया। यहां तक कि उन्होंने पाकिस्तान द्वारा जारी की गई फर्जी तस्वीरों का जिक्र करते हुए कहा कि नकल के लिए भी अकल चाहिए! ओवैसी की राष्ट्रवादी सोच तो समय-समय पर सामने आती रही है। इस तरह मुस्लिम नेतृत्व अगर उदारता दिखाता है तो देश के करोड़ों मुसलमानों के प्रति एक विश्वास और भाईचारे की भावना बढ़ती है। ओवैसी ने तो सबकी निगाहें अपनी ओर खींच ली थीं। इसी तरह डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने अपनी तल्ख और चतुराई भरे अंदाज से भारतीयों एवं दुनिया का दिल जीत लिया है। सांसद कनिमोझी ने स्पेन में अपने हिस्से का पक्ष रखते हुए भारत की राष्ट्रीय भाषा **एकता और विविधता** का जिक्र कर ऐसी बात कही है जिसके बाद वो जमकर वाहवाही लूट रही हैं। कनिमोझी ने इसके साथ ही कहा कि हमारे अपने मुद्दे हो सकते हैं, अलग-अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, संसद में हमारे बीच तीखी बहस हो सकती है, लेकिन जब भारत की बात आती है, तो हम एक साथ खड़े होते हैं, यही संदेश हम लेकर आए हैं। उनकी ये बातें इसलिए भी खास हैं क्योंकि जहां एक ओर उनकी पार्टी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित त्रि-भाषा नीति को चुनौती देते हुए गैर-हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने की बात कर रही है। वहीं कनिमोझी एकता और विविधता को राष्ट्रीय भाषा बताते हुए अपना पक्ष रख रही हैं। डीएमके सांसद का ये अंदाज सुर्खियों का विषय बना है और लोग जमकर इसकी तारीफ कर रहे हैं।

इसी तरह शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी ने भारत को न केवल बुद्ध और गांधी, बल्कि श्रीकृष्ण की भूमि भी बताया, जिन्होंने पांडवों से आग्रह किया था कि धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक हो तो युद्ध करने से न हिचकिचाएं। अब यह देखना बाकी है कि क्या सरकार ऐसे और कूटनीतिक प्रयासों में विपक्षी नेताओं का इस्तेमाल करना जारी रखेगी।

● **विपिन कंधारी**

2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी, तभी उन्होंने कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए उन्होंने देश की जनता पर कई टैक्स के भार भी डाले। जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। वहीं भारत अपने कई उत्पादन का विश्वभर में निर्यात कर रहा है। जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो रही है।

आत्मनिर्भर भारत

हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी 11 वर्ष की विकास गाथा को 176 पेज की एक पुस्तिका में लिखकर जारी करने का कार्य किया है। जिसमें मोदी सरकार ने देश की दशा व दिशा बदलने की प्रमुख योजनाओं का जिक्र किया है। हमारे प्यारे देश भारत के आम जनमानस के साथ-साथ दुनियाभर के लोगों के बीच में नरेंद्र मोदी की छवि एक ऐसे सख्त प्रशासक, कुशल राजनेता की बन गई है, जिसके लिए देशहित सर्वोपरि है, इस छवि के दम पर ही नरेंद्र मोदी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं और मोदी के **नेतृत्व** में चल रही केंद्र सरकार को 9 जून 2025 को 11 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। अपने इस 11 वर्ष के कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बहुत सारे ऐसे कार्य करके दिखाएं हैं, जिन्होंने इतिहास रचने का कार्य कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने बिना किसी के जोर दवाब में आए ऐतिहासिक कार्यों को अमलीजामा पहनाने का कार्य बखूबी करके दिखाया है। जिसके चलते ही देश-दुनिया में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की गिनती कुछ करके दिखाने वाली सरकार के रूप में होती है।

वैसे भी देखा जाए तो जिस वक्त नरेंद्र मोदी ने गुजरात से आकर 26 मई 2014 को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस वक्त देश व दुनिया के बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल **बार-बार कोंध** रहा था कि आखिरकार लोकसभा के चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भारत को सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित नव भारत के निर्माण करने का सपना आम जनमानस को दिखाया है, क्या यह सपना कभी पूरा हो पाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी इस सपने को धरातल पर उतारने के लिए अपने प्रथम कार्यकाल 26 मई 2014 से ही निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते ही देश के आम जनमानस ने मोदी के नेतृत्व में दूसरी व तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर दिया था और मोदी ने 30 मई 2019 को दूसरी बार व 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। आम जनता की अदालत में 11 वर्ष बीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश के अन्य सभी राजनेताओं पर भारी है। आम व **खास दोनों वर्गों** के लोग नरेंद्र मोदी के विजन व नीति से अभी भी प्रभावित नजर आते हैं।

हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी 11 वर्ष की विकास गाथा को 176 पेज की एक पुस्तिका में लिखकर जारी करने का कार्य किया है। जिसमें मोदी सरकार ने देश की दशा व दिशा बदलने की प्रमुख योजनाओं का जिक्र किया है। इसमें नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल को सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण के 11 वर्ष बताते हुए कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर के, सामाजिक न्याय की योजनाएं, वंचितों की सेवा की योजनाएं, महिलाओं को सशक्त बनाने की योजनाएं, किसानों को उनका हक दिलाने की योजनाएं, देश के भविष्य युवाओं को अवसर देने की योजनाएं, देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को अमलीजामा पहनाया गया, जिनका ब्यौरा इस पुस्तिका में दिया गया है।

वैसे मोदी सरकार के कुछ कार्यों को देखें तो देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए मोदी सरकार ने बहुत काम किया है, मोदी सरकार ने देश के कुछ हिस्सों में दशकों से बेखौफ होकर के अपना राज चला रहे नक्सलियों की कमर तोड़ने का कार्य किया, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम लगाने का कार्य किया है। आतंकियों के खिलाफ सीमा

मोदी युग में सांस्कृतिक पुनर्जागरण

2014 में शुरू से ही यह स्पष्ट था कि मोदी सरकार के तहत संस्कृति अब सजावटी नहीं रहेगी, बल्कि यह मूलभूत होगी। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था। अब दुनियाभर में लाखों लोगों को एक प्राचीन भारतीय परंपरा का जश्न मनाते देखा जा रहा है, जो शरीर, मन और आत्मा को आपस में जोड़ता है। जनवरी 2024 में, जब पावन नगरी अयोध्या में सूर्योदय हुआ। सदियों से लुप्त हो चुकी प्रार्थना अब आखिरकार गुंजायमान होने लगी थी। श्रीराम की अपने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महज एक धार्मिक उपलब्धि नहीं थी। यह सभ्यता के उद्धार का क्षण था। सदियों के आक्रमण, औपनिवेशिक विकृति और राजनीतिक देरी के बाद, मंत्रों से गूंजता हुआ और इतिहास के स्पंदन सहित बलुआ पत्थर में उकेरा गया यह मंदिर शान से खड़ा था। यह सिर्फ वास्तुकला के बारे में नहीं था, यह एक घायल आत्मा के उपचार के बारे में था। श्रीराम की अपनी जन्मभूमि पर वापसी ने उस राष्ट्र की आस्था को फिर से जागृत कर दिया, जिसने लंबे समय तक अपने दिल में निर्वासन की खामोशी को समेटे रखा था। कुछ महीने पहले, भारत की प्राचीन आस्था का एक और प्रतीक चुपचाप अपने सही स्थान पर लौट आया। नई संसद के उद्घाटन के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को स्थापित किया। यह एक पवित्र राजदंड है, जिसे 1947 में तमिल अधीनमों ने सत्ता के धार्मिक हस्तांतरण को चिह्नित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू को भेंट किया था। दशकों से, इसे भुला दिया गया था, समुचित स्थान से वंचित किया गया, और एक प्रचलित राजदंड के तौर पर खारिज कर दिया गया था। इसकी स्थापना केवल स्मरण का कार्य नहीं था, यह एक शक्तिशाली घोषणा थी कि भारत अब खुद को उधार की आंखों से नहीं देखेगा।

पार पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक व ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। अनुच्छेद-370 को समाप्त करके जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को उनका हक दिया है। देश में जातिगत जनगणना कराने के निर्णय, दशकों से लंबित महिला आरक्षण बिल आदि को मोदी सरकार के ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार मुख्य रूप से 14 बिंदुओं पर कार्य कर रही है, इसमें देश में गरीबों की सेवा वंचितों का सम्मान, किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना, नारी शक्ति को मिला नया बल, भारत की अमृत पीढ़ी हो रही सशक्त, मध्यवर्ग का जीवन हुआ आसान, सभी के लिए सस्ती व सुलभ स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्र प्रथम विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाना, इज ऑफ डूइंग बिजनेस से कारोबार को लगे पंख, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से हो रहा बेहतर, टेक्नोलॉजी से भारत को नई शक्ति, नॉर्थ ईस्ट बन रहा विकास का नया इंजन, विरासत व विकास, पर्यावरण एवं सतत विकास हैं। मोदी सरकार का लक्ष्य भारत को दुनिया की एक ताकतवर आर्थिक महाशक्ति बनाने का है, जिसके लिए वह निरंतर कार्य कर रही है और उन कार्यों के दम से ही भारत आज विश्व में चौथे पायदान पर आ चुका है। मोदी सरकार का लक्ष्य है- देश से गरीबी को खत्म करना। हाल ही में प्रकाशित विश्वबैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में अत्यधिक गरीबी में कमी आई है, मोदी सरकार के प्रयासों से गरीबी रेखा से 27 करोड़ लोग पिछले 11 वर्ष में बाहर हुए हैं। मोदी सरकार सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर व विकसित भारत का निर्माण करने के लिए देश में सर्वांगीण विकास पर जोर दे रही है। किसानों, महिला, युवाओं व सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र व इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।

मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आदि ने देश में धरातल पर बड़ा सकारात्मक बदलाव करने का कार्य किया है। मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, डिजिटल क्रांति, मेक इन इंडिया, जन औषधि केंद्र, फसल के एमएसपी के द्वारा किसानों की आय की गारंटी, मखाना बोर्ड, जनजातियों का सशक्तिकरण-ग्राम समृद्धि, दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन चलाना, पीएम धन-धान्य कृषि योजना, ग्रामीण विद्युत आपूर्ति, किफायती यूरिया, भारत को पंख (उड़ान 2.0 की उड़ान और तेज हुई), विमानन क्षेत्र में नया युग, कश्मीर घाटी में वंदे भारत जम्मू-श्रीनगर रेल लाइन, चिनाब नदी पर विश्व का अजूबा रेलवे ब्रिज, विमानन क्षेत्र में एक नया युग, साइबर सुरक्षित भारत और आधार आईटी, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री ई-ड्राइव आदि ने देशवासियों का जीवन बेहतर करने का कार्य किया है। मोदी सरकार के मिशन चंद्रयान ने दुनिया में भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में डंका बजाने का कार्य किया है।

मोदी सरकार ने देश में सर्वांगीण विकास को तरजीह देते हुए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर भारी-भरकम रकम खर्च की है। देश में हाईवे व एक्सप्रेस-वे का विश्वस्तरीय जाल बना देना मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश में बहुत सारे छोटे व बड़े एयरपोर्टों का निर्माण करके मोदी सरकार ने पूरे देश को चंद घंटों में जोड़ने का कार्य कर दिखाया है। रेलवे स्टेशन से लेकर के रेलवे नेटवर्क के विकास व आधुनिकीकरण का कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा है, जो अच्छा संकेत हैं। देश में धार्मिक पर्यटन को नए आयाम देते हुए मोदी सरकार ने बहुत कार्य किए हैं, भव्य राम मंदिर का निर्माण, काशी-विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर इसकी एक कहानी है। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी, नया संसद भवन, भारत मंडपम्, वॉर मेमोरियल का निर्माण मोदी सरकार उपलब्धि है। मोदी सरकार में सौर ऊर्जा पर बड़े पैमाने पर कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से मोदी सरकार में देश में विकास के नित-नए आयाम स्थापित होते हुए धरातल पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं।

● इन्द्र कुमार

अर्थव्यवस्था हो रही मजबूत

आर्थिक रूप से शक्तिशाली देशों की सूची में भारत जहां वर्ष 2014 में 10वें स्थान पर था, वह अब 2025 में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। हमारी अर्थव्यवस्था अब उछलकर विश्व के चौथे स्थान पर जा पहुंची है। कहने का तात्पर्य यह कि जिस ब्रिटेन ने दुनियाभर पर राज्य किया, वह तो कब का भारत से पिछड़ गया, वहीं अब धनकुबेर जापान को भी भारत ने पछाड़ दिया है और अपनी हठधर्मिता से दुनिया को दो विश्व युद्ध की सौगात देने वाले और तीसरे संभावित विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले जर्मनी को आर्थिक चकमा देकर भारत कब दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा और फिर अमेरिका-चीन से आर्थिक होड़ शुरू कर देगा, इसमें ज्यादा अवधि नहीं बची है! क्या यह देशवासियों के खुश होने का वक्त नहीं है? आंकड़े बताते हैं कि 1947 में आजादी मिलने के बाद साल 2014 तक यानी लगभग 70 वर्षों में देश महज 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी ही बना पाया था। ऐसा इसलिए कि हमारी सरकारें विदेशियों के मुंह पोछते रहने की आत्मघाती नीतियों पर चल रही थीं। वहीं, राष्ट्रवादी सरकार की चौथी से छठी पारी के बीच यानी 11 साल बाद भारतीय अर्थव्यवस्था 4.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुकी है। अब भारत का तात्कालिक लक्ष्य तीसरे स्थान पर चल रहे जर्मनी को पछाड़कर 2028 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है। मतलब साफ है कि एक विकासशील देश से विकसित देश बनने को आतुर भारत का अगला शिकार जर्मनी होगा। तब भारत की अर्थव्यवस्था से आगे सिर्फ चीन और अमेरिका रह जाएंगे, जो हमसे पिछले कई दशकों से मजबूत प्रतिद्वंद्विता करते आए हैं।

नक्सलवाद की जड़ पर चोट

छत्तीसगढ़ में माओवाद विरोधी केंद्रीय बलों के अभियान में 21 मई को कुछ खास उपलब्धि का दिन था। तभी तो उस दिन मुठभेड़ में मारे गए 70 वर्षीय माओवादी नेता नंबल्ला केशव राव उर्फ बसवराजू की खबर खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा, आज छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में हमारे सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार माओवादियों को मार गिराया है, जिनमें सीपीआई-माओवादी के महासचिव, शीर्ष नेता तथा नक्सल आंदोलन की रीढ़ नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू भी है। मैं नक्सलवाद के खिलाफ देश की लड़ाई के तीन दशकों में पहली बार इस बड़ी सफलता के लिए हमारे बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों की सराहना करता हूं। उग्र वामपंथ और माओवाद की चुनौती से निपटने के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों का अभियान कुछ साल से छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में जारी है। इस दौरान कथित तौर पर 54 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है और 84 ने आत्मसमर्पण किया है। शाह का दावा है कि मोदी सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद के खात्मे के लिए दृढ़ संकल्प है।

सरकार ने बहुआयामी रणनीति अपनाई

वामपंथी उग्रवादी हिंसा की घटनाएं 2010 में 1936 के साथ अपने उच्चतम स्तर पर थीं, 2024 में घटकर 374 रह गईं। उनमें लगभग 81 प्रतिशत की कमी आई। इस अवधि के दौरान कुल मौतों (आम लोगों और सुरक्षा बलों) की संख्या भी 85 प्रतिशत घटकर 2010 में 1005 से 2024 में 150 रह गई है। सरकार ने माओवादी हिंसा से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। सरकार ने शून्य सहनशीलता नीति के साथ कानून का राज स्थापित करने तथा गैर-कानूनी हिंसक गतिविधियां रोकने की नीति पर काम करना शुरू किया है।

तो, क्या वाकई बसवराजू की मौत छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड और ओडिशा के लाल गलियारे में माओवादी चुनौती से निपटने में अहम है? बेशक, यह छोटी घटना नहीं है। लेकिन 70 साल के बसवराजू अब बूढ़े हो चले थे और संघर्ष की ताकत घट गई थी। श्रीकाकुलम जिले के जियन्नापेटा गांव के बसवराजू नवंबर 2018 से सीपीआई माओवादी के महासचिव बने। पिछले 35 साल से माओवादी संगठन की केंद्रीय कमेटी के सदस्य बसवराजू पर करीब डेढ़ करोड़ रुपए का ईनाम घोषित था। अपने साथ हमेशा एके 47 रायफल रखने वाले बसवराजू का छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के इलाके में बहुत दबदबा था। 24 साल से पोलित ब्यूरो सदस्य के तौर पर सक्रिय बसवराजू वारंगल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सीपीआई माओवादी के साथ जुड़ गए थे। बसवराजू को छापामार युद्ध और सुरक्षा बलों को चकमा देने में महारत हासिल थी। उन्होंने संगठन में ज्यादातर समय हथियारबंद कमान का संचालन किया। उन्हें आक्रामक हमलों के लिए जाना जाता था। कहते हैं, बसवराजू ने ही 25 मई 2013 में हुए झीरम घाटी हत्याकांड की योजना रची थी, जिसमें कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल, छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा वगैरह मारे गए थे। उसमें कुल 33 लोगों की घात लगाकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। 60 और 70 के दशक में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से उभरा उग्र अतिवामपंथ का आंदोलन पिछले तीन-चार दशक में आदिवासी लाल गलियारे में सिमट आया। मोटे तौर पर आदिवासियों की लड़ाई ही उसका हथियार बन गया। उनकी हिंसक कार्रवाईयों की वजह से आदिवासी बहुल इस इलाके को लाल गलियारा कहा जाने लगा। इसका विस्तार झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मप्र तक रहा है। ये क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से वंचित रहे हैं। इसलिए पशुपति (नेपाल) से लेकर तिरुपति तक लाल गलियारा कानून-व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। एक समय ऐसा आया कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मप्र, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना का बड़ा हिस्सा इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ।

दरअसल उग्र वामपंथ का इतिहास देश में कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई। कम्युनिस्ट पार्टी को तेभागा 1946 (बंगाल) और तेलंगाना 1945 (आंध्र प्रदेश) के किसान आंदोलनों से ख्याति और शक्ति प्राप्त हुई। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्य के स्वरूप को लेकर भी कम्युनिस्ट पार्टी में मतभेद रहे। स्वतंत्रता के बाद यह समस्या खड़ी हुई की कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक संवैधानिक मार्ग पर चलेगी या वह हिंसा की कथित क्रांतिकारी राह अपनाएगी। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने संवैधानिक लोकतंत्र का मार्ग चुना जिससे कम्युनिस्ट पार्टी के उग्रपंथी कार्यकर्ता हतोत्साहित और दिग्भ्रमित हुए। 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण पर भी कम्युनिस्ट पार्टी में टकराव हुआ। उग्रपंथी धड़े चीन की लाइन के समर्थक थे। इसलिए भारत में हथियारबंद कम्युनिस्ट धड़े खुद को माओ और चीन से जोड़ते रहे। 1964 में भाकपा का विभाजन हो गया और माकपा का जन्म हुआ।

फिर, माकपा से टूटकर भाकपा (मार्क्सवादी लेनिनवादी) का गठन वर्ग संघर्ष की धारणा के साथ हुआ। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में 24 मई 1967 को जांच करने पहुंचे एक पुलिस दल पर हुए हिंसक हमले में एक पुलिस अधिकारी की मृत्यु हो गई। अगले दिन पुलिस की कृषक सभा पर चलाई गई गोली से 11 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय ने इस आंदोलन को कुचल दिया। लेकिन 1969 में चारू मजूमदार और कानू सान्याल सहित उनके साथियों ने माकपा से अलग होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) का गठन किया। चारु मजूमदार की वर्ग शत्रुओं के सफाई की रणनीति से काफी खून खराबा हुआ। बांग्लादेश के गठन के बाद केंद्र सरकार का ध्यान पैर पसार रहे नक्सलवाद की ओर गया। जुलाई 16, 1972 को चारू मजूमदार को कोलकाता के उनके भूमिगत ठिकाने से पकड़ लिया गया और 28 जुलाई को पुलिस हिरासत में ही उनकी मौत हो गई। आगे चलकर सीपीआई-एमएल विभिन्न गुटों में बंट गई। धीरे-धीरे ये लगभग 40 छोटे-छोटे गुट विभिन्न क्षेत्रों में काम करने लगे। 22 अप्रैल 1980 को कोंडपल्ली सीतारामैया ने पीपुल्स वार ग्रुप (पीजीडब्ल्यू) की स्थापना की।

● रायपुर से टीपी सिंह

महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले सियासी समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। शिवसेना यूबीटी और मनसे के साथ आने की चर्चा भी सियासी गलियारों में जमकर चल रही है। गठबंधन को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। ठाकरे बंधुओं के गठबंधन की चर्चा इसलिए हो रही है कि फिल्म अभिनेता महेश मांजरेकर ने राज ठाकरे का इंटरव्यू लिया था। इस इंटरव्यू में राज से मनसे-शिवसेना गठबंधन के बारे में पूछा गया था। इसका जवाब देते हुए राज ने कहा था, मुझे साथ आना मुश्किल नहीं लगता।

हमारे विवाद और झगड़े महाराष्ट्र के मराठी लोगों के अस्तित्व के लिए बहुत छोटे हैं। इसके बाद से ही इस गठबंधन की चर्चा शुरू हो गई थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे छोटे-मोटे विवादों को किनारे रखने के लिए तैयार हैं और महाराष्ट्र की जनता जो चाहेगी, वही होगा। इसके चलते इस गठबंधन की चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया। इसके बाद दोनों दलों के नेताओं के कार्यक्रमों में कुछ बैठकें भी हुईं। हालांकि, गठबंधन पर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उधर, गत दिनों महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मनसे के प्रमुख राज ठाकरे के बीच मुलाकात हुई है। जहां एक तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच गठबंधन होने की अटकलें तेज थीं। वहीं, आगामी नगर निगम चुनावों के बीच हुई यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है।

महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से मनसे और ठाकरे गुट के बीच गठबंधन की चर्चा चल रही है। खास बात यह है कि दोनों ही दलों के नेताओं ने इस गठबंधन को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बीच मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद काफी सारे कयास लगाए जा रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित ताज लैंड होटल में हुई। यह मुलाकात इसीलिए और भी ज्यादा महत्व रखती है क्योंकि यह आगामी नगर निगम चुनावों से पहले हुई है। हालांकि, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच गठबंधन की चर्चाएं तेज थीं। वहीं, इसी बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच बांद्रा के एक होटल में बैठक हुई। जिससे अब सियासी पारा बढ़ गया है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा कि दोनों नेता अच्छे दोस्त हैं और हो सकता है कि उन्होंने राज्य से संबंधित विकास के मुद्दों पर चर्चा के लिए मुलाकात की हो। महाराष्ट्र सरकार ने इस हफ्ते मुंबई सहित 29 नगर निगमों के लिए वार्ड परिसीमन के आदेश जारी करके स्थानीय निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू की है।

जहां राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक हुई है। वहीं, इससे कुछ दिन पहले तक इस तरह की अटकलें लगाई जा रहीं थी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर साथ आ सकते हैं। लेकिन अब राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणीस से मुलाकात की है। एक समय महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार का अघोषित राज था। लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार हाशिए पर आ गया है। जहां लग रहा था कि ठाकरे परिवार एक साथ आ जाएगा वहीं अब इन अटकलों पर विराम लगता दिखाई दे रहा है। शिवसेना में दो दल बन चुके हैं और उद्धव ठाकरे सत्ता से बाहर हैं। उधर, राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को पिछले कुछ चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में कयास लग रहे थे कि दोनों ठाकरे बद्रर्स फिर साथ आ सकते हैं, इन संकेतों को लेकर मुंबई के गिरगांव इलाके में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के संभावित गठबंधन को लेकर पोस्टर लगाए गए थे। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात के क्या नतीजे सामने आएंगे यह देखना होगा। हालांकि, दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई यह सामने नहीं आया है। चुनाव से पहले दोनों ठाकरे भाई के बीच संभावित सुलह की अटकलें लगाई जा रही हैं। राज ठाकरे ने कहा है कि मराठी माणूस (मराठी भाषी लोगों) के हित में एकजुट होना मुश्किल नहीं है, उधर उद्धव ठाकरे ने जोर देकर कहा है कि वो तुच्छ झगड़ों को दूर करने के लिए तैयार हैं। राज ठाकरे ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन दिया था, लेकिन उनकी पार्टी ने पिछले साल नवंबर में राज्य विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ा।

वहीं शिवसेना (उद्धव ठाकरे) गुट के विधायक आदित्य ठाकरे का कहना है कि राज्य में बहुत अत्याचार हो रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं बदलाव लाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आदित्य ठाकरे ने यह सुझाव दिया है कि महाराष्ट्र के हित के लिए लड़ने वाली पार्टियों को एक साथ आकर लड़ना जरूरी है। शिवसैनिकों के मन में कोई भ्रम नहीं है। उनके सैनिक भी हमारे संपर्क में हैं। दोनों सैनिकों के बीच कोई भ्रम नहीं है। ठाकरे बंधुओं के गठबंधन की चर्चा पर ठाकरे गुट की नेता किशोरी पेडनेकर ने स्पष्ट किया है कि हम अपनी तरफ से इस गठबंधन के लिए सकारात्मक हैं। 2022 में, महाराष्ट्र राजनीतिक कीचड़ में फंस गया। इससे नागरिकों और सभी को परेशानी हो रही है, क्योंकि प्रवासियों का दबदबा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे से लेकर हम तक, ऐसे सभी लोग इस गठबंधन के लिए सकारात्मक हैं। संजय राउत ने कहा है कि हम अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते। अगर हम पीछे देखेंगे तो हमें कीचड़ ही दिखेगा। इसलिए, आइए पीछे न देखें, आइए आगे देखें, उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि ठाकरे समूह मनसे के साथ गठबंधन के लिए सकारात्मक हैं।

● **बिन्दु माथुर**

ठाकरे-पवार ब्रांड को खत्म करने की कोशिश

महाराष्ट्र की राजनीति अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की सियासत से ठाकरे और पवार ब्रांड को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी इस ब्रांड को मिटाया नहीं जा सकता। पुणे में एक आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज ठाकरे ने महाराष्ट्र और देश की राजनीति में पवार और ठाकरे उपनामों की प्रासंगिकता के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ठाकरे-पवार ब्रांड को खत्म करने का प्रयास हो रहा है लेकिन यह खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जहां तक ठाकरे ब्रांड का सवाल है तो मेरे दादा प्रभोदनकर ठाकरे ने महाराष्ट्र पर पहला बड़ा प्रभाव डाला। उनके बाद बालासाहेब ठाकरे और फिर मेरे पिता संगीतकार श्रीकांत ठाकरे ने अपनी छाप छोड़ी उसके बाद उद्धव और मैंने भी अपना प्रभाव साबित किया। मनसे चीफ ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि इन ब्रांड्स को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन्हें आसानी से मिटाया नहीं जा सकेगा।

राजस्थान में कांग्रेस की सियासत नई करवट लेती नजर आ रही है, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की सियासी दूरियां मिटती नजर आ रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक मंच पर साथ दिखे। चार दिन में दूसरी बार पायलट-गहलोत की मुलाकात हुई है। इस तरह से पायलट-गहलोत की सियासी केमिस्ट्री बनी रही तो राजस्थान में भाजपा के लिए सियासी टेंशन बढ़ सकती है?

राजेश पायलट की पुण्यतिथि ही नहीं है बल्कि इस मौके पर दौसा में आयोजित सर्वधर्म सभा में शामिल होने वाले कांग्रेस नेताओं की फेहरिस्त रही है। इस धर्मसभा में पूरी राजस्थान कांग्रेस शामिल हुई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस की राजनीति के दो सिरे माने जाते हैं। दोनों की सियासी अदावत के चलते ही कांग्रेस को 2023 में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब दो साल के बाद पायलट-गहलोत सारे गिले-शिकवे भुलाकर फिर साथ आ गए हैं। राजस्थान में सियासत में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की अदावत किसी से छिपी नहीं है। 2018 में कांग्रेस के सत्ता में वापसी करने के साथ ही उनके बीच दूरियां बढ़ गई जब कांग्रेस पांच साल बाद फिर से सत्ता में लौटी। मुख्यमंत्री की कुर्सी की सियासी रस्साकशी में सियासी बाजी अशोक गहलोत के हाथ लगी और सचिन पायलट को उपमुख्यमंत्री की कुर्सी से संतोष करना पड़ा, लेकिन ढाई साल सरकार चलने के बाद फिर से दोनों ही नेताओं के बीच सियासी तलवार खिंच गई थी।

सचिन पायलट को कांग्रेस के 20 विधायकों को लेकर मानेसर में डेरा डालना पड़ा था, उस समय गहलोत सरकार पर खतरा मंडराने लगा था। ऐसे में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बीच में आना पड़ा और पायलट को बागी तेवर छोड़ने पड़े। इसके बाद से दोनों ही नेताओं के बीच सियासी रिश्ते सुधरे नहीं और दोनों ही एक-दूसरे को शह-मात देने में जुटे रहे। राजस्थान चुनाव से ठीक पहले पायलट का गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना कांग्रेस को महंगा पड़ा। कांग्रेस की वापसी नहीं हो सकी, जिसका ठीकरा गहलोत ने पायलट पर फोड़ा था। इसके बाद से दोनों नेताओं के रिश्ते बिगड़े ही रहे, लेकिन अब दो साल के बाद फिर से रिश्ते पटरी पर आते दिख रहे हैं। सचिन पायलट ने अपने पिता राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर होने वाले कार्यक्रम के लिए पिछले दिनों अशोक गहलोत से मुलाकात कर उनसे इसमें शामिल होने का आग्रह किया था। पायलट ने गहलोत से मुलाकात की तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर साझा की थी। गहलोत ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर सधे अंदाज में सादगी से जवाब दिया है। सचिन पायलट ने इस मौके पर कहा कि मैंने अशोक गहलोत को बुलाया और अच्छा लगा कि वे आए। हम सभी एक परिवार हैं और मतभेद मिल-बैठकर सुलझाए जाते हैं। सचिन पायलट ने कांग्रेस में एकजुटता की बात कही और राहुल गांधी के 50 फीसदी पद युवाओं को देने के वादे को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि अब अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर देखना चाहिए और जनता का विश्वास जीतना सबसे जरूरी है। वहीं, राजेश पायलट के साथ बिताए पलों को याद करते हुए गहलोत ने कहा कि आज की राजनीति में भी उनके सिद्धांत और विचार प्रासंगिक हैं। सचिन पायलट के साथ संबंधों पर गहलोत ने कहा कि मैं और पायलट कब अलग थे, हम तो हमेशा से साथ हैं और हम दोनों में खूब मोहब्बत है। ये मीडिया ही चलाता रहता है कि दोनों में अनबन है।

दिलचस्प बात यह रही कि दौसा में प्रार्थना सभा से प्रदर्शनी की ओर जाते समय अशोक गहलोत भीड़ में पीछे रह गए तो सचिन पायलट ने उनका इंतजार किया और हाथ पकड़कर उन्हें भीड़ से आगे ले गए। प्रदर्शनी में गहलोत आगे-आगे और पायलट पीछे-पीछे राजेश पायलट के जीवन से जुड़ी यादों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी का अवलोकन करते नजर आए। इस तरह से सचिन पायलट और गहलोत की सियासी केमिस्ट्री देखने वाली थी। गहलोत ने राजेश पायलट की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शिरकत कर संबंधों पर जमी बर्फ को पिघलाने का संकेत दिया है। गहलोत और पायलट के एक साथ एक मंच पर आने के बाद कांग्रेस में नए समीकरण बनने की संभावना बढ़ गई है। पायलट और गहलोत के मिलन से राजस्थान में पार्टी को मजबूती मिलेगी और नए नेतृत्व की नींव रखी जा सकती है। इस तरह दोनों के बीच सियासी तकरार की खड़ी दीवार टूटती हुई नजर आ रही है। दोनों नेताओं की मुलाकात औपचारिकता से ज्यादा कांग्रेस के लिए एक नई शुरुआत का संकेत हैं। राजस्थान कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर एक साथ एक मंच पर नजर आए।

● जयपुर से आर.के. बिन्नानी

पायलट-गहलोत में मिटीं दूरियां

भाजपा की बढ़ेगी सियासी टेंशन

सचिन पायलट और अशोक गहलोत के एक साथ आने से एक तरफ जहां कांग्रेस को सियासी संजीवनी मिली है तो वहीं दूसरी तरफ यह भाजपा के लिए किसी टेंशन से कम नहीं है। 2023 में गहलोत और पायलट की सियासी अदावत के चलते ही भाजपा सत्ता में वापसी कर सकी थी। अब जब फिर से दोनों एक साथ आ गए हैं तो भाजपा को नए तरीके से अपनी राजनीति तैयार करनी होगी। कांग्रेस ने राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर अपने नेताओं को एक मंच पर लाकर एकजुटता का सियासी संदेश दे दिया है। हालांकि, कुछ लोग इसे वक्ती तौर का सीजफायर मानकर चल रहे हैं। राजस्थान में अगले चुनाव को लेकर पायलट ने कहा कि चेहरा कौन होगा, इसका निर्णय सामूहिक प्रयासों और नतीजों के बाद होगा। उन्होंने कहा कि कोई एक आदमी हवा बना देगा, ऐसा नहीं होगा। वोट हम दोनों मिलकर बटोरेंगे। राजस्थान को 2024 और 2029 की राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ते हुए पायलट ने कहा कि अगर हम राजस्थान जीतते हैं तो 2029 में देश में भाजपा को हराया जा सकता है। ऐसे में देखना है कि पायलट और गहलोत की सियासी केमिस्ट्री कब तक बनी रहती है?

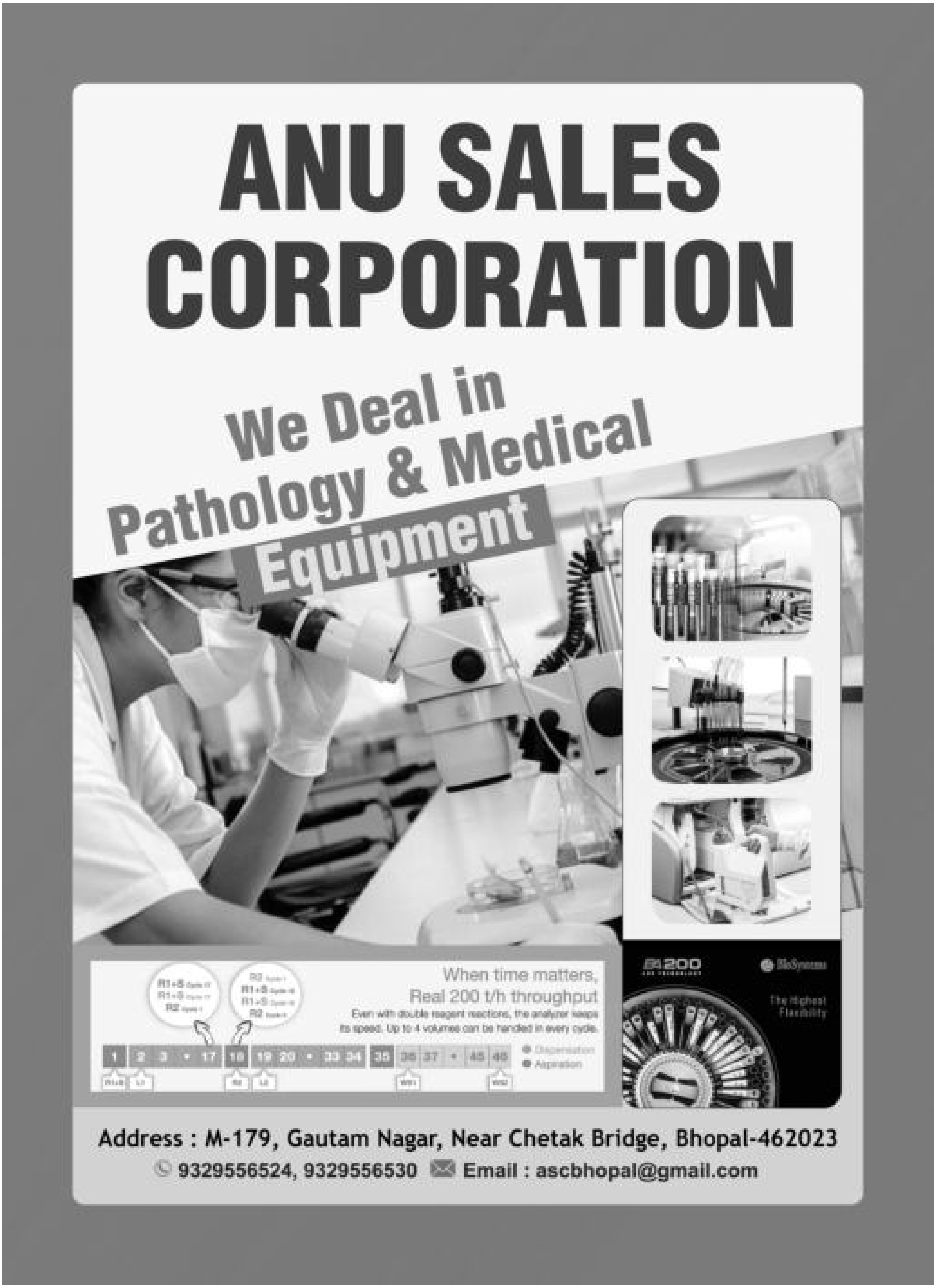
ANU SALES CORPORATION
We Deal in
Pathology & Medical
Equipment
When time matters,
Real 200 t/h throughput
Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.
Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

बिछने लगी मुस्लिम सियासत की बिसात

उप्र में दो साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से ही मुसलमानों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सियासी शह-मात का खेल शुरू हो गया है। सूबे में 20 फीसदी मुस्लिम मतदाता हैं, जो सपा का कोर वोटबैंक माना जाता है। कांग्रेस की ओर से सांसद इमरान मसूद मुसलमानों को साधने की कवायद में जुटे हैं, तो मायावती की नजर भी मुस्लिम वोटों पर है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम मुस्लिमों से आस लगाए है, तो भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने कमान संभाल ली है।

सूबे में मुस्लिमों को लेकर बिछाई जा रही सियासी बिसात को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव अलर्ट हो गए हैं क्योंकि सपा की राजनीति मुस्लिम वोटों पर ही टिकी हुई है। इमरान मसूद से लेकर मायावती और ओवैसी तक जिस तरह से सपा पर मुस्लिम समुदाय की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं, उससे अखिलेश यादव की सियासी बेचैनी बढ़ गई है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने गत दिनों आनन-फानन में अपने मुस्लिम नेताओं की एक बैठक बुलाई और उनकी सभी शंकाओं को दूर करने की कवायद करते नजर आए। उप्र में 2027 की सियासी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही मुस्लिम वोट को लेकर लामबंदी तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गत दिनों लखनऊ में अल्पसंख्यक मोर्चे के साथ बैठक की। इस बैठक में मुस्लिमों के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों का जिक्र करते हुए भाजपा व योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। इसके साथ ही वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए उन्हें ठीक करवाने की बात उठाई। इसी बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन था, है और रहेगा। हम हर हाल में कांग्रेस के साथ मिलकर उप्र का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।

उप्र अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मौलाना इकबाल कादरी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे घर, मस्जिद, रोजगार सब खतरे में हैं। राज्य में नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, जबकि अल्पसंख्यकों की समस्याएं हाशिए पर हैं। साफ है कि पिछले चुनाव में मुस्लिम समाज का करीब 90 फीसदी वोट पाने के बावजूद सपा अपने साथ बनाए रखने के लिए अलर्ट है और किसी तरह की कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है क्योंकि विपक्षी दलों की नजर सपा के इसी मजबूत वोट बैंक पर है। उप्र में एक समय मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोटर हुआ करता था, लेकिन 90 के दशक के बाद से सपा के साथ खड़ा नजर आ रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद मुस्लिमों का नजरिया कांग्रेस को लेकर बदला है। 2024 में मुस्लिमों ने एकमुश्त होकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को वोट दिया है। सहारनपुर से कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने इमरान मसूद ने इन दिनों मुस्लिम वोटों को कांग्रेस के साथ जोड़ने का बीड़ा उठा रखा है, जिसके लिए वे सपा और अखिलेश यादव को लगातार टारगेट पर ले रहे हैं। इतना ही नहीं सपा की मुस्लिम सियासत पर भी लगातार इमरान सवाल उठ रहे हैं।

इमरान 2024 के बाद से ही कह रहे हैं कि उप्र में कांग्रेस को अब किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि अखिलेश यादव मुस्लिम नेतृत्व को खत्म कर रहे हैं। इसके लिए आजम खान से लेकर इरफान सोलंकी तक के उदाहरण दे रहे हैं। इमरान ने कहा कि आजम खान और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्हें और उनके परिवार को जेल भेजा जा रहा है। वे मुस्लिम मुद्दों पर सपा की खामोशी को लेकर भी घेरने में जुटे हैं। इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि सपा को बोलने वाले मुसलमान नहीं, सिर्फ दरी बिछाने वाले मुस्लिम नेता चाहिए।

उप्र में 2027 की बढ़ती सियासी तपिश को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और भाजपा ने भी मुस्लिम वोटों को साधने की कवायद तेज कर दी है। ओवैसी की एआईएमआईएम ने गत दिनों लखनऊ में राज्य स्तरीय सम्मेलन किया, जिसमें 2027 के चुनाव लड़ने की रूपरेखा बनाई गई। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने योगी सरकार को अल्पसंख्यक विरोधी करार देते हुए कहा कि सूबे में हर दिन मुस्लिमों के मदरसों और मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, गैर-कानूनी तरीके से बुलडोजर के जरिए दरगाहों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन अपने आपको सेक्युलर कहलाने वाली सपा और कांग्रेस खामोश है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

भाजपा भी डाल रही डोरे

वहीं, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उप्र भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने पिछले हफ्ते मोदी के साथ मुसलमान सम्मेलन किया। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद मुस्लिम समाज की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र में सरकार बनाने के बाद सबसे पहले मुसलमानों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कम्प्यूटर का नारा दिया। बासित अली ने कहा कि अल्पसंख्यक का पैगाम, मोदी के साथ मुसलमान अभियान के जरिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े नेता और कार्यकर्ता उप्र के हर जिले में मुसलमानों के बीच जाकर मोदी सरकार की मुसलमानों के लिए किए गए कामों की उपलब्धियों को गिनाने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि मुसलमानों को भाजपा के किए काम बताने से जो उन्हें भरमा के भाजपा के खिलाफ किया गया है, वो भ्रम खत्म होगा। बासित ने कहा कि मदरसों, दरगाहों, मस्जिदों और मुसलमान बहुल इलाकों में जाकर चौपाल लगाकर मुस्लिमों को भाजपा के साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी। उप्र में मुस्लिम वोटों को लेकर बुने जा रहे सियासी ताना-बाना को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव अलर्ट हो गए हैं। इसी के मद्देनजर उन्होंने गत दिनों सपा अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक की, जिसमें सांसद इमरान मसूद को लेकर अखिलेश से सवाल किया। इसे लेकर अखिलेश यादव उनकी शंका को दूर करने की कोशिश करते नजर आए। सपा नेताओं ने अखिलेश के सामने सवाल उठाया कि इमरान मसूद के बयान से माहौल खराब हो रहा है और इमरान मसूद जिस तरह कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान दरी बिछाते हैं, तो इसका जवाब हम कैसे दें।

बिहार में भविष्य दांव पर लगा रहे चिराग पासवान

मुख्यमंत्री नहीं तो उपमुख्यमंत्री तो तय हो ही सकता है

बिहार की राजनीति अनिश्चित और जटिल है। नीतीश कुमार और जेडीयू का मजबूत वोट आधार (18.52 प्रतिशत), तेजस्वी यादव की यादव-मुस्लिम गठजोड़, और भाजपा की रणनीति चिराग के लिए चुनौतियां खड़ी करती हैं। इसके बावजूद, चिराग का यह कदम दबाव की राजनीति और दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अगर वे विधानसभा चुनाव जीतते हैं और एनडीए में स्थिति अनुकूल रहती है, तो वे कम से कम उपमुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश कर सकते हैं। हो सकता है अंदरखाने कुछ ऐसी बातें तय भी हो गई हों। क्योंकि केंद्र के मंत्री पद को कोई भी शख्स यूं ही दांव पर नहीं लगाएगा।

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान के 2025 बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की पुष्टि ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। गत दिनों बिहार के आरा में पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जाहिर है कि चुनाव लड़ने की बात से ही चिराग पासवान की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी की चर्चा भी तेज हो गई है।

दरअसल चिराग की रणनीति, बिहार के बदलते राजनीतिक परिदृश्य और एनडीए गठबंधन की आंतरिक राजनीति को लेकर है, ऐसी अफवाहें जोर पकड़नी ही थीं। आज हर कोई यह सोचने को विवश है कि चिराग पासवान केंद्र में मिले हुए मंत्री पद को छोड़कर बिहार की अनिश्चित राजनीति में क्यों झक मारना चाहते हैं? हालांकि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्हें मंत्री पद छोड़ने की कोई जरूरत वैसे तो नहीं है। पर यदि वाकई में अगर उन्हें बिहार में विधायक बनकर राजनीति करनी है तो उनकी संवैधानिक मजबूरी होगी कि वे अपना मंत्री पद और सांसदी दोनों ही छोड़ दें।

चिराग बहुत पहले बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते रहे हैं। चिराग पासवान बार-बार कहते हैं कि उनकी राजनीति का मूल उद्देश्य बिहार का विकास है। उनका मानना है कि दिल्ली में रहकर बिहार के लिए उनके सपने पूरे नहीं हो सकते। वे बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में देखना चाहते हैं, और इसके लिए वे राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। जाहिर है कि विधानसभा चुनाव लड़कर वो अपने नारे के हिसाब से अपनी व्यक्तिगत छवि को और मजबूत करना चाहते हैं। जो आगे चलकर उनके लिए बहुत निर्णायक साबित हो सकता है। हो सकता है कि बाद में चलकर विधायकी से इस्तीफा भी दें दें। पर अपने पक्ष में वो माहौल तो तैयार ही कर लेंगे।

चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), और उनके कुछ समर्थक उन्हें बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। हालांकि बिहार में चिराग के लिए मुख्यमंत्री पद बहुत दूर की कौड़ी है। एनडीए में कोई नहीं चाहेगा कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। भाजपा खुद नहीं चाहेगी कि चिराग बिहार की कमान संभालें। फिर भी बिहार में चिराग के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा शुरू कैसे हो गई यह कोई नहीं समझ रहा है। यह भी एक किस्म की राजनीति ही है। यह विशेष रूप से तब चर्चा में आया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद उनकी स्थिति को लेकर अटकलें तेज हुईं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि चिराग नीतीश कुमार के बाद एक मजबूत विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करना चाहते हैं, खासकर अगर एनडीए में नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति बनती है।

चिराग पासवान सामान्य (अनारक्षित) सीट से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जिससे वे केवल दलित नेता के रूप में नहीं, बल्कि सभी वर्गों के नेता के रूप में उभरना चाहते हैं। जाहिर है कि आज तक देश में कोई दलित नेता सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं उठा सका। उप्र की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और चिराग के पिता रामविलास पासवान तक ने कभी सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। अगर चिराग सामान्य सीट से चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं तो जाहिर है उनकी पार्टी को समावेशी संगठन का विस्तार मिलेगा। जिसमें विभिन्न समुदायों के नेता शामिल हैं। यह उनकी स्वीकार्यता को बढ़ाने और जातिगत राजनीति से बाहर निकलने की रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है।

चिराग की पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 6.47 प्रतिशत वोट शेयर के साथ पांच सीटें जीतीं, जिससे एनडीए में उनकी स्थिति मजबूत हुई है। वे विधानसभा चुनाव में अधिक सीटों (लगभग 45) की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी पार्टी का प्रभाव बढ़े। यह कदम नीतीश कुमार की जेडीयू के लिए चुनौती पैदा कर सकता है, और चिराग इसे अपने पक्ष में भुनाना चाहते हैं। चिराग पासवान की युवा छवि और जातिगत राजनीति से हटकर भाषण देने की शैली उन्हें बिहार के युवाओं और गैर-जातिगत मतदाताओं में लोकप्रिय बनाती है। वे इसे भुनाकर तेजस्वी यादव जैसे अन्य युवा नेताओं के लिए चुनौती बनना चाहते हैं।

कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा चिराग पासवान को नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए उपयोग कर रही है। माना जाता है कि नीतीश कुमार को कंट्रोल करने के लिए ही पिछले विधानसभा चुनावों में चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की कई सीटों पर हार का कारण बने थे। हाल ये हुआ कि जेडीयू बिहार में मात्र 43 सीटों पर सिमटकर रह गई। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा इस बार भी चिराग को 30 से 40 सीट दे सकती है। अगर लोजपा 30 से 40 सीट के बीच में अपने विधायक बनाने में कामयाब होती है और जेडीयू 40 से भी कम सीटों पर सिमटती है तो चिराग के लिए चांदी हो सकती है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बिहार में एक मजबूत चेहरा तैयार करने में असफल रहा है, और चिराग इस कमी को भर सकते हैं। हालांकि, भाजपा ने नीतीश को 2025 के लिए मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है, लेकिन चिराग की सक्रियता से भविष्य में बदलाव की संभावना बनी रहती है। हालांकि भाजपा चिराग को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेगी इस पर रत्ती भर भी किसी विश्लेषक को भरोसा नहीं है।

● विनोद बक्सरी

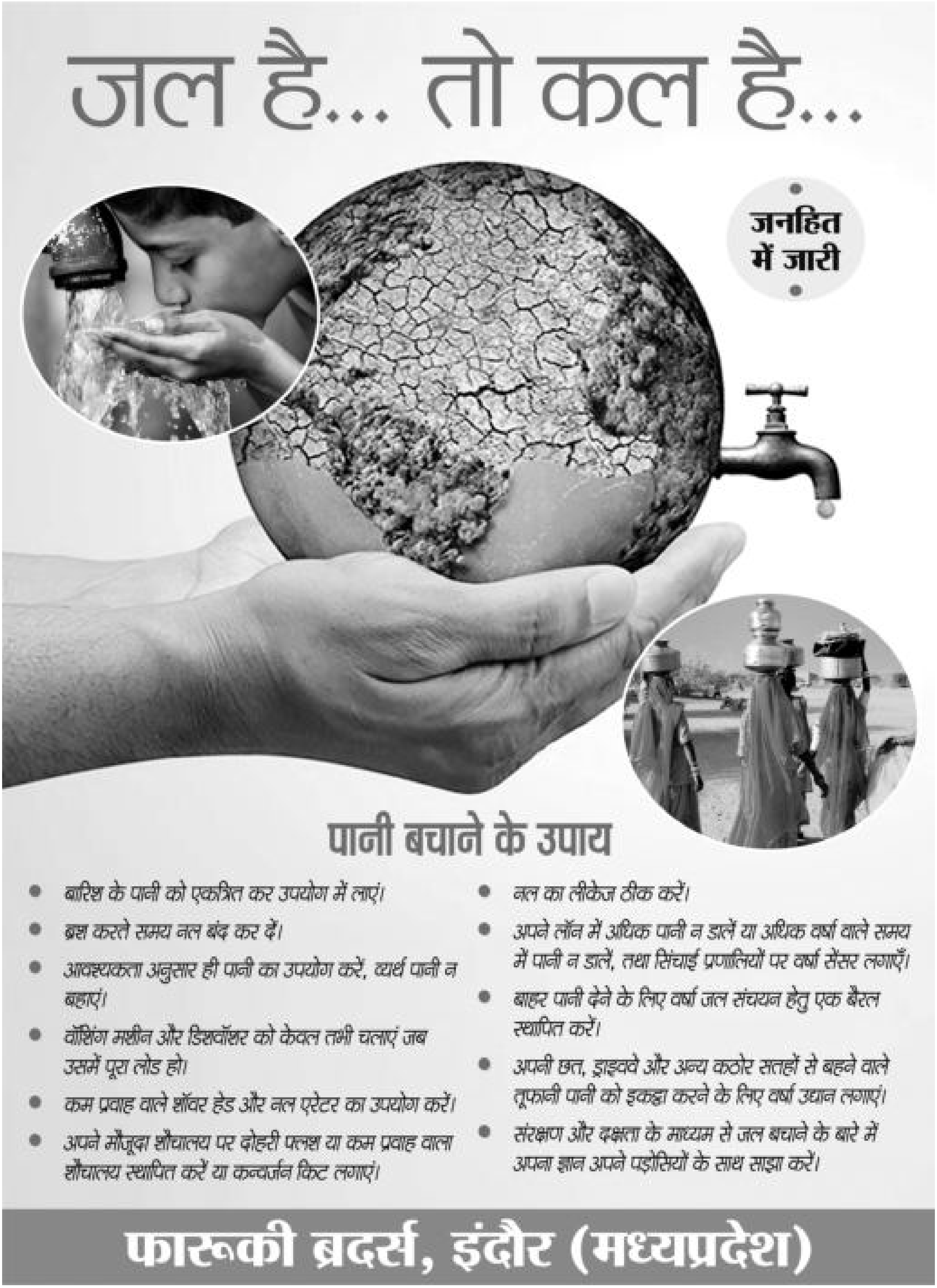
जल है... तो कल है...
जनहित में जारी
पानी बचाने के उपाय
बारिश के पानी को एकत्रित कर उपयोग में लाएं।
ब्रश करते समय नल बंद कर दें।
आवश्यकता अनुसार ही पानी का उपयोग करें, व्यर्थ पानी न बहाएं।
वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर को केवल तभी चलाएं जब उसमें पूरा लोड हो।
कम प्रवाह वाले शॉवर हेड और नल एरेटर का उपयोग करें।
अपने मौजूदा शौचालय पर दोहरी फ्लश या कम प्रवाह वाला शौचालय स्थापित करें या कन्वर्जन किट लगाएं।
नल का लीकेज ठीक करें।
अपने लॉन में अधिक पानी न डालें या अधिक वर्षा वाले समय में पानी न डालें, तथा सिंचाई प्रणालियों पर वर्षा सेंसर लगाएँ।
बाहर पानी देने के लिए वर्षा जल संचयन हेतु एक बैरल स्थापित करें।
अपनी छत, ड्राइववे और अन्य कठोर सतहों से बहने वाले तूफानी पानी को इकट्ठा करने के लिए वर्षा उद्यान लगाएं।
संरक्षण और दक्षता के माध्यम से जल बचाने के बारे में अपना ज्ञान अपने पड़ोसियों के साथ साझा करें।
फारूकी ब्रदर्स, इंदौर (मध्यप्रदेश)

कट्टरपंथी संगठन लड़ेगा चुनाव

बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी का पंजीकरण बहाल हो जाना और उसके चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो जाना भारत के लिए भी चिंताजनक है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से ही एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं, वे भारत के लिए शुभ संकेत नहीं। बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार केवल पाकिस्तान और चीन से ही अपने संबंध बढ़ाने में ही नहीं लगी हुई है, बल्कि अपने यहां के कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा देने में भी लगी हुई है। ताजा उदाहरण जमाते इस्लामी का चुनाव लड़ने में सक्षम हो जाना है। यह ठीक है कि इसका पंजीकरण इसलिए बहाल हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने का आदेश दिया था, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के एक सप्ताह के अंदर ही बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ दो अन्य न्यायाधीशों ने इस्तीफा दे दिया था। इन्हें छात्रों के उसी संगठन ने इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया था जिनके नेतृत्व में शेख हसीना सरकार के विरूद्ध आंदोलन चला था।

स्पष्ट है कि अब वहां के सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे न्यायाधीश आ चुके हैं जो कार्यवाहक सरकार की हां में हां मिलाने के लिए तैयार हैं। तथ्य यह भी है कि छात्रों के आंदोलन में जमाते इस्लामी ने पूरा सहयोग दिया था। यह वही संगठन है जिस पर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय पाकिस्तान की मदद करने और मानवता के विरूद्ध अपराध एवं नरसंहार के आरोप लगे थे। इन आरोपों के चलते ही उसके छह शीर्ष नेताओं को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। जमाते इस्लामी कितना कट्टरपंथी और जिहादी सोच वाला संगठन है, इसका एक प्रमाण यह भी है कि एक समय जो विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ती थी, उसने कुछ समय पहले स्वयं को उससे अलग कर लिया था। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर शीघ्र चुनाव कराने का दबाव बना रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में एक के बाद एक कट्टरपंथी और जिहादी सोच वाले संगठनों से प्रतिबंध हटने के साथ आतंकी गतिविधियों में जेल की सजा पाए तत्वों को रिहा किया जा रहा है। इससे यही स्पष्ट होता है कि कट्टरपंथी तत्वों के सिर उठाने से सेना प्रमुख को कोई समस्या नहीं। कहना कठिन है कि सेना प्रमुख के दबाव बनाने के बाद बांग्लादेश में शीघ्र चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि हाल-फिलहाल चुनाव कराने की कोई तत्परता नहीं दिख रही है। भारत को बांग्लादेश की गतिविधियों को लेकर इसलिए चिंतित होना चाहिए, क्योंकि वहां पाकिस्तान और चीन के साथ अमेरिका का भी प्रभाव बढ़ सकता है।

मदरसों के जरिए चला रहे नेटवर्क

हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी बांग्लादेश (हूजी-बी) और जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) जैसे समूह, जो लश्कर से जुड़े हैं, विश्वविद्यालयों के पास मदरसे संचालित करते हैं। ये मदरसे छात्रों को वहाबी-सलाफी विचारधाराओं से भरते हैं, शिक्षा को इस्लामी पुनरुत्थान के लिए जिहाद के रूप में पेश करते हैं। यूके स्थित फ्रंट संगठनों ने कट्टरपंथी मदरसों को भी वित्त पोषित किया है जो बाद में विश्वविद्यालय के छात्रों की भर्ती करते हैं। शिविर के सदस्य भारतीय छात्रों को इस्लामी अध्ययन मंडलियों में आमंत्रित करते हैं, धार्मिक चर्चाओं को एलईटी के प्रचार वीडियो के साथ मिलाते हैं। ढाका विश्वविद्यालय में होने वाले कार्यक्रमों में मारे गए कश्मीरी आतंकवादियों को शहीदों के रूप में महिमामंडित किया गया है। भारत से एलईटी के हमले के फुटेज को टेलीग्राम और सिग्नल जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप के माध्यम से साझा किया जाता है, जिसमें पहलगाम हमलों जैसी घटनाओं के वीडियो भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए प्रसारित किए जाते हैं।

1947 तक भारत का ही हिस्सा रहा बांग्लादेश अब अस्थिरता से जूझ रहा है। वहां अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, और वे वहां से जान बचाकर भारत आ गई थीं। हसीना को वहां से भगाने वाले इस्लामिक कट्टरपंथी अब अपने मंसूबे पूरे करने में जुट गए हैं। हसीना के ढाका छोड़ने के बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी थी, जिसके तहत कट्टरपंथियों की गतिविधियों पर कुछ रोक लगाई गई थीं, लेकिन अब वे ताकतें वहां फिर से सक्रिय हो गई हैं। ढाका और अन्य शहरों में कट्टरपंथी समूहों ने महिलाओं के खिलाफ नए नियम लागू किए हैं। एक शहर में घोषणा की गई है कि अब युवा महिलाएं फुटबॉल नहीं खेल सकतीं। वहीं, एक अन्य शहर में पुलिस को एक व्यक्ति को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, जिसने सार्वजनिक रूप से महिला को परेशान किया था, फिर उसे फूलों की माला पहनाई।

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार इस्लाम का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं देती है, तो वे स्वयं यह कदम उठाएंगे। नए संविधान के मसौदे पर काम कर रहे राजनीतिक दलों के अधिकारियों ने कहा कि इसमें धर्मनिरपेक्षता को समाप्त कर बहुलवाद को प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, लेकिन अब कट्टरपंथी ताकतों के सत्ता में आने से महिलाओं के अधिकारों पर खतरा बढ़ गया है। हसीना सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश में अहमदिया मुस्लिम संप्रदाय के धार्मिक स्थलों पर भीड़ ने हमले किए। इसके चलते अहमदिया समुदाय डर में जी रहा है और उनकी प्रार्थना सभाओं में उपस्थिति आधी हो गई है। शेख तस्नीम अफरोज एमी जैसी छात्राएं, जिन्होंने हसीना को सत्ता से हटाने के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी, अब ठगी हुई महसूस कर रही हैं। उन्हें उम्मीद थी कि लोकतंत्र बहाल होगा, लेकिन कट्टरपंथी ताकतों के उभरने से वे चिंतित हैं। खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया कि हाल ही में लाहौर के कसूर में सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद के भाषण में बंगाल और 28 मई को क्षेत्र के विभाजन का संदर्भ दिया गया है। इस भाषण का इस्तेमाल कट्टरपंथी हलकों में दुष्प्रचार को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से किया जा रहा है।

● ऋतेन्द्र माथुर

पश्चिम अफ्रीका में नव-उपनिवेशवाद

फ्रांसीसी-भाषी अफ्रीका का कभी पूरी तरह से निरुपनिवेशीकरण हुआ ही नहीं था। अपने इन पुराने उपनिवेशों में स्थित फ्रांसीसी संपत्ति की हिफाजत करने के नाम पर, फ्रांस ने इसका आग्रह किया था और ये पूर्व-उपनिवेश इसके लिए राजी भी हो गए थे कि इन देशों में, फ्रांसीसी सैनिक तैनात रहेंगे। इससे फ्रांस को अपने इन पूर्व-उपनिवेशों की राजनीति में दखलंदाजी करने के खूब मौके मिले। इसके अलावा इन देशों से सीएफए फ्रांक नाम की मुद्रा अंगीकार कराई गई, जिसकी फ्रांसीसी फ्रांक की तुलना में स्थिर विनिमय दर थी। और इस स्थिर विनिमय दर को बनाए रखने के लिए, इन देशों की मुद्रा नीति को फ्रांसीसी केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता था। और चूंकि मुद्रा नीति को आम तौर पर आर्थिक नीति से अलग नहीं किया जा सकता है, इसका बुनियादी तौर पर अर्थ यह हुआ कि मोटे तौर पर इन देशों की आर्थिक नीति को फ्रांस ही नियंत्रित करता था।

यह समूची व्यवस्था, फ्रांस के यूरोपीय यूनियन प्रणाली का हिस्सा बनने के बाद भी जारी रही थी। इसलिए, इन पूर्व-फ्रांसीसी उपनिवेशों की स्वतंत्रता हमेशा से ही गंभीरता से कटी-फटी रही थी। और इनमें से किसी भी देश में सत्ता में आने के बाद क्रांतिकारियों द्वारा जब भी इस स्थिति के शिकंजे से बाहर निकलने की कोशिश की गई, हर बार उसका मुकाबला फ्रांस की ओर से, अमेरिका के समर्थन से, ऐसी सरकारों के खिलाफ नव-उपनिवेशिक निर्ममता की करतूतों से किया गया था। थामस संकरा को, जो एक क्रांतिकारी थे, जो बुर्किनो फासो में सत्ता में आए थे और जो फ्रांसीसी सेनाओं को अपने देश से बाहर कराना चाहते थे, उन्हें एक तख्तापलट में मौत के घाट उतार दिया गया था। यह तख्तापलट किया तो उनकी अपनी पार्टी के ही एक सदस्य ने था, लेकिन जाहिर है कि फ्रांसीसी उकसावे पर और फ्रांसीसी समर्थन से ही किया था। बहरहाल, इन देशों में नव-उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष जारी रहा है और अक्सर स्थानीय सेना ही वह क्षेत्र बनी रही है, जिससे इस तरह के प्रतिरोध का नेतृत्व आता है। कैप्टन त्राओर ने, जो पैट्रिओटिक मूवमेंट फॉर सेफगार्ड एंड रेस्टोरेशन (पीएमएसआर) के नेता हैं, जिसकी स्थापना 2022 के आरंभ में बुर्किनो फासो में हुई थी, 30 सितंबर 2022 को सत्ता संभालने के बाद फ्रांसीसी सेनाओं को अपने देश से बाहर कराने का आग्रह किया था और वास्तव में इसमें कामयाब भी हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएफए फ्रांक व्यवस्था को भी खत्म कर दिया, जिसमें उनका देश फंसा हुआ था। त्राओर ने दो पड़ोसी देशों, माली तथा नाइजर के साथ मिलकर, जो दोनों भी सच्चे निरुपनिवेशीकरण की इच्छा से भरे हुए थे, एसोसिएशन ऑफ सहेल स्टेट्स (एईएस) का गठन किया। फ्रांसीसी तथा अमेरिकी सेनाओं को नाइजर से हटना पड़ा और वहां पेंटागन का जो एक ड्रोन स्टेशन था, उसे बंद करना पड़ा। इस तरह, इस क्षेत्र में जो कि खनिज संपदा के मामले में बहुत ही समृद्ध है, एईएस साम्राज्यवाद के पांव का कांटा बन गया। इस खनिज संपदा में सोने का महत्वपूर्ण स्थान है और बर्किनो फासो अफ्रीका के सबसे बड़े स्वर्ण उत्पादकों में से है, जिसने 2024 में 57 टन सोने का उत्पादन किया था। लेकिन, इस देश के लोगों को इस स्वर्ण उत्पादन से शायद ही कोई लाभ मिलता था और सोने के उत्पादन से होने वाली ज्यादातर आय उन विदेशी कंपनियों के हाथों में चली जाती थी, जिनकी मिल्कियत में ये खदानें थीं। बहरहाल, पीएमएसआर सरकार ने 2024 में एसओपीएएमआईबी नाम की एक सरकारी कंपनी स्थापित की और इसके जरिए धीरे-धीरे विदेशी मिल्कियत वाली उन कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया, जो सोना निकालने के काम में लगी हुई थीं।

इस तरह, राष्ट्रीयकृत सोना खदानों की कमाई से सरकार के पास पहले से ज्यादा राजस्व आने लगा जिसे सरकार ने देश का औद्योगिकीकरण करने के लिए और बर्किनो की जनता के लिए स्वास्थ्य तथा शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए लगाना शुरू कर दिया। अब जब पिछले कुछ समय से सोने की कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि डॉलर की नियति पर संदेह के बादल मंडराने लगे हैं और बहुत से डॉलर में संपत्ति रखने वालों ने सोने के रूप में संपत्ति जमा करना शुरू कर दिया है, बर्किनो फासो की सरकार इस स्थिति में है कि वह इन हालातों का फायदा उठा सकती है और एक हद तक उन पाबंदियों के असर की काट कर सकती है, जो अपनी धरती से उसके फ्रांसीसी सेनाओं को बाहर करने की पृष्ठभूमि में, पश्चिमी ताकतों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस पर लगाई गई थीं। कहानी इतनी ही नहीं है। त्राओर की सरकार ने दस्तकाराना सोने के क्षेत्र को भी विनियमित किया है, देश में एक गोल्ड रिफाइनरी स्थापित की है, बर्किनो फासो के अन्य प्राथमिक उत्पादों के भी घरेलू स्तर पर प्रसंस्करण की प्रक्रिया शुरू की है, खेती की पैदावार बढ़ाने में किसानों की मदद की है और खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कदम उठाए हैं।

● सुश्री नित्या

मुक्ति संघर्ष के नए अध्याय की शुरुआत

बहरहाल, आने वाले दिनों में साम्राज्यवाद, निरुपनिवेशीकरण के इस संघर्ष के खिलाफ और भीषण रूप लेने जा रहा है। पुराने फ्रांसीसी स्वार्थों के अलावा अब दुनियाभर में कच्चे मालों की एक नई तलाश और है, जो डोनाल्ड ट्रंप निजाम ने शुरू की है और जिसमें जाहिर है कि अफ्रीका एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने जा रहा है। वास्तव में ट्रंप ने पहले ही कांगो के निजाम की मिलीभगत से, कांगो की खनिज संपदा पर नियंत्रण हासिल करने की योजना बना ली है। ट्रंप जिस तरह की जल्दी में दुनियाभर के खनिज संसाधनों पर नियंत्रण हासिल करने की और खासतौर पर उन खनिज संसाधनों पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जो नई तथा उदीयमान प्रौद्योगिकियों में काम आते हैं, उस पर हम बाद में अलग से किसी लेख में चर्चा करेंगे। लेकिन, इस मामले में उसकी जल्दी यूक्रेन के साथ उसके सौदे से, ग्रीनलैंड को हथियाने की उसकी आकांक्षा से, कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य या प्रांत बनाने की और सागर तल पर भी नियंत्रण हासिल करने के उसके लालची मंसूबों से स्वतः स्पष्ट है। यहां तक कि रूस तथा यूक्रेन के बीच युद्ध में शांति लाने के लिए ईमानदार मध्यस्थ बनने की उसकी इच्छा को भी, इन दोनों देशों के समृद्ध खनिज संसाधनों तक पहुंच की उसकी आकांक्षा से पूरी तरह से अलग करके नहीं देखा जा सकता है।

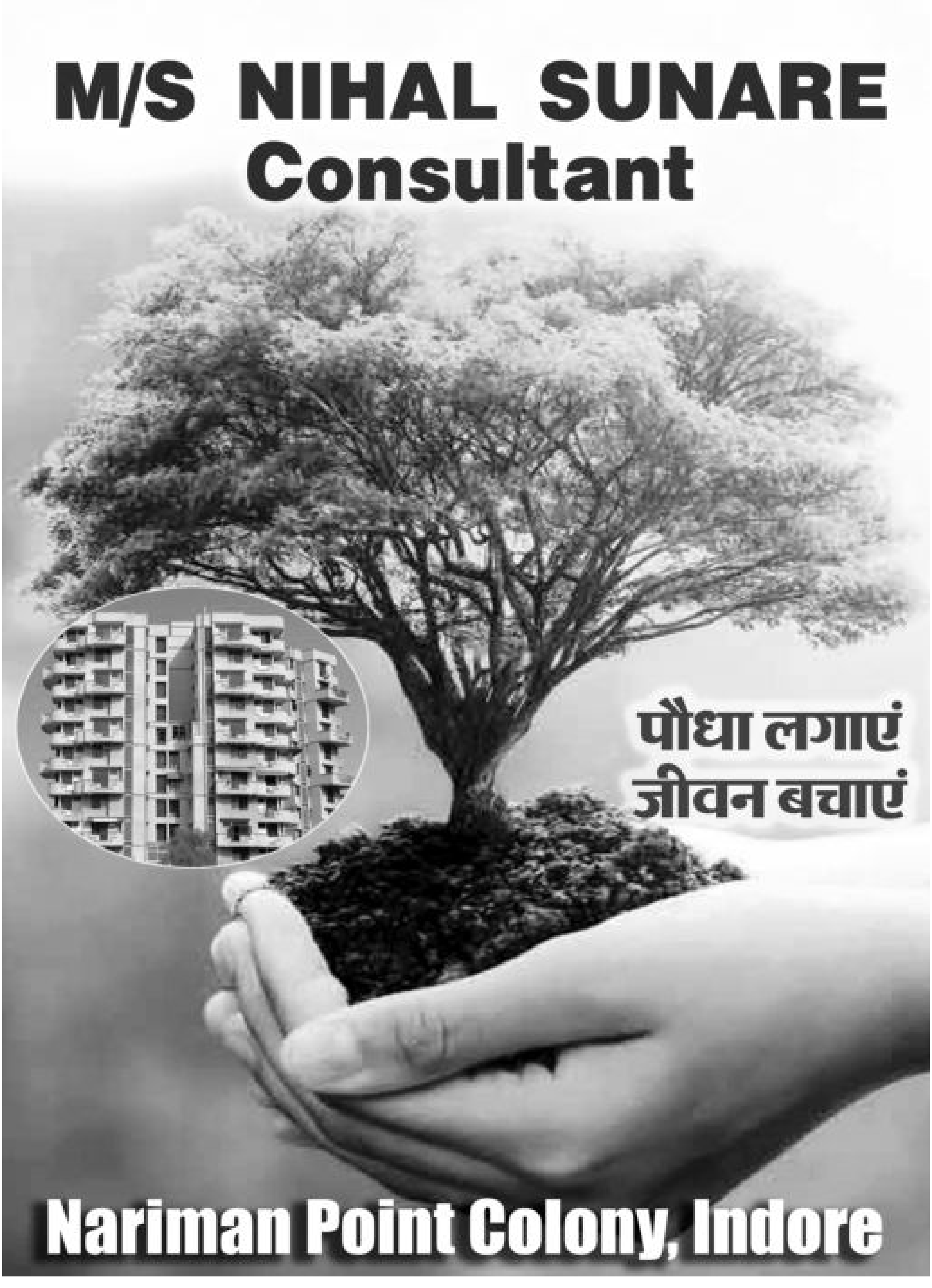
M/S NIHAL SUNARE
Consultant
पौधा लगाएं
जीवन बचाएं
Nariman Point Colony, Indore

नीरज ने गढ़ा नया कीर्तिमान

भारत के स्टार और दो बार के ओलम्पिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में अपने नाम नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। उन्होंने 90.23 मीटर का थ्रो किया और दूसरे स्थान पर रहे। अपने करियर में उन्होंने पहली बार इस आंकड़े को छुआ है। हालांकि जर्मनी के जूलियन वेबर ने उनसे ज्यादा दूर भाला फेंका और वह पहले स्थान पर रहे। नीरज 90 मीटर पार करने वाले दुनिया के पच्चीसवें और एशिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। डायमंड लीग 2025 में उन्होंने पहले प्रयास में 88.44 मीटर का स्कोर किया था, जबकि दूसरा थ्रो सामान्य रहा। लेकिन जब नीरज ने तीसरा थ्रो किया तो अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज कर दिखाया। इससे पहले उनका सर्वश्रेठ थ्रो 89.94 मीटर का था जो उन्होंने 2022 डायमंड लीग में किया था। वहीं वेबर ने भी पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार किया और वह ऐसा करने वाले छठे खिलाड़ी बने।

नीरज के इस थ्रो के बावजूद वे दूसरे स्थान पर रहे। उनसे भी शानदार थ्रो जर्मनी के जूलियन वेबर ने किया। उन्होंने 91.06 मीटर का थ्रो हासिल किया, जबकि तीसरे नंबर पर ग्रेनेडा के पीटर एंडरसन रहे जिन्होंने 85.64 मीटर का थ्रो किया। पेरिस ओलम्पिक चैम्पियन पाकिस्तान के अरशद नदीम (92.97 मीटर) और चीनी ताइपै के चाओ सुन चेंग (91.36 मीटर) ही एशिया के दो अन्य खिलाड़ी हैं जो 90 मीटर से अधिक का थ्रो फेंक चुके हैं। दूरी के हिसाब से बात की जाए तो नीरज इन 26 खिलाड़ियों में 24वें स्थान पर हैं।

इस थ्रो के साथ नीरज अब 90 मीटर क्लब में शामिल हो गए हैं, जिसमें ओलम्पिक स्वर्ण पदक विजेता पाकिस्तान के अरशद नदीम जैसे खिलाड़ी पहले से मौजूद हैं। यह उपलब्धि नीरज के लिए सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी एक बहुत बड़ी जीत है। दोहा में यह नीरज का इस सीजन का पहला बड़ा मुकाबला था, जहां उनका सामना दो बार के वर्ल्ड चैम्पियन और 2024 ओलम्पिक कांस्य पदक विजेता ग्रेनेडा के पीटर्स एंडरसन, चेकिया के याकुब वाडलेजच (2024 के दोहा विजेता), जर्मनी के वेबर जूलियन और मैक्स डेह्निंग, केन्या के जूलियस येगो और जापान के रोडरिक जेंकी डीन जैसे दिग्गजों से हुआ। इस ऐतिहासिक थ्रो ने उन्हें डायमंड लीग में दूसरा स्थान दिलाया लेकिन न कोई मेडल मिला और न ही कोई ट्रॉफी। इसके बाद कई खेल प्रेमियों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि जब डायमंड लीग में पदक नहीं मिलता, ट्रॉफी नहीं मिलती तो आखिरी एथलीट इस लीग में भाग क्यों लेते हैं?

एथलेटिक्स की सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिताओं में से एक है जिसमें दुनिया के सर्वश्रेठ एथलीट भाग लेते हैं। इसमें भाग लेना और अच्छा प्रदर्शन करना खिलाड़ी को पहचान दिलाता है। हालांकि इसमें कोई मेडल या ट्रॉफी नहीं मिलती है। डायमंड लीग के चार इवेंट होते हैं। सबसे पहले दोहा, फिर पेरिस, लुसाने और आखिर में ज्यूरिख। प्रत्येक इवेंट में शीर्ष 8 एथलीट को नकद पुरस्कार मिलता है। 2025 में दोहा डायमंड लीग में पहले स्थान पर रहने वाले एथलीट को 10 हजार अमेरिकी डॉलर की ईनामी राशि मिली। दूसरे स्थान पर रहने वाले नीरज चोपड़ा को 6 हजार डॉलर मिले। तीसरे स्थान के एथलीट को 3500 डॉलर, चौथे स्थान के एथलीट को 2 हजार डॉलर, पांचवें स्थान के एथलीट को 1250 डॉलर, छठे स्थान के एथलीट को 1000 डॉलर, सातवें स्थान के एथलीट को 750 और आठवें स्थान के एथलीट को 500 डॉलर इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। डायमंड लीग के चारों इवेंट के विनर और बेस्ट 2 एथलीट के बीच एक डायमंड लीग का फाइनल मुकाबला होता है। फाइनल में पहले स्थान पर रहने वाले एथलीट को 30 हजार अमेरिकी डॉलर मिलते हैं। दूसरे स्थान के एथलीट को 12 हजार, तीसरे स्थान के एथलीट को 7000 और चौथे स्थान के एथलीट को 4000 अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। पांचवें एथलीट को 2500 और छठे एथलीट को 2000 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं।

● आशीष नेमा

नीरज चोपड़ा के सर्वश्रेष्ठ थ्रो

- **दोहा डायमंड लीग 2025:** नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग के दोहा चरण में आखिरकार 90 मीटर की बाधा पार करके 90.23 मीटर का थ्रो फेंका लेकिन वे जर्मनी के जूलियन वेबर के बाद दूसरे स्थान पर रहे। वेबर ने अपने आखिरी प्रयास में 91.06 मीटर का थ्रो फेंका, जबकि नीरज ने तीसरे प्रयास में ऐसा किया था। यह नीरज का अब तक का सर्वश्रेष्ठ थ्रो है।
- **पेरिस ओलम्पिक फाइनल 2024:** नीरज का पेरिस ओलम्पिक के फाइनल में 89.45 मीटर का थ्रो उनके करियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा। हालांकि इसके बाद वह एक बार भी वैध थ्रो नहीं कर सके।
- **डायमंड लीग फाइनल 2024:** नीरज ने ब्रसेल्स डायमंड लीग फाइनल में 87.86 मीटर का थ्रो किया। वह दूसरे स्थान पर रहे और खिताब से चूक गए थे।
- **दोहा डायमंड लीग 2023:** नीरज के 88.67 के थ्रो ने उन्हें 2023 में दोहा डायमंड लीग में फिर से स्वर्ण पदक दिलाया। नीरज ने अपने पहले प्रयास में स्वर्ण पदक जीता।
- **विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023:** इस चैम्पियनशिप में 88.17 मीटर का थ्रो कर नीरज ने स्वर्ण पदक जीता। इसी प्रतियोगिता के जरिए पेरिस ओलम्पिक के लिए क्वालिफाई किया। इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने।
- **लुसान डायमंड लीग 2023:** नीरज ने 87.66 मीटर थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। यह उन्होंने पांचवें प्रयास में जाकर थ्रो किया और सीधे स्वर्ण पदक पर निशाना साधा था।
- **स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022:** नीरज ने स्वीडन में डायमंड लीग 2022 में 89.94 मीटर के जेवलिन थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। इस थ्रो के साथ, उन्होंने फिनलैंड में पावो नुरमी गेम्स में सेट किए गए अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 89.30 मीटर को बेहतर किया।
- **विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022:** नीरज ने विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में रजत पदक जीत एकमात्र भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रचा था। उन्होंने 88.13 मीटर के प्रयास के साथ रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया था।
- **टोक्यो ओलम्पिक 2020:** टोक्यो ओलम्पिक में स्वर्ण पदक जीतकर नीरज रातों-रात सनसनी बन गए थे। अपने दूसरे थ्रो में उन्होंने 87.58 मीटर की दूरी तय की और भारत को ओलम्पिक का पहला ट्रैक एंड फील्ड गोल्ड दिलाया था।
- **एशियन गेम्स 2018:** नीरज ने 2018 एशियाई खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। तब उन्होंने 88.06 मीटर का थ्रो किया था।

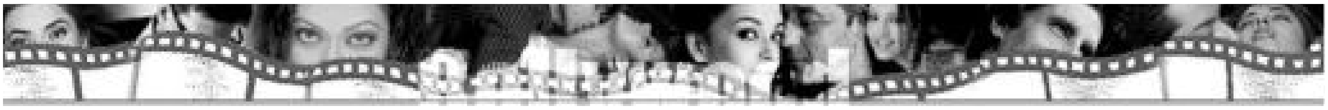

श्रीदेवी के चांद से चेहरे का दीवाना था ये सुपरस्टार

उम्र में 13 साल बड़ा... निभा चुका उनके सौतेले बेटे का किरदार

श्रीदेवी की खूबसूरती के कई किस्से आपने सुने होंगे। उनकी लवस्टोरी और पति बोनी कपूर की लवस्टोरी भी सुनी होगी। लेकिन क्या आप साउथ सुपरस्टार के साथ उनकी अलग ही प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं। जिनके लिए उन्होंने भी खूब तप किए थे। तो चलिए इस प्यारे से रिश्ते और किस्से के बारे में बताते हैं।

ये सुपरस्टार हैं रजनीकांत। रजनीकांत और श्रीदेवी ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है। दोनों की दोस्ती और ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री किसी से छिपी नहीं है। दोनों ने पहली बार साल 1976 में तमिल रोमांटिक फिल्म मूंडरू मुदीचू में काम किया। उस वक्त श्रीदेवी सिर्फ 13 साल की थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रजनीकांत की फिल्म में श्रीदेवी कोई हीरोइन नहीं थीं। बल्कि एक्टर की सौतेली मां का रोल प्ले किया था।

आगे चलकर दोनों ने साथ में 19 फिल्में की। हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ से लेकर हिंदी तक। कहते हैं कि काम के साथ-साथ रजनीकांत को श्रीदेवी से प्यार भी होने लगा था। इतना ही नहीं, रजनीकांत श्रीदेवी की फैमिली से बहुत क्लोज थे। एक बार तो रजनीकांत ने अपनी चाहत को कबूल करना चाहा था। वह 16 साल की श्रीदेवी से शादी करना चाहते थे। एक बार वह श्रीदेवी को प्रपोज भी करने वाले थे। उनकी मां से भी रिश्ते के बारे में बात करने वाले थे लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि बात कभी आगे ही नहीं बढ़ सकी।

अभिनेता ने इंटरव्यू में किया था खुलासा... फिल्ममेकर के बालाचंदर को दिए इंटरव्यू में रजनीकांत ने खुलासा किया था कि उनके दिल में श्रीदेवी के लिए बहुत प्यार था। वह प्रपोजल लेकर उनके घर भी गए थे। वह उनकी मां से भी श्रीदेवी का हाथ मांगने वाले थे लेकिन अचानक घर की लाइट चली

गई और अंधेरा पसर गया। रजनीकांत जब श्रीदेवी के घर गए तो उनकी खूब आव-भगत हुई। अच्छा-अच्छा खाना बना और खूब मेहमान नवाजी हुई। रजनीकांत भी अपनी दिल की बात कहने ही वाले थे कि अचानक लाइट चली गई और उन्होंने अपने दिल की बात दिल में ही रख ली। उन्होंने इसे एक अशुभ संकेत माना और सोचा कि फिर कभी इस शुभ चीज के बारे में बात होगी। मगर उस दिन के बाद वो दिन कभी नहीं आया कि रजनीकांत श्रीदेवी से कुछ ऐसा कह पाते। आगे चलकर श्रीदेवी ने साल 1996 में बोनी कपूर से शादी कर ली। एक किस्सा ये भी बड़ा फेमस है कि एक बार रजनीकांत बहुत बीमार हो गए थे। रजनीकांत के लिए तब श्रीदेवी ने सात दिन का व्रत रखा था। दोनों के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था जो हमेशा रहा। जब श्रीदेवी की मौत हुई तो रजनीकांत भी सब छोड़कर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत हैं। दोनों ने साल 1981 में शादी की थी। शादी के बाद से दोनों हमेशा सालगिरह पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। इन 37 सालों में पहली बार रजनीकांत ने ये ट्रेडिशन तोड़ा था। जब श्रीदेवी की मौत हुई थी। उस साल उन्होंने एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं की थी।

अमिताभ बच्चन ने कर दिया ऐसा काम... फिर डायरेक्टर को सताने लगी चिंता

बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने खुलासा किया कि उन्होंने सिर्फ दो घंटे में पांच विज्ञापनों और दो फोटोशूट की शूटिंग पूरी की। जिसके चलते निर्देशक ने उनसे मजाक में कहा, आप तो काम करने का तरीका ही बिगाड़ रहे हैं। ये किस्सा बिग बी ने अपने ब्लॉग में किया। वह अक्सर ब्लॉग लिखते हैं और अपने हिस्से के किस्से-कहानियों को शेयर करते हैं।

अमिताभ ने अपने ब्लॉग में लिखा, काम कर रहा हूं... और इससे जो खुशी मिलती है, वो गजब की है... करीब 2 घंटे में 5 फिल्में और 2 फोटोशूट किए... बेशक ये सब एक विज्ञापन है... लेकिन फिर भी यह बड़ी बात है!!

डायरेक्टर बोले- माहौल बिगाड़ रहे- उन्होंने आगे कहा, क्रू और दोस्त निर्देशक मुझसे मजाक में कहते हैं- आप तो काम करने का तरीका ही बिगाड़ रहे हैं... उन्होंने कहा- अगर आप एक दिन का पूरा काम सिर्फ आधे दिन में खत्म कर देंगे, तो क्लाइंट और ज्यादा विज्ञापन बनाने को देगा और इससे बाकी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक नया नियम बन जाएगा कि सबको जल्दी काम करना होगा। मुझे तो यह बहुत अच्छा लगा।

1983 की ब्लॉकबस्टर, राजेश खन्ना ने निभाया ऐसा किरदार, मां-बाप का उठ गया औलाद से विश्वास

हिंदी सिनेमा में कुछ कहानियां ऐसी हैं जिन्हें देखने के बाद दर्शकों के दिल दिमाग पर गहरा असर पड़ा। ऐसी ही एक कहानी है राजेश खन्ना की फिल्म की। फिल्म सुपरहिट थी और कहानी उससे भी ज्यादा हिट। काका की एक्टिंग हो या पूरी टीम का काम, सबकुछ इतना शानदार था कि लोग इसे एक हकीकत भरी कहानी मानने लग गए थे।

ये फिल्म है अवतार... फिल्म अवतार में राजेश खन्ना ने लीड रोल प्ले किया था। ऐसी कहानी, जिसमें मां-बाप के साथ अपनी ही जन्म दी औलाद दर्दनाक हाल करती है। 42 साल पहले आई फिल्म को देखकर लोगों ने अपनी वसीयत बदल दी थी। लोगों के दिल दिमाग में ये कहानी घर कर गई थी।

अवतार के बारे में... अवतार साल 1983 में रिलीज हुई थी जिसमें राजेश खन्ना की पत्नी के रोल में शबाना आजमी थीं। फिल्म का डायरेक्शन मोहन कुमार ने किया था। फिल्म की कहानी ये है कि बुढ़ापे में अपने ही बच्चे मां-बाप के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। बच्चे अपने मां-बाप को साथ नहीं रखना चाहते। चाहिए तो सिर्फ काम करने वाला नौकर। ऐसे में अवतार किशन (राजेश खन्ना) पत्नी राधा (शबाना आजमी) को लेकर दूर हो जाते हैं और अपनी मेहनत से दोबारा से अपनी पहचान बनाते हैं। ऐसे में पूरी फिल्म में बदलते रिश्तों की कहानी को बहुत ही भावनात्मक तरीके से दिखाया गया है।

भ्रष्टाचार सर्वोत्तम व्यवहार अस्ति...

जब कोई आम नागरिक सरकारी कार्यालय के चक्कर काटते-काटते थक जाता है, तब उसे एक मार्गदर्शक तारे की तरह भ्रष्टाचार की रोशनी दिखाई देती है। बिना चाय-पानी के भुगतान के फाइलें धूल फांकती रहती हैं, पर जैसे ही जेब गर्म होती है, फाइलें पंख लगाकर उड़ती हैं और मंजिल तक पहुंच जाती हैं। सोचिए, अगर भ्रष्टाचार न होता, तो एक वृद्ध व्यक्ति पेंशन के लिए चार साल सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता और अंत में दम तोड़ देता, पर भ्रष्टाचार की कृपा से अब वह केवल चार हजार रुपए खर्च कर उसी सप्ताह पेंशन प्राप्त कर लेता है। यह समय की बचत है, जीवन की बचत है और कहने की आवश्यकता नहीं कि यह व्यवस्था की गतिशीलता का प्रतीक है। स्कूल में दाखिले से लेकर अस्पताल में इलाज तक, हर जगह भ्रष्टाचार की अनौपचारिक सेवा जनता को अत्यंत लाभ पहुंचा रही है। जो गरीब नागरिक पहले हफ्तों सरकारी राशन के लिए लाइन में लगता था, वह अब थोड़ा दे-दिलाकर अगले ही दिन अनाज का थैला लेकर मुस्कुराते हुए घर लौटता है। और ऊपर से ये सेवा बिना किसी जीएसटी या टैक्स के है-कितनी उदार व्यवस्था है ये। अतः यह स्पष्ट है कि जनता के जीवन को सरल, सुगम और संगीतमय बनाने में भ्रष्टाचार से बढ़कर कोई उपाय नहीं-भ्रष्टाचार सर्वोत्तम व्यवहार अस्ति।

पैसे देने वालों को लाभः अगर कोई सोचता है कि रिश्वत देना महज पैसे की बर्बादी है, तो वह आज के यथार्थ से अंजान है। पैसे देने वाला हर बार अपना काम नो सवाल, नो अटकाव के सिद्धांत पर करवा लेता है। सरकारी बाबू को पैसा देकर यदि पासपोर्ट जल्दी बन जाए, बिजली कनेक्शन बिना सत्यापन के लग जाए, या पुलिस रिपोर्ट आपके मन-मुताबिक तैयार हो जाए-तो इसमें घाटा कहां है? दरअसल, पैसा देने वाला अपना सामाजिक निवेश कर रहा होता है और यह निवेश इतना लाभकारी है कि शेयर बाजार भी शर्मा जाए। एक छात्र जिसने परीक्षा में पास नहीं किया, वह थोड़े प्रयास और मोटे नोटों के दम पर न सिर्फ पास हो जाता है, बल्कि अच्छे अंकों से होता है-यह प्रगति नहीं तो और क्या है? भ्रष्टाचार ने पैसे देने वालों को वह अधिकार दिया है जो पहले केवल योग्यता वालों के पास होता था-अब योग्यता की जगह मौद्रिक विनम्रता ने ले ली है। ये नया लोकतांत्रिक सिद्धांत है जिसमें हर किसी को बराबर मौका मिलता है, बशर्ते वह जेब गर्म रखे। इस प्रकार, पैसे देकर काम करवाने की व्यवस्था में फायदा ही फायदा है-भ्रष्टाचार सर्वोत्तम व्यवहार अस्ति।

पैसा लेने वालों को लाभः भ्रष्टाचार की असली लॉटरी तो उस महान आत्मा के हाथ लगती है जो पैसे लेता है। सरकारी बाबू से लेकर ऊंचे पद के अधिकारी तक, यदि कोई सचमुच अपने परिवार का भविष्य उज्ज्वल बनाना चाहता है तो उसकी पहली पाठशाला भ्रष्टाचार ही होनी चाहिए। सैलरी तो सिर्फ जीने के लिए होती है, लेकिन रिश्वत जीवन को लाइफस्टाइल में बदल देती है। बच्चों की इंग्लिश मीडियम स्कूल, विदेश यात्रा, पांच मंजिला बंगला और बीएमडब्ल्यू, ये सब सर्विस रूल्स से नहीं, सेवा भाव से आते हैं, जहां सेवा का मूल्य नकद में चुकाया जाता है। और सोचिए, इससे सरकार का भी फायदा है-अफसर खुश तो व्यवस्था खुश और व्यवस्था खुश तो देश खुश। ऊपर से यह सब नॉन-ऑफिशियल होता है, जिससे टैक्स की कोई झंझट नहीं। इससे अफसर अपने कर्मचारियों को अनौपचारिक बोनस भी देते हैं, जिससे पूरी व्यवस्था में प्रोत्साहन और भाईचारे की भावना पनपती है। हर महीने सैलरी के अलावा यदि पांच जगहों से सहयोग राशि मिल जाए तो नौकरी में नई ऊर्जा और प्रेरणा आती है-भ्रष्टाचार सर्वोत्तम व्यवहार अस्ति।

ठेकेदारों को लाभः जब कोई ठेकेदार सरकारी दफ्तर में प्रवेश करता है, उसके पास दो फाइलें होती हैं-एक में उसका प्रस्ताव और दूसरी में प्रस्ताव की प्रेरणा। यह प्रेरणा ही है जो फाइल को सरकाती है, मंजूरी लाती है और कार्यादेश का वरदान प्रदान करती है। और सच पूछिए तो यही प्रेरणा पूरे निर्माण उद्योग को जीवन देती है। यदि सड़क, पुल, भवन, जल योजना, विद्युत ग्रिड जैसी विशाल परियोजनाओं के पीछे अगर कोई अदृश्य शक्ति है, तो वह भ्रष्टाचार ही है। ठेकेदार को लाभ मिलता है क्योंकि वह जानता है कि यदि वह इंजीनियर, निरीक्षक और आपूर्ति अधिकारी को उनकी सहभागिता राशि देगा, तो कार्य बिना अवरोध संपन्न होगा। इसका सीधा लाभ यह होता है कि समय पर भुगतान भी हो जाता है और गुणवत्ता के नाम पर सस्ता माल चल जाता है। और इसी पैसे से वह अगला टेंडर भी सुनिश्चित करता है। यही कारण है कि देश की सड़कें पहली बारिश में बह जाती हैं-यह किसी त्रुटि का परिणाम नहीं, बल्कि एक सुगठित वित्तीय व्यवस्था का प्रमाण है, जो हर बार निर्माण, मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए पैसे जारी करवा देती है। और इसमें हर कोई संतुष्ट-ठेकेदार को पैसा, अधिकारी को हिस्सा और जनता को सड़क। तो जब ठेकेदार कम लागत में ज्यादा लाभ कमाए, बिना झंझट ठेका ले, बिना गुणवत्ता की चिंता किए भुगतान पा जाए, तो इसे भ्रष्टाचार नहीं-स्मार्ट ठेका प्रबंधन कहना उचित होगा। और जब सभी संबंधित पक्ष प्रसन्नचित्त हों, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भ्रष्टाचार सर्वोत्तम व्यवहार अस्ति।

आपूर्ति करने वाली कंपनियों को लाभः सरकारी आपूर्ति में हिस्सा लेना, कोई मामूली कार्य नहीं-यह साहस, समझदारी और नेटवर्किंग की मांग करता है। लेकिन यदि सप्लायर समझदार हो और उसे पता हो कि किस अधिकारी को कौन सी चीज प्रिय है, तो वह बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के भी सीधे ऑर्डर पा सकता है। आप कल्पना करें, एक स्टेशनरी सप्लायर, जो 20 रुपए की पेन को 200 रुपए में आपूर्ति करता है और फिर उसी रकम का 50 प्रतिशत अधिकारी को प्रसन्नता शुल्क के रूप में लौटाता है। ऐसा नहीं है कि यह छल है, बल्कि यह गोपनीय व्यापार सहयोग है। इससे विभाग को फाइलें लिखने की सुविधा, सप्लायर को अधिक लाभ और अधिकारी को मनचाहा उपहार-सभी का हित एक साथ।

बड़ी कंपनियां भी इसे अपनाती हैं: सरकारी अस्पतालों में दवा की आपूर्ति हो, स्कूलों में मिड-डे मील हो, या जल निगम में पाइप की डिलिवरी, सभी कुछ सहयोग शुल्क आधारित होता है। इससे कंपनियों को निरंतर सरकारी ऑर्डर मिलते हैं और उन्हें बाजार की प्रतिस्पर्धा की चिंता नहीं रहती। सप्लाई चेन में यदि भ्रष्टाचार न हो, तो वह चेन टूट जाती है, यह आधुनिक आपूर्ति व्यवस्था की आधारशिला है। अगर आप चाहें कि समय पर डिलिवरी हो, भुगतान ना अटके और अगली बार का टेंडर भी पक्का हो, तो रिश्वत ही वह चाबी है जो इन सब दरवाजों को खोलती है। अतः जब कंपनियां तरक्की करें, अधिकारी लाभ लें और जनता तक सामान पहुंचे, तब यह सिद्ध होता है कि भ्रष्टाचार सर्वोत्तम व्यवहार अस्ति।

● **डॉ. शैलेश शुक्ला**

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय

सेवा सुशासन और जनकल्याण का अडिग संकल्प

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

नागरिक सुविधा और राज्य की प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए तकनीकी सुधार डिजिटलाइजेशन, ई-रिकॉर्ड के माध्यम से आम-जन के कार्यों को आसान बनाना और हितधारकों को सीधा लाभ देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

सरकार ने सुशासन और नागरिक सेवा को प्राथमिकता देकर हर वर्ग का लाभ सुनिश्चित किया है। इन अभूतपूर्व प्रयासों से मध्यप्रदेश अब उन्नति के नए युग में प्रवेश कर रहा है।

- नामांतरण, बंटवारा जैसे विभिन्न राजस्व प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण के लिए सभी 55 जिलों में साइबर तहसील परियोजना लागू। यह पहल करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य।
- संपदा 2.0 रजिस्ट्री के लिए ई-पंजीयन एवं ई-स्टाम्पिंग की नवीन प्रणाली। दस्तावेजों के ऑनलाइन निष्पादन, [illegible] वेरिफिकेशन आदि कार्य होंगे आसान।
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संभागीय समीक्षा बैठकों का आयोजन। कानून व्यवस्था के साथ बड़े पैमाने पर किए गए विकास कार्यों के भूमिपूजन एवं लोकार्पण।
- राजस्व महाअभियान के दोनों चरणों में 80 लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण।
- जिला, संभाग, तहसील आदि की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए पृथक प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग बनाने का निर्णय।
- मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री अब स्वयं भरेंगे अपना इनकम टैक्स।
- प्रदेश की अंतरराज्यीय सीमाओं पर 1 जुलाई, 2024 से परिवहन जांच चौकियों के स्थान पर रोड सेफ्टी एवं इन्फोर्समेंट चेकिंग पॉइंट की व्यवस्था शुरू।
- वॉरंट और समन की तामील के लिए ई-तकनीक का उपयोग प्रारंभ। मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है।
- प्रदेश के किसी भी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में से 50% शहीद की पत्नी और 50% माता-पिता को देने का निर्णय।
- 105 वर्ग मीटर तक के आवासीय भू-खंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर शीघ्र अनुज्ञा प्राप्त करने और 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भू-खंडों पर त्वरित अनुज्ञा प्रदान करने की व्यवस्था लागू।
- बालाघाट के [illegible] में हुई मुठभेड़ में नक्सलियों को धूल चटाने वाले 24 शासकीय पुलिस सेवकों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन।
- प्रदेश में थानों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का कार्य तेजी से जारी।
- शासकीय सेवाओं में महिलाओं को अब 35% आरक्षण।
- भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय नौकरियों में आरक्षण।